खण्ड-06 सत्र -05 (भाग-01) / अंक-48

बृहस्पतिवार 10 मार्च, 2017 / 19 फाल्गुन, 1938 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

पांचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-05 (भाग-01) में अंक 44 से अंक 48 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 भाग (1) शुक्रवार, 10 मार्च, 2017/19 फाल्गुन, 1938 (शक) अंक-48

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:10 बजे समवेत हुआ।

माननीय अधयक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची:

1 श्री शरद कुमार
2 श्री संजीव झा
3 श्री पंकज पुष्कर
4 श्री पवन कुमार शर्मा
5 श्री अजेश यादव
6 श्री महेंद्र गोयल
7 श्री वेद प्रकाश
8 श्री सुखवीर सिंह दलाल
9 श्री ऋतुराज गोविंद
10 श्री संदीप कुमार
11 श्री रधुविन्द्र शौकीन
12 श्रीमती बंदना कुमारी
13 श्री जितेंद्र सिंह तोमर
14 श्री राजेश गुप्ता
15 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
16 श्री सोमदत्त
17 सुश्री अलका लाम्बा
18 श्री आसिम अहमद खान
19 श्री विशेष रवि
20 श्री हजारी लाल चौहान
21 श्री शिव चरण गोयल
22 श्री गिरीश सोनी

23 श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
24 श्री राजेश ऋषि
25 श्री महेंद्र यादव
26 श्री नरेश बाल्यान
27 कर्नल देवेंद्र सहरावत
28 सुश्री भावना गौड़
29 श्री सुरेंद्र सिंह
30 कर्नल देवेंद्र सहरावत
31 श्री प्रवीण कुमार
32 श्री मदन लाल
33 श्री सोमनाथ भारती
34 श्रीमती प्रमिला टोकस
35 श्री नरेश यादव
36 श्री करतार सिंह तंवर
37 श्री प्रकाश
38 श्री अजय दत्त
39 श्री दिनेश मोहनिया
40 श्री सौरभ भारद्वाज
41 सरदार अवतार सिंह कालकाजी
42 श्री सही राम
43 श्री नारायण दत्त शर्मा
44 श्री अमानतुल्लाह खान
45 श्री राजू धिांगान
46 श्री मनोज कुमार
47 श्री नितिन त्यागी
48 श्री एस. के. बग्गा
49 श्री अनिल कुमार बाजपेयी
50 श्री राजेंद्र पाल गौतम
51 श्रीमती सरिता सिंह
52 मो. इशराक
53 श्री श्रीदत्त शर्मा
54 श्री आदर्श शास्त्री
55 श्री कैलाश गहलोत
56 चौ. फतेह सिंह
57 श्री जगदीश प्रधाान
57 श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की 89/89

कार्यवाही

सत्र-05 शुक्रवार, 10 मार्च, 2017/19 फाल्गुन 1938 (शक) अंक-48

सदन अपराह्न 2.10 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

विशेष उल्लेख (नियम-280)

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है। 280 में श्री सोमनाथ भारती जी। अनुपस्थित। श्री विजेंद्र गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं सरकार का धयान दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में बसों की संख्या में भारी कमी है और सरकार ने ये घोषणा भी की थी कि 10 हजार बसें डीटीसी के बेड़े में जोड़ी जाएंगी। क्लस्टर बसेज को लेकर भी सरकार की योजनाएं थी। जब 2015 में सरकार बनी, तो उस समय 1380 लो फ्लोर बसेज खरीदने का प्रोसेस शुरू हो गया था। लेकिन वो प्रोसेस रोक दिया गया। उसके क्या कारण है, ये सरकार बेहत्तर बता सकती है। पिछले छः वर्षो से लगातार डीटीसी में चलने वाली बसों की संख्या में कमी हो रही है। 2011 में 6204 बसेज थी और अब घटकर, मेरी जानकारी के अनुसार, लगभग 4 हजार बसें डीटीसी के पास, सही रूप में जो लोगों को लाने ले जाने का काम कर रही हैं। इस भारी दिक्कत के कारण लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता

है और जो एक कहा जाता है कि एक क्लेटिक्व पूलिंग, जिसको कहा जाता है कि हमको डिस्करेज करना है; इन्डिविज्युएल व्हीकल्स को, टू व्हीलर्स को, कारों को, तो इस लिए बसों की व्यवस्था को सुधार किया जाएगा। लेकिन ऐसा सुधार प्रतीत नहीं हो रहा है। सरकार ने एक बात और कही थी और वो था युनिफाईड ट्रांसपोर्ट अथोरिटी का गठन करना। ये विषय पहले भी मैं कई बार उठा चुका हूं। यूनिफाईड ट्रांसपोर्ट अथोरिटी जब तक स्थापित नहीं की जाएगी, तब तक इस बात का निचोड़ नहीं आएगा, लास्ट माइल्स कनेक्टिविटी का तब तक दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं होती हैं और अगर हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो यह जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंग्थन किया जाए जिससे कि हर स्थान से उसको ट्रांसपोर्ट मिल सके। मैट्रों का जो नेटवर्क है, उसके कारणव हम कह सकते हैं कि लोग किसी न किसी रूप में गुजारा कर रहे हैं लेकिन मैट्रो के अलावा, अगर मैट्रो को इस ट्रांसपोर्ट के सिस्टम से, एक समय के लिए इसका इनालिसिस करने के लिए इसको अलग कर दें, जहां मैट्रो की कनैक्टिविटी नहीं है, तो मैं समझता हूं कि आज दिल्ली में 70 प्रतिशत क्षेत्र ऐसे हैं, जहां से ट्रैवल करना आसान काम नहीं है। इसके लिए प्राईवेट लोगों को व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, हॉयर करनी पड़ती है। कई-कई गुणा पैसा खर्च करना पड़ता है और वो दूर-दराज के गरीब इलाकों में जो मजदूरन हैं, जो कामगार हैं, जो अपने काम के लिए आते हैं, उनको प्रतिदिन कई गुणा अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, समय व्यर्थ होता है।

तो एक बार उसको लेकर के अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि आपके माध यम से सरकार कोई एक रिपोर्ट जारी करे, एक सर्वे रिपोर्ट जारी करे। एक कम्पलीट एक प्रकार का डाक्यूमेंट बनाया जाए और एक मास्टर प्लान पब्लिक

ट्रांसपोर्ट का, वो दिल्ली की बनाई जाए। दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को धयान में रखते हुए मास्टर प्लान फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनेगा, तो हम दूरगामी तरीके से चीजों के बारे में फैसले ले सकेंगे। धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमदत्त जी।

श्री सोमदत्त : धान्यवाद, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपके माध यम से मैं माननीय मंत्री जी का धयान मेरे क्षेत्र में चल रहे राशन माफिया की तरफ दिलाना चाहता हूं। कई सारी राशन की दुकानें ऐसी हैं, जो खुलती ही नहीं हैं। महीने में 15-15 दिन बंद रहती हैं। जो राशन कार्ड होल्डर हैं, वो वहां पर जाते हैं। उनको पूरा राशन नहीं दिया जाता है और तरह-तरह से उनके साथ मिसविहेव कियाजाता है। लगातार ऐसी शिकायतें बार-बार आ रही हैं और मैंने खुद गुलाबी बाग में राशन दफ्तर में जाकर एफएसओ को इस बारे में बताया और एक दुकान जो लगभग 15-16 दिन से नहीं खुली थी, एफएसआई के साथ जाकर उस दुकान पर वहां पह ुंचे हम लोग, तो वो दुकान उस दिन भी बंद थी। अड़ोस-पड़ोस में लोगों से पता किया, बोले, ''ये दुकान 10-10, 15-15 दिन बंद ही रहती हैं।'' बहुत ज्यादा शिकायतें थी उस दुकान की। वो दुकान लॉक पाई गई। वहां पर, उस ओनर से भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की गई, उसने फोन नहीं उठाया। उसकी दुकान को सील किया गया। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि दूसरे ही दिन, बिना किसी सूचना के उस दुकान की सील खोल दी गई। उस राशन दुकान के ऊपर कोई काग्रवाई नहीं की गई। इतनी ज्यादा कम्पलेंटस हैं। और तो और उस ईमानदार अधिाकारी का ट्रांसफर कर दिया गया वहां से। तो मुझे लगता है ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उस माफिया पर लगाम लगाने की, उनका ट्रांसफर किया गया ये बड़े खेद की बात है।

इस विषय में कमिश्नर साहब से भी मिला, फूड एंड सप्लाई के कि जी, ये बिल्कुल उल्टा कर दिया आपने। बजाय उस दुकान दार को पैनल करने के, उसके खिलाफ इन्कवायरी करने के, आपने उस राशन कार्ड इंसपैक्टर का ट्रांसफर कर दिया। ऐसा क्यूं? बोले जी, ''कम्पलेंटस हैं।'' मैंने कहा, ''कन्जूमर की कम्पलेट नहीं है, राशन दुकानदार की कम्पलेंट है। जो राशन नहीं दे रहा लोगों को।'' तो ये बिल्कुल गलत बात है। जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ तो हो नहीं रही और उस ईमानदार अधिकारी का ट्रांसफर किया जा रहा है, जो लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा है, उनका हक दिलाने की कोशिश कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माधयम से मेरी माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ईमानदार अधिकारियों को संरक्षण दिया जाए ताकि वो और ज्यादा पब्लिक के हित में काम कर सकें और ऐसे माफिया के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि पब्लिक में बहुत अच्छा मैसेज जा सके। धान्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सरिता सिंह जी। (2.20)

श्रीमती सरिता सिंह : धान्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं आपका धयान अपने क्षेत्र में एमसीडी द्वारा साफ सफाई में जो लापरवाही बरती जाती है, उसकी ओर दिलाना चाहती हूं। दो तीन एरिया हैं मेरी विधान सभा में, एक तो बिल्कुल आपके विधान सभा क्षेत्र से ही सटा हुआ है। पीछे रेलवे कालोनी जो है, वहीं से एमसीडी का एक नाला जाता है, जिसमें पीडब्ल्यूडी द्वारा मरम्मत, आपके आदेश से तो हुआ था पर एमसीडी के नाले की सालों से सफाई नहीं हुई है और ये शायद कम्पलेंट आपके पास भी आता होगा और डीसी से, कमिश्नर

से लगातार बात करने के बावजूद भी उस नाले की कोई सफाई नहीं हो रही है औरवहां पर जो कालोनी है, जो झुग्गियां हैं, वो पूरी तरह से आज के डेट पर, इस टाइम पर भी पूरी भरी हुई है, केवल नाले के पानी से। यही सेम व्यवस्था है मोती राम रोड में, राम नगर से जब हम आगे बढ़ते हैं और मोती राम रोड पर जब हम आते हैं, आधाी रोड वो पीडब्ल्यूडी की है, आध ाी रोड एमसीडी की है तो जब पीडब्ल्यूडी का खत्म हो के जब एमसीडी का खत्ता है, उसके आगे से जब वो रोड शुरू होता है, लगभग 20 से 2 5 साल से उसकी सफाई कभी नहीं हुई। उस नाले को पूरा पाट दिया गया है और उसकी सफाई बिल्कुल भी नहीं होती। जिस वजह से घरों के अंदर बिल्कुल पानी घुस गया है। लोगों के घरों की जो नींव है, वो खराब हो रही है। तो ये एक एमसीडी की बहुत बड़ी समस्या है और लगातार जेई, एई, एक्सईएन यानि कमिश्नर तक के लोगों से भी बात ाहे रही है, लिखित में उनसे बात हो रही है, फोन पे उनसे बात हो रही है, उनको बुलाया जा रहा है पर उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई, साफ सफाई की नहीं जा रही है। इससे क्षेत्र के लोगों को बहुत समस्या आ रही है। तो इसको प्लीज आप अपने माधयम से सॉल्व कराने की कोशिश करें।

धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सुश्री अलका लांबा जी।

सुश्री अलका लांबा : धान्यवाद, अध्यक्ष जी कि नियम 280 के तहत आपने मुझे मेरी विधान सभा की समस्या रखने को कहा।

अध्यक्ष जी, समस्या नई नहीं है, समस्या वो ही है जो दो दिन पहले भी आपने खुद अपना अनुभव बताया, ट्रैफिक की समस्या को लेकर। अध्यक्ष

जी, मेरे यहां, पुरानी दिल्ली की समस्या, इसलिए पूरी दिल्ली से भी ज्यादा अधिाक गंभीर हो जाती है क्योंकि मेरे यहां पर अन्तर्राज्जीय बस अड्डा, टर्मिनल पड़ता है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है और आप देखेंगे कि बहुत लोग अपनी ट्रेन सिर्फ एक जाम की वजह से नहीं पकड़ पाते हैं। ये इतना गंभीर मामला, शायद न हो अध्यक्ष जी, लेकिन पुरानी दिल्ली के अंदर सेंट स्टीफन हॉस्पिटल, आपका ट्रॉमा सेंटर, अरूणा आसफ अली हॉस्पिटल, कस्तूरबा गांधाी अस्पताल, जीबी पंत हॉस्पिटल, लेडी इर्विन हॉस्पिटल, एलएन जेपी अस्पताल; ये अस्पताल, मुझे लगता है कि ज्यादा गंभीर मामला इसलिए पड़ता है ट्रैफिक जाम की वजह से बहुत बार मरीज सिर्फ इसलिए समय पर अस्पताल पहुंच के इलाज नहीं पा पाते, क्योंक वो ट्रैफिक जाम में घंटों फंसे रहते हैं।

अध्यक्ष जी, इस ट्रैफिक जाम के कारण भी, बहुत स्पष्ट है ऐसा नहीं है कि इसका समाधान नहीं दिया जा सकता, इसके समाधान दिए जा सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो हैं, वो बताते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की कमी हैं इन कर्मियों की, जो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की जो कमी है, इसे पूरा करना किसे है और क्यों नहीं ट्रैफिक पुलिस इन कर्मियों की भर्ती करके इस कमी को पूरा कर पा रहा?

दूसरा, जो मुझे बताया गया कि यहां पर क्रेन जो है, वो है नहीं और जो क्रेन है, वो पुरानी दिल्ली की वो जो सड़के हैं, वहां पर भेजकर गाड़ी उठाकर लाना वो भी उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। वे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मजबूरियां बताई जा रही हैं। मैं आपको अध्यक्ष जी, बताती हूं गंभीर प्वाईंट कि जामा मस्जिद गेट नं. 1 पर अवैधण तरीके से ऑटो रिक्शास्टैंड बना दिया गया है और जिस वजह से कस्तूरबा गांधाी अस्पताल

में गर्भवती महिलाएं भी नहीं पहुंच पाती हैं। अगर आंकड़ा भी पूछेंगे, आपको साफ आंकड़ा मिल जाएगा कि जामा मस्जिद 1 नं. गेट में जो जाम लगता है और उसकी वजह से जो, रिक्शों पे म हिलाएं आती हैं, कस्तूरबा गांधी अस्पताल में वो न पहुंच पाने से कितने हादसे जो हैं, वो रास्ते में ही हो चुके हैं।

अध्यक्ष जी, दरियागंज लाल बत्ती, जो रेड लाइट है, बहुत बार कम्पलेंट की। आप हैरान होंगे कि दरियागंज लाल बत्ती, कम्पलेंट करने के बाद भी, आज एक हफ्ते से ऊपर हा गया है, वो लाइट जल नहीं रही है जिससे जो दरियागंज का मैन चौराहा है, वो पूरा जाम रहता है और उसके जाम का असर पूरी पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक मैन मार्किट से लेकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आज देखे जा सकते हैं। पटौदी हाउस के आरडब्ल्यूए मुझे लिख-लिखकर दे चुकी हैं। सर, पटौदी हाउस के अंदर पूरे इलाके में अवैधा पार्किंग की वजह से वहां से छोटी संकीर्ण गलियों में रिक्शों की आपकी तीन-तीन किलोमीटर तक लम्बी लाइनें मिल जाएंगी।

अध्यक्ष जी, मेरा हाथ जोडद्य के यही निवेदन है, समस्या साफ है, उसका समाधान भी ट्रैफिक पुलिस को पता है, मैं उम्मीद करती हूं कि एक दरियागंज गोलचा सिनेमा, डाकघर के सामने जो मैट्रो का काम चल रहा था, अध्यक्ष जी, यूटर्न बना दिया गया था जिससे लोगों को बहुत राहत मिली हुई थी। अभी मेरे बहुत निवेदन के बाद भी उस यूटर्न को मैट्रो को काम खत्म होने के बाद बंद कर दिया गया। मेरी ट्रैफिक पुलिस से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दो यूटर्न, जो मैंने निवेदन किए हैं; एक दरियागंज डाकखाने के सामने जो यूटर्न बनाया गया था, उसे बंद कर दिया गया है, उसे खोल दिया जाए।

दूसरा, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के बिल्कुल एंट्री गेट पर जो यूटर्न, मेरे निवेदन के बाद जो है बनाय गया था लेकिन उसे दुरूस्त रूप से चलाया नहीं जा रहा। उस पर कोई लाइट नहीं लगाई गई, सिर्फ उसके कुछ पतथर हटा दिए गए हैं, जिससे वो और ज्यादा जो है, आपकी तीस हजारी जो हमारा कोर्ट है, उसके सामने जाम करते हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद पुल मिठाई आप देखेंगे। पूरे ये इलाके हैं पुरानी दिल्ली के है, पुरानी दिल्ली के लोग बिल्कुल जाम की वजह से घंटों फंसे होने से परेशान हो रहे हैं। आपसे निवेदन है इसे गंभीरता से लिया जाए। धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धान्यवाद। विजेंद्र गर्ग जी।

श्री विजेंद्र गर्ग : अध्यक्ष महोदय, धान्यवाद कि आपने मुझे विशेष उल्लेख के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माधयम से माननी मंत्री जी का धयान दिल्लीवासियों की उस मांग की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो बिजली के बिलों से संबंधित है। दिल्ली में बिजली के बिलों को जाम करने के लिए कैश लिमिट चार हजार रूपये निर्धारित की गई है अर्थात् यदि बिजली के बिल की राशि 4 हजार रूपये से अधिाक होती है तो उस बिल का भुगतान नगद धान राशि में नहीं किया जा सकता और उसका भुगतान चैक आदि कैशलेस साधानों द्वारा ही किया जाना अनिवार्य हैं

अध्यक्ष जी, चार हजार रूपये से अधिाक के बिजली बिलों को कैश रकम में जमा कराने की तय सीमा के कारण बहुत से बिजली उपभोक्ताओं को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके बिजली क बिल चार हजार

रूपये से अधिाक की राशि के ही आते हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनके या तो बैंक में खाते ही नहीं हैं और अगर खाते हैं तो उनमें चैक बुकी की सुविधा नहीं होती है।

अत: अध्यक्ष जी, आपके माधयम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध ा है कि इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए, बिजली कंपनियों या डीईआरसी को निर्देश जारी करके बिजली बिलों के कैश में जमा करने की सीमा चार हजार से बढ़ाकर 10 हजार की जानी चाहिए। धान्यवाद, जयहिंद। (2.30)

अध्यक्ष महोदय : श्री आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, धान्यवाद कि आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का मौका दिया।

यह बात जो है मेरी विधान सभा द्वारका से निकल कर आती है, जो कि पूर्वांचल बहुत क्षेत्र है और भोजपुरी भाषा जो पूर्वांचलियों की अपनी भाषा है, उसको लेकर संबंधित है तो मैं इसलिए इस बात को यहां सदन में आपके माधयम से रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, संविधान की आठवीं सूची में 22 भाषाएं हैं, जो अधिाकृत हैं, जिसमें से हिंदी है और उसके अलावा 21 अनेक भाषाएं हैं। हिंदी के अलावा जो 21 भाषाएं हैं, उनका बोलना विश्व में, देश भर में हिंदी के मुकाबले कम है मगर भोजपुरी से बहुत ज्यादा कम है। भोजपुरी विश्व भर में लगभग 20 करोड़ लोग बोलते हैं और हिंदी के बाद देश के अंदर यह दूसरे नंबर पर भाषा आती है। मगर यह कॉन्स्टिट्यूशन के आठवें शेड्यूल में नहीं है, इसको इन्क्लूड नहीं किया गया है। यहां तक कि भोजपुरी भाषा को नेपाल और

मॉरिशस ने भी संवैधानिक मान्यता दे रखी है मगर हम लोगों के देश में संविधान में इसको मान्यता नहीं प्राप्त है। अभी बिहार की विधान सभा में पंद्रह दिन पहले एक रिजोल्यूशन पास हुआ। बिहार सरकार ने भी उसको पास किया और उन्होंने यह निवेदन किया भारत सरकार से कि भोजपुरी भाषा को संवैध ानिक मान्यता दी जाये और संविधान की आठवीं सूची में इसको जोड़ा जाये क्योंकि लगभग 20 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं और संविधान की 22 भाषाओं में हिंदी के बाद इसका दूसरा नंबर आता है मगर इसको संविध ान में नहीं जोड़ा गया है।

मेरा आपके माधयम से आग्रह है कि यह सदन और दिल्ली सरकार एक रेजल्यूशन पास करे, भारत सरकार को यह निवेदन कि कॉन्स्टिट्यूशन की आठवीं सूची में भोजपुरी भाषा को मान्यता दी जाये। साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार की जितनी अकादमी हैं; पंजाबी अकादमी है, संस्कृत अकादमी है, उर्दू अकादमी है, इन सारी अकादमियों की भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, मैथिली और भोजपुरी अकादमी भी उनमें से एक है और भोजपुरी अकेली भाषा है, जिसको मान्यता नहीं प्राप्त है।

आपके माधयम से अनुरोधा करूंगा कि सदन इस चीज को नजर में लाये और रेजल्यूशन पास करके भारत सरकार को इस बात को रखें। बहुत-बहुत धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : गिरीश सोनी जी।

श्री गिरीश सोनी : अध्यक्ष जी, धान्यवाद। आपने मुझे 20 के तहत अपनी विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं को रखने का मौका दिया है।

अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा में एक नजफगढ़ ड्रेन जो नाला है, कम से कम डेढ़ से दो किलोमीटर वो नाला आता है। नाले पर आधाी विधानसभा रघुबीर नगर उस साइड चला जाता है और बाकी विधानसभा इधार मादीपुर और पंजाबी बाग क्षेत्र है। रोड़ नं. 77 से शिवाजी एंकलेव के बीच में फ्लड विभाग ने एक पुल बनाया था उस पर। जो पुल बनाया है, वह पुल कंप्लीट पुल तो बन गया लेकिन काफी समय से वो चालू नहीं हो पाया। कारण ये था कि आर. ब्लाक, रघुबीर नगर में कुछ झुग्गियां थी, उनमें से होकर के रास्ता निकलना था तो उसको कंप्लीट नहीं किया गया। टेम्परेरी रूप में यू टर्न लेकर के एक छोटा-सा रास्ता बना दिया गया जिसकी वजह से वहां कंप्लीट नहीं हो पाया। वो जाकर पीडब्ल्यूडी रोड में मिलना था, वो नहीं मिल पाया। अब उसे एक टेम्परेरी रूप देकर बना तो दिया गया लेकिन उससे हुआ क्या? हुआ ये कि शिवाजी एंकलेव के साइड में जो रोड है जिस पर उसको मिलाया गया, वहां ट्रैफिक जाम होता रहता है क्योंकि एक गाड़ी जाती है फिर दूसरी वेट करती है और उस पुल की वैसे ही बहुत ज्यादा आवयकता थी। जब लोगों को पता लगा, उस पुल से आने-जाने वालों को काफी राहत महसूस तो होती है लेकिन इतना ट्रैफिक जाम होता है और उस पुल को मतलब जो है इतना सीधा था, यू-टर्न लेके उसको बनाया गया है, यू-टर्न लेके जो बनाया है, वो टेम्परेरी है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से मैं उसे देख रहा हूं, जिस तरह से हमारी सरकार का प्रस्ताव है, जितनी झुग्गियां है, डूसिब उनको मकान देंगे। जिस तरह से पंजाबी बाग में मैट्रो का रूका हुआ था तो वहां भी उनको फ्लैट अलाट किए गए और वहां से वो मैट्रो का काम कंप्लीट हुआ। तो इसी प्रकार अगर उन आर. ब्लाक की कुछ चंद 20-25 जो झुग्गियां उसके आड़े आ रही हैं, अगर उनको प्रॉयरिटी पर मकान दे दिए जाएं क्योंकि 30-49-50

झुग्गियों से ज्यादा मैं नहीं समझता, वहां होंगी और उनको मकान हमारी सरकार, डूसिब डिपार्टमेंट उनको अलाट करे तो वहां से वो पुल सीधा हो जाएगा और लगभग मैं समझता हूं कि वहां से जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, वो भी खत्म हो जाएगी और दोनों हमारी विधानसभा का जो 77 नं. रोड और शिख्वाजी एंकलेव से जो पुल बनाया है, उस पुल को सुचारू रूप से चलने में काफी मदद मिलेगी और काफी लोगों की परेशानियां दूर होंगी क्योंकि उस पुल पर मैं भी अक्सर, जब मेरी विधानसभा मेमं बना है तो मुझे रोज वहां काम पड़ता है तो मैं रोज यही समस्या देखता हूं कि वहां ट्रैफिक जाम हुआ है।

तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माधयम से ये आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करने की कोशिश करें क्योंकि वहां काफी जनता परेशान है और लगभग मेरे पास 200 से 300 शिकायतें भी उसकी आ चुकी हैं कि आप इसे जल्द से जल्द ठीक कराइए। तो मैं समझता हूं इसमें तीन डिपार्टमेंट्स अलग-अलग होने के वजह से दिक्कत आ रही है; फ्लड है, जिसने ये बनाया है, दूसरा पीडब्ल्यूडी और तीसरा मैं समझता हूं एक वो डिपार्टमेंट जो डूसिब है, जो वहां से झुग्गियां हटायेगा। तो इसकी कोई मीटिंग रखकर इसका हल निकालने की कोशिश की जाए। धान्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : संदीप कुमार जी।

श्री संदीप कुमार : धान्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय मैं आपका धयान मेरी विधानसभा में एक फ्लाईओवर है एमसीडी का वो कम से कम 7-8 साल से ऐसे ही पड़ा है निर्माणाधीन और उसकी वजह से हमारी जो सुल्तानपुरी की साइड है, वहां की सारी मार्किट की दुकानें तोड़ दी गई और जब नांगलोई की तरफ का नम्बर आया तो कुछ दुकानें बची उनको दिल्ली

सरकार ने डूसिब की जमीन में कुछ जमीन भी अलाट कर दी कि जाप यहां पर दुकानें शिफ्ट कर लो और ये फ्लाईटोवर पर काम शुरू हो जाएगा। उस फ्लाईओवर की वजह से अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी दुर्घटनाएं वहां पर हो चुकी हैं। स्कूल के बच्चे जो वहां उस लाइन को पार करके जाते हैं और कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है ना तो कोई छोटा-छोटा ब्रिज बनाया हुआ है कि पार कर लें। यहां तक कि अगर किसी के घर में कोई हत्या या मृत्यु हो जाए कोई डेथ हो जाए तो वहां से ही गुजरना पड़ता है। कई लोगों के एक्सीडेंट्स भी हुए उस दौरान और माननीय मंत्री जैन साहब से भी मिला था। इन्होंने फिर आर्डर किया था तो वो एक बार डेमोलेशन होना शुरू हुआ था वहां पर उसके बाद वो फिर लोग कोर्ट में चले गए, वे स्टे ले आए। लेकिन मैं सदन से एक बात कहना चाहता हूं अगर कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया तो फिर उन लोगों की दुकानों की अलाटमेमंट कैंसिल होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली सरकार की जमीन है और वो फ्लाईओवर बनना जरूरी है और जो जमीन है, वो वैसे ही वेकेंट लैंड नहीं है। वो वेकेंट लैंड दिखाकर के उनको अलाट की गई है। वो ग्रीन लैंड है। सारी ग्रीन बैल्ट है तो वो भी कुल कानून के खिलाफ जाकर के अलाटमेंट हो रखी है, पहली बात और अगर अलाटमेंट हो गई तो फिर वो काम होना चाहिए तो मैं आदरणीय सत्येंद्र जैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार कमिश्नर साहब को बोलें कि उसमें वो काम लागे बढ़ाया जाए क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे दुकानदार लोग तो दमे की वज हसे मर गए हैं। लोों की रोजी-रोटी का वहां पर बहुत बुरा हाल हो गया है और रोज की रोज वहां पर एक्सीडेंट होते हैं। विधानसभा के लोगों का निकलना मुश्किल है, जाम लगा रहता है। मतलब सबसे मैन समस्या यही है। जब मैं चुनाव लड़ा था वो महत्वपूर्ण मुद्दा था और आज भी वो वैसे

का वैसे ही खड़ा है। बहुत सारी मीटिंग्स करी, बहुत सारी चीजें खूब गिड़गिड़ा लिए मंत्रियों-संतरियों से, सब के पास जा लिए लेकिन समस्या यूं की यूं ही बनी हुई है।

तो अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि इसमें थोड़ा आप ही इन्टरफेयर करें और इस समस्या का समाधान हो तो लोगों को राहत राहत मिलेगी ध ान्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : नरेश यादव जी। रघुविन्द्र शौकीन जी।

श्री रघुविन्द्र शौकीन : आदरणीय अध्यक्ष जी, वैसे तो संदीप जी ने जो कहा, मेरा भी 280 नियम के तहत सेम ही वो था। लेकिन मेरा इससे थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। बेसिकली क्या है ये रेलवे के ऊपर एक अंडरग्राउंड बैरेज और एक एफओबी है। लेकिन पिछले काफी सालों से ये एमसीडी ने ये रेलवे ने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया है लेकिन एमसीडी वाले न तो उसके नीचे अंडरग्राउंड ब्रिज है, उसकी कंक्रीटिंग करके उसकी साइड वाल्स बनाकर उसे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो सुल्तानपुरी रोड पर आरओबी रेल अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य एक दशक से पहले शुरू हुआ था। रेल ब्रिज के नीचे अंडरपास बना दिया गया है रेलवे की तरफ से बनाने वाला आरओबी भी बनकर तैयार है। लेकिन अंडरपास की वाल लाइनिंग और ेस कंक्रीटिंग ना होने की वजह से ये काफी साल से लंबित है और सब-वे के नीचे सड़क निर्माण कार्य न होने के कारण बरसात के मौसम में कई फीट तक यहां पानी जमा हो जाता है। जिसके कारण कई तरह की बीमारी फैलती है और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसकी दोनों तरफ की कच्ची मिट्टी उसमें गिर जाती है तो मैं आपसे अनुरोधा करना चाहूंगा

कि इस कार्य को एमसीडी जल्दी से जल्दी पूर्ण करें ताकि दोनों सुल्तानपुरी से आने-जाने के लिए नांगलोई का जो रास्ता है वो कंप्लीट हो सके धान्यवाद।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

अध्यक्ष महोदय : धान्यवाद। अब श्री सत्येंद्र जैन जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री की ओर से कार्यसूची में दर्शाये गए उनके विभाग से संबंधित दस्तावेजों की प्रति सदन सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येंद्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री की ओर से कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 02 में दर्शाये गए उनके विभाग से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं :

1. वर्ष 2015-16 हेतु विनियोजन लेखे (अंग्रेजी एवं हिंदी प्रतियां)
2. वर्ष 2015-16 हेतु वित्त लेखे (अंग्रेजी एवं हिंदी प्रतियां)
3. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की प्रतियां :

क. वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 03-31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) पर प्रतिवेदन (अंग्रेजी एवं हिंदी प्रतियां)

---

1 पुस्तकालय में संदर्भ सं0.....पर उपलब्ध।

ख. वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या 01-सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) (अंग्रेजी एवं हिंदी प्रतियां)

ग. वर्ष 216 का प्रतिवेदन संख्या 05-राजस्व और सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) (अंग्रेजी एवं हिंदी प्रतियां)

घ. वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 04- राज्य वित्त (अंग्रेजी एवं हिंदी प्रतियां)

बजट (2017-18) पर चर्चा जारी

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा 8 मार्च, 2017 को सदन में प्रस्तुत बजट 2017-18 के और आगे चर्चा होगी। श्री मदन लाल जी। (240)

श्री मदन लाल : धान्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर चर्चा करने का मौका दिया। संस्कृत में अध्यक्ष महोदय एक दोहा है। उसके बोल हैं :

येषां न विद्या, तपो न दानम्। ज्ञानम् न शीलम् न गुणों न धार्मः।

ते मृत्युलोके भूवि भार भूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरिन्त।।

इसका पहला वाक्य विद्या से संबंधित था और उसका अर्थ है कि जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, उसमें गुण है, न धार्म है वो इस धारती पर एक सुंदर मृग की तरह केवल भार है। उस शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए, उस शिक्षा के महत्व को समझते हुए इस सरकार ने, जब पहली बार बनी तो बजट को दोगुना किया था। अगले वर्ष

अपने पूरे बजट का 23 परसेंट कियाऔर इस बजट में अब 24 परसेंट किया। 48000 करोड़ के बजट में 1 1300 करोड़ रूपये केवल शिक्षा के लिए है और इस शिक्षा पर महत्व किसको दिया? जो सबसे ज्यादा जरूरी बच्चे हैं; दो साल से पांच साल तक के, उनकी शिक्षा के मद्देनजर, उनके लिए वहां प्राईमरी से नीचे के सेंटर खोलने की बात पहली बारकिसी सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों में किया है। हम जब बड़े चिंतित होते जब हमारा कोई छोटा बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद पढ़ने लगे तो सबसे पहले विचार आता है कि हम इसे कौन से स्कूल में भर्ती करेंगे। क्योंकि एमसीडी के स्कूल मात्र दिल्ली सरकार चलाती है और एमसीडी के स्कूलों की हालत हमने देखी है, जहां बच्चों को पढ़ने के लिए न कापी है, न किताब है। उनकी ड्रेस की हालत, उन बच्चों के स्टैंडर्ड, उन क्लासरूमों की हालत, उन स्कूलों की हालत देखकर, उसकी दयनीय हालत को देखकर तरस आता है। ऐसे समय में इस सरकार ने पहली बार सोचा कि जो दो साल से पांच साल तक के बच्चे प्राईमरी क्लास से पहले के बच्चे, जो और दूसरी जगह प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन में, प्राईवेट स्कूल्स में जोन को बाधय हैं, वहां मोटी-मोटी फीस ली जाती है, ये सरकार का सबसे पहला पीपल फ्रेन्डली कदम है जहां दो साल से प ांच साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने चाईल्ड सेंटर खोलने की बात कहीं है। यहां अब सरकारी स्कूलों में जो सबसे बड़ा कदम है, अब से पहले पांचवीं से, छठी से लेके आठ, नौंवी, दसवीं तक के बच्चों को जो पहली बार यहां खाने की बात की। उनका मील जो अब तक एट्थ क्लास तक दिया जार हा था, अब ये पहली बार सरकार ने ऑल गर्ल्स चाईल्ड के लिए, नौंवी और दसवीं के लिएखाने का जो मीड डे मील है, उसको प्रोविजन में लाके रखा है और साथ ही साथ बच्चों की सेहत अच्छी रहे, उसके लिए पहली बारकेला

और अंडे का प्रोविजन किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सरकार की उस नीयत को दर्शाता है कि वो स्कूल में पढ़ने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए कितने चिंतित है। मैं शिक्षा मंी जी को बधाई देता हूं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो मूलभूत क्रांति लाये हैं और उन्होंने दस अर्ली चाइल्ड सेंटर खोलने की जो बात, दिल्ली में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के थ्रू कही है, उसके साथ ही उन्होंने जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका स्तर सुधारने के लिए जो सब्सिडी, जो यूनिफार्म में सब्सिडी थी, उसको पांचवीं क्लासतक जो पांच सौ रूपये तक दिये जा रहे थे, उसको ग्यारह सौ रूपये कर दिया। जो 6 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को सात सौ रूपये तक मिल रहे थे, उसे चौदह सौ कर दिया है और जो नौवीं से बारहवीं तक के थे जिन्हें अब तक नौ सो रूपये दिये जा रहे थे, उसको पंद्रह सौ रूपया कर दिया है। जब बच्चों के तन पर अच्छे कपड़े होंगे, उनका मानसिक विकास भी उसी स्वच्छता के साथ आगे बढ़ेगा। इस बात को धयान में रखते हुए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को, फाईनेंस मिनिस्टर जी को बहुत-बहुत धान्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक नई कॉन्सेप्ट जी को बहुत-बहुत धान्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक नई कॉन्सेप्ट जो छोटे बच्चों की शिक्षा को लेकर, जो बच्चों के मन में हीन भावना पैदा होती है, उसके बारे में चिंता कर इस स्तरको सुधारने की एक चेष्टा की हैं यहां टीचर्स जो अब तक स्कूलों में या तो आते नहीं थे, नदारद रहते थे या पढ़ाते नहीं थे और एक आम शिकायत थी कि लोग अपने घर का काम करते थे, उसको सुधारने के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की के कॉन्सेप्ट की जो शुरूआत की, उसके साथ उसमें जो बचें केपैरेंट जुड़े, वो अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चूंकि बहुत ज्यादा जागरूक थे, उन्होंने टीचर्स के और प्रिंसिपल्स के साथ मिलकर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को जन्म

देना शुरू कर दिया जहां हर टीचर पहले अपने काम को समझकर केवल शिक्षा की बात करने लगा और एसएमसी के जितने भी टीचर्स के साथ जुड़ाव हुआ, उसके साथ शिक्षा का स्तर सुधारने लगा और अब पिछले दो वर्षों में जिस तरीके से जो बच्चों के एग्जामिनेशन के बाद जो रिजल्ट आयें हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। उनमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। क्योंकि पैरेंट टीचर एसोसिएशन के सहयोग से अब टीचर्स और प्रिंसिपल्स, अभी बड़े कान्शस से पढ़ाई हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ा अच्छा कदम उठाया। जो टीचर्स पहले जनगणना, कहीं और, प्रिंसिपल किसी स्कूल मैनेजमेंट में जो लिप्त थे, उनको उससे हटाने के लिए पहली बार स्कूल में मैनेजर्स, एस्टेट मैनेजर भर्ती किये और वो एस्टेट मैनेजर अब स्कूल का, शिक्षा के क्षेत्र के छोड़ के वो स्कूल से संबंधित सारे कार्य करते हैं जिससे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को अपना समय और ज्यादा बच्चों की शिक्षा में लगाने में मिल जाता है। यहां शहीद सुखदेव कालेज 2917 में शुरू होने वाला है जो बिजनस स्टडीज के लिए पहला बहुत बड़ा इन्स्टीट्यूट होगा। ये बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि जब तक आपको केवल शिक्षा नहीं चाहिए। शिक्षा के साथ व्यावहारिक शिक्षा चाहिए। वो शिक्षा जो आपके काम आती, मुझे एक छोटा सा कहानी याद आ रही है। एक बहुत बड़े पंडित जी पढ़े-लिखे, अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए नाव में बैठ गये और उस नाविक को पूछा, ''नाविक, कुछ पढ़ना-लिखना आता है?'' नाविक ने कहा, ''पंडित जी, मुझे तो नहीं आता।'' कहा, ''तेरी जिंदगी तो बेटा एक चौथाई गयी।?'' थोड़ी दूर नाव और चली। कुछ देर और चली। ''अरे! तू कहीं ज्ञानियों में बैठा होगा, कुछ ज्ञान लिया होगा।'' पंडित जी से कहा, ''मैं तो सारे दिन नाव चलाता हूं।'' कहा, ''तेरी आधाी जिंदगी गयी।'' नाव

कुछ दूर और चली। ''अरे! कहीं गांव में किसी के पास चीलम भरते, कहीं कुछ लोगों से कुछ ज्ञान हासिल किया होगा?'' कहा, ''नहीं, पंडित जी, मैं तो सुब से शाम तक नाव खेता हूं।'' ''बेटा, तेरी पहचहत्तर परसेंट गयी।'' और तभी नाव भंवर में फंस गयी और उस नाविक ने बड़े भले मन से पूछा, ''भई पंडित जी, तैरना आता है?'' पंडित जी ने कहा, ''क्यों, क्या हुआ? मुणे तो नहीं आता।'' कहा, ''पंडित जी, आपकी तो पूरी जिंदगी गयी।'' तो केवल शिक्षा, जो किताबी शिक्षा है, उससे काम नहीं चलता और वो पंडित जी डूब गये। क्योंकि उन्हें व्यावहारिक ज्ञान नहीं था। इस सरकार ने पहली बार उस व्यावहारिकता को स्कूलों में और कालेजों में लाने के लिए इंस्टीट्यूट खोलने शुरू कर दिये है। जिससे न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि उन और जरूरी ज्ञानों के बारे में जिससे जिंदगी चलती हो, क्योंकि अकेली किताब पढ़के कोई, कुछ लोग आईएएस बन सकते हैं, कुछ लोग चपरासी बन सकते हैं, कुछ क्लर्क बन सकते हैं परंतु और जो ज्ञान जरूरी है जो इस देश के विकास के लिए भी जरूरी है, जो इंजीनियरिंग का, जो किसी और चीज का जो और व्यावहारिक ज्ञान है, वो भी उतना ही जरूरी है। यहां सरकार अपने स्टूडेंटस के वेलफेयर के लिए बहुत चिंतित दिखतीं आ रही हैं। 10000 नये क्लासरूम बनाने का उन्होंने इस बजट में प्रोविजन रखा है। 156 नये प्राईमरी क्लासेज शुरू करने की, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चूंकि पैरेंटस प्राईमरी स्कूलों में केवल एमसीडी के स्कूलों में या तो जाने के लिए बाध य हैं या फिर प्राईवेट स्कूलों में जहां बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। यहां 90 टीचर्स को अब तक आक्सफोर्ड भेजा जा चुका है। 30-30 के टीचर जत्थे में तीन बार आक्सफोर्ड से ट्रेनिंग लेके आये हैं और ट्रेनिंग इस बात के लिए हमारे स्कूलों का शिक्षा का स्तर कैसे सुधारे, मैं गवर्नमेंट को, फाईनेंस मिनिस्टर को, एजूकेशन मिनिस्टर को इस बात के लिए बधाई देता है।

अध्यक्ष महोदय, मेडिसिन रिसर्च के लिए बहुत बड़ा कदम इस सरकार ने उठाया है और यहां दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च केंद्र की स्थापना करने का जो फैसला किया है, मैं सरकार को उस काम के लिए बधाई भी देता हूं और उनका धान्यवाद भी करता हूं। क्योंकि जब तक मेडिसिन में रिसर्च नहीं होगी। मैं दो दिन पहले अभी तक टीबी के सेमीनार में था। उस सेमीनार में पता चला कि टीबी जैसे रोगों से लोग अभी भी मर रहे हैं क्योंकि जो पिछली मेडिसिन थी, वो आजकल कारगर नहीं हो रही है और उनके जो जर्मस हैं, उन्होंने उनको सहना शुरू कर रखा है। जो पहले वैक्सीनेसन था, वो अब कामयाब नहीं, वो बेकार हो गया। ऐसे समय में सभी मेडिसीन का और उनकी गुणवत्ता सुधारने के लिए रिसर्च की, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जो ये सरकार इस बार सोच के ही ये रिसर्च सेंटर खोल रही है। हेल्थ सेक्टर में इस सरकार की इच्छाशक्ति को जो दिखाया है। मोहल्ला क्लीनिक जो 1000 खोलने थे, अब तक 130 खुल चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसा माननीय हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हम अगले 6 महीने में पूरे 1 000 सेंटर खोल देंगे। ये एक ऐसा कदम है, जिससे केवल लोगों की भलाई होगी। लोगों के पसा अपने इलाज करने के बाद समय बचेगा क्योंकि अभी माननीय हेल्थ मिनिस्टर ने पीछे एक वक्तव्य दिया था जसमें उन्होंने बताया था कि अगर कोई आदमी गवर्नमेंट के बड़े अस्पताल में जाता है तो खर्चा 800 रूपया आता है (2.50) क्योंकि उस बिल्डिंग का इनफ्रास्ट्रक्चर, उसके डॉक्टर्स, उसका पूरा का पूरा सिस्टम 800 रूपये एक पेंशट पर खर्च करता है परंतु मोहल्ला क्लीनिक में वो खर्च घटकर केवल 100 रूपये आता है। वो केवल पैसे की बचत नहीं होती है, उस पांच करोड़ के हॉस्पिटल के बदले में जो 20 लाख रूपये में बनने वाला मोहल्ला क्लीनिक है, उससे एक तरफ सरकार के पैसे

बचते हैं, साथ के साथ उस पेशंट को, जो अपने घर के कई मीलों दूर जाता है, उसको मोहल्ला क्लीनिक में अपना इलाज कराने की सुविधा मिलेगी, इससे उसका समय भी बचेगा और उसके पैसे बचेंगे और इकॉनोमी में 800 और 100 रूपये का फर्क आयेगा। मैं सरकार को इसके लिए बहुत धान्यवाद देता हूं। इस सरकार के सबसे बड़े कदम के रूप में जो पूरे के पूरे टेस्ट इस सरकार ने फ्री कर दिये हैं, चाहे वो पंद्रह हजार का टेस्ट हो, दस हजार का टैस्ट हो, आठ हजार का टेस्ट हो, वो पूरे के पूरे टेस्ट जिनके न करवाने की वजह से गरीब अपनी जान देता था या तड़फ-तड़फ कर मरने के लिए मजबूर होता था, अब उसके लिए इस सरकार ने सारे टेस्ट फ्री कर दिये हैं। केवल टेस्ट फ्री नहीं किए हैं, अब के बाद अगर किसी भी दिल्ली सरकार के अस्पताल में कोई मरीज जाये और वहां एक महीने से ज्यादा की वेटिंग हो तो उसको पूरा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर करवाने की स्वतंत्रता इस सरकार ने दे दी है, जिसके लिए सरकार बहुत-बहुत धान्यवाद की पात्र है।

अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 55 करोड़ रूपये का प्रोविजन जो पूरे बजट का 11 परसेंट है, करके इस सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति को बताया है। मैं माननीय विजेंद्र गुप्ता जी की बात से सहमत नहीं हूं कि आज के दिन कोई चार हजार बसें चल रही हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से डीटीसी की 5815 बसेज अभी सड़क पर मौजूद हैं और उसके अलावा इस सरकार का फैसला है कि ट्रांसपोर्ट के लिए क्लस्टर में 736 नई बसों को जोड़ा जायेगा और पब्लिक की भलाई के लिए इस सरकार ने दस हजार नए ऑटो परमिट देने का जो फैसला किया है, उससे जो ट्रांसपोर्ट की हमारी समस्या है, उसको कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, डीसीडब्ल्यू जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है जिसमें बहुत सारे लोग अब पीड़ित महिलाएं, बहन, बेटी जो जाती हैं और उनकी देखभाल के लिए, उनके मुकदमों के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनको काउंसलिंग करने के लिए जो बजट पहले सात करोड़ का बहुत थोड़ा पड़ रहा था, इस सरकार की इच्छा को दर्शाता है कि यह सरकार पीड़ित महिलाओं के प्रति कितनी जागरूक है और इसीलिए उस बजट को तीन गुना कर बीस करोड़ रूपये का बजट किया गया है, जिसके लिए मैं इस सरकार को धान्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा सोचती है। इनका धयान रहता है और एक सबसे बड़ा इन्होंने, जो वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में कहा है कि यह दिल्ली गांवों का शहर भी है। यहां 360 गांव हैं और महात्मा गांधाी ने कहा कि जो भारत की आत्मा है, वो गांवों में बसती है। उस बात को चरितार्थ करने के लिए इस सरकार ने जो पहले वाला बजट था 120 करोड़ का, उसको बढ़ाकर इस समय 600 करोड़ कर दिया। यह 600 करोड़ अगर हम देखें तो लगभग 2 करोड़ रूपया हर गांव के हिस्से में आयेगा, जिससे गांव का विकास होगा, जो अब तक वंचित है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माधयम से सदन को एक और बात धयान दिलाऊं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक कलेंडर का अनावरण किया था। उस कलेंडर का अनावरण करते हुए जो हमने उसमें देखा कि दिल्ली के जोहड़ों को, दिल्ली के जलाशयों को फिर से रिवाइव किया जायेगा, जिससे वो पुराने पानी का स्रोत फिर से जागें और दिल्ली के गांव के एरिया में एटलीस्ट पानी

की कमी दूर हों। उस बात को धयान में रखते हुए जो यह बजट में प्रोविजन किया है 600 करोड़ का, मैं उसके लिए माननीय....

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मदन लाल जी, कन्क्लूड कीजिए प्लीज।

श्री मदन लाल : मैं कर रहा हूं। सर, यहां दिल्ली में कई अकादमी है। हिंदी अकादमी है, गुजराती अभी मेरे दोस्त शास्त्री जी ने कहा, भोजपुरी को भी पूरा स्थान मिलना चाहिए। मैं इस सदन के माधयम से सरकार से निवेदन करता हूं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से निवेदन करता हूं कि दिल्ली में गुजराती अकादमी भी होनी चाहिए। यह हमारे देश का एक बहुत बड़ा राज्य है वहां की संस्कृति बहुत स्ट्रांग है। वहां की अकादमी और अकादमियों की तरह दिल्ली में भी खोली जानी चाहिए और इसके साथ ही हमारे देश में अगर देखे तो टूरिज्म का सबसे बड़ा हब या तो रा जस्थान कहलाता है या फिर आगरा कहलाता है तो राजस्थान की कला को बढ़ाने क लिए भी दिल्ली में राजस्थान की, चूंकि राजस्थानियों की यहां बहुतायत है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होने वाले फेस्टिवलस जितने भी हैं, उसमें राजस्थान का जरूर स्थान होता है चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो म्यूजिक का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई और क्षेत्र हो। इसलिए यहां गुजराती अकादमी के अलावा एक राजस्थान अकादमी भी होनी चाहिए और उससे भी ज्यादा है एक दिल्ली अकादमी भी होनी चाहिए जो दिल्ली का पुराना कल्चर हैं, जो दिल्ली के पुराने सांस्कृतिक वैल्यूज हैं, उनको मेन्टेन करें, उनको रिवाइव करे।

इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली में दिल्ली अकादमी की भी स्थापना होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मदन लाल जी हो गया। मदन लाल जी अब कन्क्लूड करें प्लीज।

श्री मदन लाल : महोदय, मैं कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक सेमिनार में हिस्सा लेने गया। जब मैंने वहां चर्चा शुरू की दिल्ली की तो वहां के जितने पंजाब और लाहौर के एमपी और एमएलएज थे, वो सारे चर्चा करने लगे कि हां, हमें पता है, दिल्ली में क्या हो रहा है। ये बातें हमने सुनी हैं। ये बातें वहां हो रही हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र की हो, चाहे सरकार के और फ्रेंडली जितने काम हैं, उनकी हो रही हो। मैं आपकी एक और बता दूं। मैं अभी-अभी....

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मदन लाल जी अब कन्क्लूड कीजिए। समय की सीमा है।

श्री मदन लाल : मुझे अभी पता चला कि पीछे अभी माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि दिल्ली में दुर्घटना में चोट खाये व्यक्ति को जो भी हॉस्पिटल पहुंचायेगा, उसको दो हजार रूपये देंगे, यह बहुत बड़ा पीपुल फ्रेंडली एक कदम है। इससे लोग घायलों की जान बचा पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब हो गया।

श्री मदन लाल : मैं धान्यवाद करता हूं मानीय हेल्थ मिनस्टर का कि आज उन्होंने 125....

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मदन लाल जी अब यह लास्ट है, इसको कन्कलूड कीजिए प्लीज।

श्री मदन लाल : जी सर। 125 नये वेंटिलेटरों का उद्घाटन किया है जो इस दिल्ली में बहुत बड़ा काम है जिससे लोगों की जान बचाने के लिए बहुत कहेंगे।

मैं अंत में, एक बात के साथ कि इस सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि 25 परसेंट का जो फ्यूल टैक्स था, उसको 24 परसेंट घटाकर एक परसेंट कर दिया। इससे जो छोटी दूरी के हैं खास कर नॉर्थ ईस्ट के जितने यहां स्टूडेंट है, उन लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। एक और जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने घोषणा की कि 60 साल के सभी लोगों को फ्री यात्रा और लेडीज को जो 60 साल से कम हैं उनको 250 रूपये में हजार की जगह और जो 20 हजार रूपये महीना कमाते हैं, उन लोगों को केवल 250 रूपये में हजार वाला पास बनाकर दिया जाएगा। यह सरकार की इस बात को दर्शाता है कि यह सरकार लोगों के भले के लिए कितना काम कर रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धान्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस. के. बग्गा जी।

श्री एस. के. बग्गा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धान्यवाद करता हूं कि आपने मुझे वार्षिक बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए मौका दिया। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी और डिप्टी सी. एम. मनीष

सिसोदिया जी को बधाई देता हूं कि एक ऐसा बजट जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया बल्कि कुछ आइटमों पर टैक्स की दर साढ़े बारह से 5 परसेंट की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को तोहफा भी दिया है 20 रूपये के मूल्य तक के सेनेटरी नेपकिन्स कर मुक्त है। म हिलाओं की स्वच्छता के प्रति सरकार के सरोकार को देखते हुए 20 रूपये से अधिाक मूल्य वाले सेनेटीर नेपकिन्स मामले में कर की मौजूदा दर साढ़े बारह से घटाकर पांच परसेंट का प्रस्ताव रखा है। लेमिनेट्स, प्लाईवुड, ब्लैक बोर्ड, एमडीएफ बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड के लिए मौजूदा साढ़े बारह की दर को भी पांच परसेंट की दर में लाने का प्रस्ताव रखा है। पिछले वर्ष मार्बल की दर घटाकर पांच परसेंट की गई थीं इस वर्ष ग्रेनाइट, स्वदेशी कोटा स्टोन, धोलपुर, स्टोन, ग्वालियर स्टोन, स्लेट पर भी मौजूदा दर साढ़े बारह प्रतिशत से कम करके पांच प्रतिशत का प्रस्ताव रखा है। नागर विमानन ऑपरेटर को प्रोत्साहित करने के लिए एयर टरबाइन ईंधान (एटीएफ) की खरीद पर वैट की दर 25 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है। यह एक ऐतिहासिक बजट है कि बिना नय कर लगाये हुए बजट का पेश किया है। यह बजट व्यापारियों के अनुकूल है। दिल्ली सरकार दिल्ली के व्यापारियों के लिए मददगार है। चालू वर्ष के दौरान में 723 करोड़ रूपये के रिफंड दिये गये। लास्ट ईयर 227 करोड़ की तुलना में 300 प्रि तशत अधिाक है। 72 हजार रिफंड के मामलों का निपटारा किया गया। इस वर्ष यह आउटकम बजट है। इसमें एकाउंटबिलिटी है। (3.00) आउटकम बजट की मॉनिटरिंग हर तिमारी की जाएगी। 37 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में करना अपने आप में दर्शाता है किसरकार आम जनता के साथ व मजदूरों के साथ है। पेंशन में हर महीने 1000 रूपये की वृद्धि की गई है, बुजुर्गों और विधावाओं को अब हर महीने 1000 रूपये

ज्यादा मि लेगा। 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए मैं बधाई देता हूं। 150 पॉलीक्लिनिक बनाने के लिए, अतिथि शिक्षकों की सेलरी 25000 से बढ़ाकर 36000 का प्रस्ताव रखा है, मैं अपनी सरकार को और माननी वित्त मंत्री को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी ऐसे ही बजट देते रहेंगे, धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री संजीव झा जी, प्रमिला टोकस।

श्रीमती प्रमिला टोकस : धान्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बजट पर चर्चा करने के लिए मौका दिया और मैं बधाई देती हूं अपने चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया जैसे एक मां अपने सभी बच्चों के लिए अगर वो कुछ बनाती है, अगर एक के लिए नहीं बनाया तो वो कहेगा कि मां मेरे से प्यार नहीं करती, आपने इसक पसंद का खाना बनाया है। तो मुझे लगता है कि मनीष जी ने उन सभी का धयान करते हुए ये बजट बनाया, बच्चे से लेकर और बूढ़ों तक सभी का धयान रखा। उन्होंने ग्रामीण हो या शहरी हो या पंजाबी हो या उर्दू हो सभी को एक साथ लेकर चले और मैं उसके लिए अपने मनीष सिसोदिया जी का चीफ मिनिस्टर का बहुत-बहुत धान्यवाद करती हूं और अभी सभी ने हर चीज पर चर्चा की, मैं थोड़ा सा पर्यावरण की तरफ भी, शिक्षा पर और बच्चों पर और स्वास्थ्य पर और सबसे जरूरी है पर्यावरण क्योंकि पर्यावरण से जीव जंतु, पशु पक्षी सब इससे प्रभावित है। सभी पर इसका बुरा असर पड़ता है। पहले हम जब शाम के समय इतने पशु पक्षी चहचहाते थे और ऐसे झुंड के झुंड देखा लिया करते थे लेकिन अब वो कहीं न कहीं खत्म हो गया है। हमारी दिल्ली में प्रदूषण इतना है जो हमारी सरकार ने आकर उस पर इतना काम किया जो पहले छह केंद्र

होते थे वायु की गुणवत्ता के लिए और आज 26 कर दिये, मैं तहे दिल से धान्यवाद करती हूं और प्रदूषण न फैले हमारी दिल्ली में जो बैटरी वाहन हैं जिनसे प्रदूषण न फैले, वो वहां चलाई जाएं और 686 ऐसे वाहनों पर 1 करोड़ 6 लाख की सब्सीडी दी जो एसे वाहन खरीदेंगे, उन पर 1 करोड़ 6 लाख की सब्सीडी दी। इसलिए मैं अपने मिनिस्टर को तहे दिल से बधाई देती हूं कि इससे हम सभी प्रभावित होते हैं।

अध्यक्ष जी हम आंध्रा गाये तो वहां पर वैकया नायडू जी ने आपने भी सुना होगा, उन्होंने वहां पर क्या बोला कि हमने गैस फ्री में दिया अब वो जो आप कहीं पर भी देखते हैं तो गैस सिलेंडर की ही चर्चा होती रहती है कि इतने दुगने गैस के सिलेंडर कर दिये वो वहां पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो महिलाओं के हित में हैं या महिलाओं के विरोधाी हैं। उन महिलाओं को उन्होंने रोजगार नहीं दिया जो उन्होंने वहां पर सिलेंडर और गैस दी जो आज इतने महंगे हो चुके हैं। वो गरीब घर के हैं। क्या वो इतने प्रयास कर सकते हैं कि वो इतना महंगा सिलेंडर भरवा सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय, हमारी एक सरकार है कि अभी तक शायद हमारे वित्त मंत्री ने जो ये काला धान, काला धान बाहर से मोदी जी लेकर आये वो शायद हमारे मिनिस्टर के पास आ गया जो आज पूरी दिल्ली में कहीं पर भी वैट नहीं लगा कहीं किसी भी चीज पर टैक्स नहीं है। शायद हमारे मंत्री जी के पास वो सारा कालाधान जो वो बाहर से लेकर आने वाले थे, उनके पास नहीं गया, हमारे वित्त मंत्री जी के पास आ गया।

अध्यक्ष जी, जिन महिलाओं और बुजुर्गों ने अपनी पेंशन से बचा-बचा कर जिन्होंने इतनी मुश्किल घड़ी क लिए जो पैसे जमा किये, नोटबंदी से जो घाव

मोदी सरकार ने दिये और जो आज उनके जो घाव थे वो हमारी दिल्ली सरकार ने उनको भरा तो मैं मनीष सिसोदिया जी का बहुत-बहुत धान्यवाद करती हूं कि आज बुजुर्ग और महिलाएं इतनी खुश है जिसे वो बयां नहीं कर सकते। जिस तरह से वो भाषा प्रयोग करती है, मैं अपने उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का बहुत-बहुत धान्यवाद करती हूं कि इतना अच्छा बजट हम दिल्ली वासियों के लिए प्रस्तुत किया, बहुत-बहुत धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बहुत बहुत धान्यवाद। राखी बिड़ला जी।

सुश्री राखी बिड़ला : धान्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का जो बजट वर्ष 2017-18 है, उस पर चर्चा करने का मुझे मौका दिया और सिर्फ धान्यवाद शब्द काफी नहीं है हमारे माननीय वित्तमंत्री जी और हमारी पूरी कैबिनेट और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं एक बार फिर कहती हूं कि इन्हें दिल से सलाम करना चाहिए क्योंकि ये गांधाी जी के राम राज्य के सपने को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने दो दिन पहले ही कहा था कि गांधाी जी का जो राम राज्य है, उनका सपना ये था कि पंक्ति मेमं खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को तमाम वो सुविधा, तमाम वो सुख, तमाम वो सम्मान मिले, जिससे वो वंचित है और आजादी से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने उस सपने को पूरा करने की कोशिश नहीं की बल्कि खाई इतनी चौड़ी, इतनी गहराती गई कि गरीब और गरीब होता गया और अमीर और अमीर होता गया लेकिन सलाम दिल्ली की जनता को भी उन्होंने आम आदमी पार्टी पर विश्वास किया ऐसे ईमानदार नेतृत्व पर विश्वास किया जिसने लगातार तीसरा ऐसा बजट पेश किया है, जिसमें न कोई टैक्स है और न कोई और और बढ़ोत्तरी, का नया कर के इसके लिए इन्हें बहुत-बहुत धान्यवाद।

अध्यक्ष जी, मुझ से पूर्व सभी वक्ताओं ने क्योंकि इस मुद्दे पर कल भीच चर्चा हुई, सब वक्ताओं ने बहुत बारीकी से बहूत गहनता के साथ वित्तमंत्री के द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने-अपने विचार रखे लेकिन अध्यक्ष जी मैं एक बात कहना चाहती हूं, मैं अपने घर में हमेशा एक बात अपनी मां से, अपने पिताजी से सुनती हूं कि हमने परमात्मा को नहीं देखा भले ही हम हिंदू ध ार्म के लोग हैं, भगवान की पूजा करते हैं लेकिन हमने भगवन कहां हैं, कहीं नहीं देखा और मैं मानती हूं कि हमारे लिए भगवान हमारे बुजुर्ग हैं और इन बुजुर्गों का सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने जो अनोखी पहल करी है, इसके लिए बहुत-बहुत तहे दिल से धान्यवाद कि उन्होंने बुजुर्गों के लिए एक कमीशन का गठन किया है क्योंकि जिस तरह से आए दिन बुजुर्गों के लिए एक कमीशन का गठन किया है क्योंकि जिस तरह से आए दिन बुजुर्गों के लिए एक कमीशन का गठन किया है क्योंकि जिस त रह से आए दिन बुजुर्गों पर अत्याचार होते हैं, आए दिन उनका मर्डर होता है, लूटपाट की घटनाएं आती हैं कई ऐसे बच्चे हैं जो उनको बाहर बिठा देते हैं, तमाम तरीके के गैर कानूनी, कानूनी दायरों में उन्हें फंसाकर उन्हें बेदखल कर देते हैं, बेघर कर देते हैं आए दिन की घटनाएं हम लोग समाचार पत्रों के माधयम से न्यूज चैनल के माधयम से देखते हैं और सिर्फ देखते ही नहीं हैं बल्कि इन पर ब्रेकिंग न्यूज भी बनती है। डीमोनीटराइजेशन हुआ और इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपनी 90 वर्षीय मां को महज 4 हजार रूपये निकालने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए लाइन में खड़ा कर देता है। मुझे लगता है, मुझे वित्तमंत्री को धान्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने प्रेरणा ली कि भविष्य में ऐसी किसी भी मां को पीड़ा न सहनी पड़े। भविष्य में बुजुर्गों के साथ ऐसा न हो तो उन्होंने एक बुजुर्ग

कमीशन का आयोग का गठन किया। (3.10) मैं इनको दिल से धान्यवाद देती हूं। साथ साथ धान्यवाद मैं अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी देती हूं कि उन्होंने साठ वर्ष से ऊपर के तमाम आयु के बुजुर्गों के लिए फ्री में बस सर्विस उपलब्धा कराई है उसके लिये भी बहुत बहुत धान्यवाद।

मैं फिर कहूंगी कि कि बहुत बारीकी से चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, पर्यटन हो, जल हो हमारे सभी साथियों ने बहुत बारीकी के साथ चर्चा की और उन मुद्दों पर जाना नहीं चाहती लेकिन एक बात फिर कहूंगी कि अभी कुछ साथी या हो सकता है नेता विपक्ष दोबारा इस बात को बोलें कि हमने दलितों के लिये कुछ नहीं किया क्योंकि कल की घटना है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में दलित न्याय मार्च निकाला गया कि दिली सरकार दलित विरोध ाी है, दलित न्याय मार्च निकालो। भई, किस प्रकार से दलित विरोधाी है? अगर आप दलितों को शिक्षा नहीं देंगे, अगर आप उन्हें साथ बैठने का सम्मान नहीं देंगे, अगर आप उन्हें बेहतर वेतन नहीं देंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? आपने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाते हुए दलितों को हमेशा वोट बैंक समझा और शासन किया। लगातार कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें! मैं कल एक टीवी रिपोर्ट देख रही थी। उसमें ये था कि दिल्ली सरकार का रियलिटी चैक कि शिक्षा में इतना भारी भरकम बजट ये लेकर आये लेकिन शिक्षा से क्या बच्चे खुश हैं? क्या पेरेंटस खुश हैं? क्या वहां के आसपास के लोग खुश हैं? दिल्ली सरकार की शिक्षा प्रणाली से और बहुत सुनकर आश्चर्य हुआ कि लाख कोशिशों के बाद, लाख मुंह में शब्द डालने के बाद रिपोर्टर बच्चों में शब्द ठूंसने की कोशिश कर रहे थे कि वो एक बार बोल दें कि शिक्षा व्यवस्था से वो खुश नहीं हैं। दिल्ली सरकार के आने के बाद शिक्षा

में सुधार नहीं आया, लेकिन बच्चों ने सच्चाई बोली कि पिछले दो सालों में सरकारी स्कूलों में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा के स्तर पर हुए सुध ार से उन्हें सम्मान मिलता है। न सिर्फ किताबी ज्ञान उन्हें दिया जाता है बल्कि समाज में एक अच्छा ईमानदार व्यक्तित्व, एक ईमानदार इंसान कैसे बना जाये, सम्मानजनक जीवन किस तरह से जिया जाये, उसकी भी शिक्षा एक्स्ट्रा करिकुलम के हिसाब से उनको दी जाती है।

अध्यक्ष जी, लगातार मैं दो दिन से सुन रही हूं जगदीश प्रधान जी कहते हैं कि एक लाख बच्चे नौवीं क्लास में फेल हो गये। वो एक लाख बच्चे जो नौंवी क्लास में आकर फेल हुए वो नौ साल लगभग लगा होगा उन्हें नौंवी में आने में नौ साल से पिछले नौ साल से दिल्ली में जो सरकार थी, वो कांग्रेस की थी और उससे भी अगर हम पूर्व अंदाजा लगाये तो 1 5 और 5 बीस साल पांच साल बीजेपी की सरकार और 15 साल लगातार कांग्रेस की सरकारों का ही आज ये किया हुआ कारनामा है कि आज हमारा नौंवी का बच्चा क्या, दसवीं ग्यारहवीं का बच्चा भी हिंदी में ठीक से अपना नाम नहीं लिख पाता तो इसके लिए मनीष सिसौदिया या केजरीवाल सरकार को बदनाम करने की जगह हम अपना आत्मचिंतन करें, न कि बीस सालों में हमने अपनी एक पीढ़ी को कहां लाकर खड़ा कर दिया है कि आज वो मजदूरी करने को मजबूर है। चोरी चकारी करने को मजबूर है लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने उनकी नींव कमजोर बनाई्ग। कमजोर भी एक साजिश के तहत बनाइ कि अगरहम इन्हें पढ़ा दे गे, लिखा देंगे, शिक्षा का ज्ञान दे देंगे, समाज का ज्ञान दे देंगे तो ये हमारी जो गंदी राजनीति है, जाति ध ार्म मजहब में जो बांटने वाली राजनीति है, इसे समझेंगे और हमारे को कभी

भी सत्ता पर काबिज नहीं होने देंगे। लेकिन मैं एक बार पुनः धान्यवाद देना चाहती हूं हमारे शिक्षा मंत्री का कि उन्होंने जो बजट पेश किया, उसमें से 24 परसेंट बजट उन्होंने एक बार शिक्षा के लिये रखा। न सिर्फ शिक्षा के लिये रखा, मैं कहना चाहती हूं कि उन्होंने एक हमारी पीढ़ी के डेवलेपमेंट के यि एक नींव तैयार करने के लिये ये इन्वेस्ट किया और इसको हम दिल से स्वीकार करते हैं, सलाम करते हैं कि कम से कम अब जो आने वाले बच्चे हैं, जो आज बच्चा चौथी क्लास में या पांचवीं क्लास में पढ़ा रहा है जब वो नौवीं क्लास में आयेगातो उस क्लास का रिजल्ट हम 100 परसेंट लाने में कामयाबी हासिल करेंगे। ये सपना हमारा जरूर पूरा होगा। न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने ऐतिहासिक क्रांति की, जैसा कि मैंने बताया हेल्थ के ऊपर भी हमने ट्रिपल लेयर का पूरा का पूरा हेल्थ गार्ड सिस्टम देने की तैयारी की है। महिला आयोग में बजट बढ़ाने की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, सात करोड़ से सीधा हमने बीस करोड़ का इजाफा किया है। युवाओं के लिये भी सौ करोड़ रूपये से हमने चार सौ लाइब्रेरी बनाने की तैयारी की है।

अध्यक्ष जी, ये पूरा का पूरा जो बजट है, वो सपनों के भारत को सच करता हुआ बजट है क्योंकि बाबा साहेब कहते थे कि शिक्षित जो व्यक्ति होगा, वो अपनेसारे अधिाकार खो दे....और यहां पर दुर्भाग्य रहा पिछली सरकारों के माधयम से कि इन्होंने एक वही चीज जनता को गरीब बच्चों को नहीं दी जिसका वो अधिाकार रखते थे। तमाम चीजें हैं कितने भी मुद्दों पर मैं बोल लूं और सभी आने वाले वक्ताओं पर उन मुद्दों पर बोलने के लिये एक बहुत बड़ी बात है। ये टाईम्स आफ इंडिया की खबर है कि दिल्ली का जो टोटल

बजट है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7.2 परसेंट ही हमें सैंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है बाकी का जो 92.8 परसेंट है, वो हमें खुद इकट्ठा करना पड़ता है, चाहे हम अपने टैक्स के माधयम से करें या और किसी माधयम से करुं।

अध्यक्ष जी, हमारी नीयत साफ है, हमारा दृष्टिकोण एकदम साफ है कि हमें जनता के हित में काम करना है, जनता की भलाई के लिये काम करना है औ उसी के मद्दे नजर एक और दिल्ली सरकार है जो कि अपने कुल बजट का छह परसेंट जो है चार हजार करोड़ केंद्र सरकार को देता है ब्याज के रूप में और अन्य ऋण के रूप में और वहीं पर दिल्ली सरकार की मंशा है, साफ इच्छा है, साफ दृष्टिकोण है कि एमसीडी के लिये वर्ष 2917-18 में जो सात हजार सात सौ इक्यावन करोड़ रूपये जो कि कुल बजट का लगभग 16 परसेंट है, वो एमसीडी को जायेगा लेकिन उसके एवज में न हम कोई ब्याज लेते हैं और न कोई ऋण वापसी लेते हैं। यह हमारी ईमानदारी है निगम को मजबूत करने की, ये हमारा एक ईमानदारी स्वच्छ भारत अभियान के सपने को जो बीजेपी कभी भी पूरा नहीं कर पाई, उस सपने को पूरा करने की।

अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आज तक हमारे पूर्वांचल के साथियों को, दिल्ली में तमाम पार्टी, तमाम राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझी और जब उनका एक ऐतिहासिक पर्व छठ पर्व आता है तो सिर्फ उस मंच को राजनीतिक मं बनाकर भाषण देकर वहां से ज ुमले कहकर वहां के नेता चले आते थे लेकिन यही अरविंद केजरीवाल की सरकार का ऐतिहासिक फैसला है कि उन्होंने 1 20 करोड़ की लागत से नये छठ घाट बनाने का ऐलान किया है। मैं धान्यवाद देना चाहती हूं कि पुनः हमारी पूरी कैबिनेट को, हमारे वित्तमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने

इतना ऐतिहासिक औरइतना सिम्पल बजट पेश किया है कि साधारण सी महिला भी इस बजट को समझ सकती है। एक मजदूर भी इस बजट को समझ सकता है। कल हम अपने कार्यालय में बैठे थे और जो हमारे जेजे क्लस्टर के वालंटियर हैं, वो आये और उन्होंने बोला कि दीदी, इतना बढ़िया बजट आया है! आज से पहले तो बजट लगता था कि बस नेताओं के लिये कोई पर्व होता होगा गैट टू गैदर पहले तो बजट लगता था कि बस नेताओं के लिये कोई पर्व होता गैट टू गैदर का प्रोग्राम होता होगा लेकिन आज मालूम पड़ता है कि ये बजट वास्तव में हम गरीब जनता के विकास के लिये, हमारे सम्मान के लिये बनाया गया है। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी लोगों को धान्यवाद देती हूं और मैं बस यही कहना चाहती हूं कि ये अभी तीसरा बजट है अभी और ऐतिहासिक काम करने बाकी हैं, अभी और इतिहास रचना बाकी है, बहुत बहुत धान्यवाद, जयहिंद, जयभारत।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजेंद्र गुप्ता जी।

श्री विजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आपका बहुत आभार आपने मुझे बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। ये बजट चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष की संख्या बहुत अधिाक है और विपक्ष संख्या में बहुत कम है। मैं इतना कह सकता हूं कि....

...(व्यवधान)

श्री विजेंद्र गुप्ता जी : अरे! थोड़ी तसल्ली रखो। अभी बड़े मौके आयेंगे आपको बोलने के।

....(व्यवधान)

श्री विजेंद्र गुप्ता जी : जिसमें आउट कम बजट की बात की गई है, इससे पहले स्वराज बजट की बात की गई थी। आउट कम बजट मैंने काफी किताबों को खंगाला, भई, आउटकम कहीं दिखे। तो मुझे कहीं कोई आउटकम नहीं दिखा। तो मैंने मंत्री जी से....

....(व्यवधान)

श्री विजेंद्र गुप्ता जी : एक मिनट फिर बात की अभी

अध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दीजिये उनको कोई बात नहीं....

....(व्यवधान)

श्री विजेंद्र गुप्ता जी : मंत्री जी से....

अध्यक्ष महोदय : सरिता जी, ऐसे सदन का समय खराब न करे, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है....नितिन जी प्लीज।

श्री विजेंद्र गुप्ता : मंत्री जी से मैंने बात की, वित्तमंत्री जी स तो उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक आपको आउट कम बजट का मसौदा मिल जायेगा तो अध्यक्ष जी, मैं कहूंगा कि चर्चा बिना उस मसौदे के अधूरी है लेकिन खैर! जो भी हमारे समक्ष है। अभी मंत्री जी ने, वित्तमंत्री जी ने जब बजट पेश किया तो पेज नंबर आठ पर उन्होंने बोला कि अध्यक्ष जी, इस बार नोटबंदी के कारण राज्य के आर्थिक परिदृश्य में नाकारात्मक रूझान देखने को मिल रहा है। मैं मंत्री जी के समक्ष वित्तमंत्री जी के समक्ष आपके माधयम से कुछ आंकड़े पेश कर रहा हूं। मेरे पास पूरे देश की तस्वीर है। नोटबंदी आठ नवंबर 2016 को हुई थी और हर राज्य में नोटबंदी के बाद नवंबर और

दिसंबर के महीनों में जो क्लैक्शन थी, टैक्स कलैक्शन, वो काफी बढ़ गई। (3.20) आंध्र प्रदेश में 12.91%, उसके बाद बिहार में 20.13%, जम्मू कश्मीर में 111.63%, उसके बाद कर्नाटका में 9.32%. केरला में 7.21%, मधय प्रदेश में 12.66%, महाराष्ट्रा में 16.7 मेरे पास पूरे देश का खाका है....

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली में कितनी बढ़ी?

श्री विजेंद्र गुप्ता : लेकिन दिल्ली और वेस्ट बंगाल जो राज्य नोटबंदी का विरोधा कर रहे थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि 8 नवम्बर को जब नोटबंदी हुई तो पूरे नवम्बर का महीने में पुराने नोट सरकारी विभागों के लए जा रहे थे बावजूदी इसके दिसम्बर में दो राज्य वेस्ट बंगाल में 7.84% यानि कि 1483.66 करोड़ थी दिसंबर 2015 में टैक्स कलैक्शन और 2016 दिसंबर में, दिसंबर 2016, 16 दिसंबर नहीं, कलैक्शन थी 1599.43 करोड़ यानि कि 1599.43 करोड़ थी जो दिसंबर 2016 में 1514.63 करोड़ यानि कि 5.3% कम हुई। कहने का अर्थ ये है कि जब पूरे देश में नोटबंदी के बाद रैवन्यू में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है तो फिर ये वित्त मंत्री को बताना पड़ेगा, इस पर जानकारी देनी पड़ेगी सदन में कि क्या कारण है ममता दीदी के साथ मिलकर दिल्ली में ये 50 करोड़, हालांकि नवम्बर में वित्त मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा आपको 400 करोड़ रूपये अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं, नवंबर में। नवंबर ी फीगर भी मैं आपको दे देता हूं 2015 मेमं 1580.89 करोड़ आपने पिछले वर्ष किए थे और इस वर्ष आपने 1837.94 करोड़ रूपया प्राप्त किया जो लगभग कुल का 400 करोड़ रूपये के करीब बनता है। तो सवाल ये है कि मैं कुछ इस तरह की चीजों को स्पट करना चाहता हूं। अभी यहां पर बहुत सारी बातें आई। कल मुख्यमंत्री जी का बयान था वाई-फाई को लेकर तो कहा गयाकि

देखिए वाई-फाई पर अभी हमारा कोई मॉडल नहीं है हमारे पास।

अध्यक्ष महोदय : पेंशन इतनी बड़ी है कि उसके लिए धान्यवाद कर दो।

श्री विजेंद्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आप आदरणीय है। मैं आपके समक्ष पूरा बजट का जो है, कम से कम समय में खाका खींचने की कोशिश करूंगा और मुझे मालूम है वित्त मंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है 'निंदक नियरे राखिये' ठीक है न जी?

अध्यक्ष महोदय : मदन जी, प्लीज।

श्री विजेंद्र गुप्ता : लेकिन एक के बाद एक अभी भ्रष्टाचार की मैं बात करूं, सत्ता में जब जाए थे तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था लेकिन मैं उनकी गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। 'स्वराज बजट' की बात हुई थी पिछले वर्ष। कोई 'स्वराज बजट' ये मेरे पास पुस्तक है अरविंद जी होते तो मैं उनकी लिखी हुई पुस्तक लेकर आया हूं, मैंने इसको पढ़ा है। इसमें जो कुछ लिखा है....बिल्कुल। क्योंकि बिना जाने क्रिटिसिजम ठीक नहीं है लेकिन इसमें जो लिखा है, मैं पढ़ूंगा, तो समय ज्यादा लग जाएगा। मैंने हालांकि अंडर लाईन किया हुआ है, बजट के ऊपर ही लिखा हुआ है लेकिन इन 3 वर्षों में इस पुस्तक में जो बजट के बारे में लिखा गया है, उसका कहीं भी अंशमात्र इन 3 वर्षों के, हां, आपने पिछले वर्ष मौहल्ला सभाओं की बात की थी, तो मैं ये ही कहूंगा कि ये तो फिर बेवफाई है और वित्त मंत्री जी कि ये जिस तरीके की वादा खिलापी हो रही है, जिस तरह का विश्वास टूट रहा है, उस पर इतना ही कहूंगा कि :

'तू इस तरह से मेरे साथ बेवफाई कर,
कि तेरे बाद फिर मुझे कोई बेवफा ना लगे।'

माननीया उपाधयक्ष महोदया (सुश्री राखी बिड़ला) *पीठासीन हुई*

श्री विजेंद्र गुप्ता : तो सवाल ये है कि आपने ये कहा, अरे! ताली भी बजा दिया करो कभी-कभी। कोई ऐसी बात नहीं है। जरूरी नहीं कि विरोध ा ही करना है। अब सवाल ये है कि मैं आपके समक्ष ये कुछ विषय जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, मेरे लिए ही नहीं वित्त मंत्री जी के लिए भी और इस सरकार के लिए भी और मेरा भी हमेशा एक प्रिय विषय रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य। मैं हमेशा कहता हूं, वर्षों से इस बात को कह रहा हूं और जिसको ये सरकार ने भी क्योंकि आ आदमी पार्टी बनी है जिस दिन इस देश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर वोट पड़ने शुरू हो जाएंगे, जिस दिन सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर जिस दिन सरकारें इस देश में बनने लगेंगी, इस देश की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा, मुझे याद है मनीष जी का पहला भाषण कि शिक्षा में दो गुणा खर्च करेंगे। स्वास्थ्य पर डेढ़ गुणा खर्च करेंगे। मैं आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहता हूं मनीष जी आप इंच भर भी आगे नहीं बढ़े। देखिए 2014-15 में वास्तविक खर्च जो शिक्षा पर हुआ कुल बजट का वो 17% है लगभग और 15-16 में आप आए, आपने बजट पेश किया। आपने सदन को विश्वास दिलाया कि शिक्षा पर दो गुणा खर्च होगा। लेकिन जब वासतविक खर्च सामने आया 15-16 का तो वो भी लगभग 17% ही है। यानि कि 2014-15 में जो प्रतिशत था कुल बजट के खर्च का, 2015-16 में भी उतना ही वास्तविक खर्च आया। उसके बाद 16-17 में जो रिवाइज बजट एस्टीमेट आपने पेश किया, उसमें भी

हमको वो परिप्रेक्ष्य नजर नहीं आया जिसकी बात आप कर रहे थे और वो भी लगभग 18% शिक्षा का कुल बजट का। चलिए ये तो बीत गई सो बीत गई!

अब जो इसवर्ष आपने बजट पेश किया है। इस वर्ष जो आपने बजट पेश किया है उसमें आपने 9066 करोड़ रूपया शिक्षा पर व्यय रखा है और कुल बजट जो वॉल्यूम है बजट का, वो है 48,000 करोड़। अगर आप कैल्कुलेट कर लीजिए ये भी 18% प्रपोजल है ये। पीछे जो ख्र्च है वो वास्तविक सामने आ रही है, उसमें बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी अंतर है। लेकिन जब 9066 करोड़ रूपये आप शिक्षा के लिए रखते हैं 48,000 करोड़ के बजट में अध्यक्ष महोदय, तो मुझे लगता है कि ये दावे कहीं न कहीं खोखले सिद्ध हो रहे हैं। (3.30) शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, वो कमरों की बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी से दिल पर हाथ रखकर बताइये जो सपना आप देख रहे थे शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का क्या मात्र मेरे उठाय गये सवाल या मेरी जिज्ञासा का जवाब सिर्फ बन रहे कमरों तक सीमित रह जाएगा। आपने शिक्षा के व्यावसायिकरण पर, आपने दाखिला नीति पर, आपने शिक्षा के स्वभाव पर बहुत सारी कमेटियों की रिपोर्टस है, यशपाल कमेटी की रिपोर्टस है, बस्ते का वजन है, पढ़ाने के तरीके का विषय है, लेकिन तीसरे बजट तक वो तस्वीर धूमिल होती हुई नजर आ रही है और वो सिर्फ कुछ कमरों तक सीमित रह गई है। इसलिये मेरा अनुरोध ा है सरकार से, वो इस पर गौर करे। मुझे मालूम है कि मेरे लिये जिन परिस्थितियों में मैं यहां हूं, जिन परिस्थितियों में मैं आपके समक्ष अपनी बात कहता हूं वो मेरे लिए बहुत प्रतिकूल है। कई बार मेरे पास मेरे साथी आते

हैं। ऑफ दा रिकॉर्ड कहते हैं, ''भाई साहब, आपमें बड़ी हिम्मत है। आपको कुछ-कुछ कहा जाता है आपमें पेशंस बड़ी है। तो मैं कहता हूं उनको

'साहिल के सुकुन से किसे इंकार है,
तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है'

तो इसलिये सवाल ये है कि साहिल के सुकुन में हैं आप, आप रहिये, आपके लिये परिस्थितियां बड़ी रोचक भी हैं और सकारात्मक भी है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको याद होगा वित्त मंत्री जी, आपकी सरकार का संकल्प था कि हम स्वास्थ्य पर डेढ़ गुणा खर्च करेंगे, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर डेढ़ गुणा खर्च होगा, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, वो खर्च बढ़ा नहीं है अध्यक्षा महोदया, वो खर्च कम हो गया। वर्ष 2014-15 में वास्तविक खर्च 3116 करोड़ रूपये था जबकि कुल बजट 30240 करोड़ रूपये का था, जो 10 प्रतिशत से अधिाक था ये खर्च। आपके कहे अनुसार डेढ़ गुणे का अर्थ है कि ये लगभग 10.5 या 10 प्रतिशत, 15-15.5 प्रतिशत, 16 प्रतिशत लेकिन 2015-16 में वास्तविक खर्च हुआ 9.3 प्रतिशत, 35196 करोड़ का बजट था और 33 सौ करोड़ रूपया खर्च हुआ, 2016-17 में भी ये जो खर्च है ये 10 प्रतिशत से कम है यानि की 9.85 प्रतिशत और अध्यक्षा जी, जो आपने अब बजट पेश किया है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिये, वो भी लगभग 10. 5 प्रतिशत है, 5033 करोड़, 48 हजार करोड़ पे जो बजट एस्टीमेट है 17-18 का वो मैडिकल एंड पब्लिक हैल्थ पर 5033 करोड़ रूपया है। ये आपका ही दस्तावेज है, मेरा दस्तावेज नहीं है। तो सवाल ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर भी और शिक्षा पर भी सरकार कोई आमूल-चूल परिवर्तन करने की बजाए विज्ञापनों के माधयम से अपनी बात को कहकर लोगों को ये अहसास कराना

चाहती है कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं बदल रही है लेकिन आपको याद होगा गत वर्ष जब डेंगी का प्रकोप आया था तो किस तरह पूरी दिल्ली हाथ-पैर फूल गये थे, सरकार भी उस परिस्थिति को समझ नहीं पा रही थी। आज भी दिल्ली के अंदर वाटर बॉर्न डिसीजेज हो वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हो या फिर कोई जल ज नित बीमारी हो हम देख सकते हैं कि प्राईमरी हैल्थ के मामले में दिल्ली के अंदर कोई भी, किसी भी प्रकार की नई व्यवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं स्वास्थ्य और शिक्षा पर ओर अधिाक समय इसलिए नहीं लगाना चाहूंगा कि मैंने जो कुछ कहा है, वो एक निचौड़ है। सरकार को जरूश्र इस पर विचार करना चाहिये। लेकिन आपने एमसीडी के बारे में कहा और एक बार नहीं, आपने अपने भाषण में कई बार इस बात को दोहराया कि देखिये, हमने उनसे और आपने ये भी कहा कि भारत सरकार हमसे रि-पेमेंट और इन्ट्रैस्ट 4 हजार करोड़ रूपये जो रिवैन्यू एक्सपैंडिच्र है, उसका हिस्सा है, 4 ह जार करोड़ तो केंद्र सरकार हमसे ले जाती है। वित्त मंत्री जी, आपने भी 2017-18 में नगर निगम से 4 सौ करोड़ रूपया इन्ट्रैस्ट वसूलने का प्रावध ान किया है और टोटल ये जो रकम है, ये 797 करोड़ रूपये है। आप बताइये, ज ब आपने ये कहा कि केंद्र सरकार को हमें लोन कि किस्त देनी है, इंटरैस्ट देना है तो आप नगर निगम से जो आप वसूल रहे हैं, इसके बारे में मुझे लगता है कहीं न कहीं सदन के समक्ष सही स्थिति पेश नहीं की, लेकिन आपने शायद हो सकता है जगलरी ऑफ फीगर्स करने की कोशिश की। उनको साल दर साल के बीच में फंसाने की कोशिश की। आप कहते हैं कि भारत सरकार हमको पैसा नहीं देती, भारत सरकार से हमको कोई मदद नहीं मिलती और भारत सरकार हमें रोकने की कोशिश करती है। हमें वित्तीय रूप

से पंगु बनाने की कोशिश करती है आपने जब पहला बजट पेश किया था ग्रांट इन-एड एंड कंट्रीब्यूशनस यानि की भारत सरकार से वित्तीय रूप में मिलने वाली सहायता इसकी अनुमान राशि प्रपोजल आपने 2777 करोड़ रूपये इस सदन के समक्ष रखी थी। पहला ही साल था इस सरकार का। लेकिन जो आपको वास्तविक प्राप्ति हुई, वो हुई 4258 हजार करोड़ रूपये, 57 प्रतिशत अतिरिक्त लगभग, अगर मैं इसको पूरा कैल्कुलेट करूंगा तो 60 परसैंट आपको अतिरिक्त मिला, आपकी अपेक्षा से 60 प्रतिशत अधिाक आपको मिला, फिर आपने जबकि 2014-15 में ये राशि कम थी, लेकिन नई सरकार आई। 2014-15 में, ये 2348 करोड़ रूपये थे। आपने अपेक्षा की 2777 करोड़ की, आपको मिले 4 285 करोड़। अभी आपने बजट एस्टीमेट रखा 16-17 में 3870 करोड़ का, लेकिन अभी तक आपको 4 हजार करोड़ से ज्यादा प्राप्त हो चुकी है, जब एक्चुल फीगर आयेगी, वो क्या होगी, वो आप सदन के समक्ष आप जरूर रखेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आपने जैसे कल बताया कि स्लम बस्तियों में टॉयलेट बनाने के लिए, मैं खुद स्लम बस्ती, बहुत बड़ी तादाद में मेरे क्षेत्र में स्लम बस्तियां है, मैं कल वहां गया। वहां डीडीए की एक बहुत बड़ी साइट जिस पर हम पार्क बनाना चाहते थे और वो भी स्लम बस्ती के लोगों के लिये, क्योंकि वो चारों तरफ से स्लम बस्ती है और बीच में वो एक गड्ढा है बहुत बड़ा, उसकी फिलिंग करवाकर हम उस पर पार्क बनाना चाहते थे, झुग्गी-बस्ती में रहने वाले लोगों के लिये। लेकिन हमको लगाकि पार्क से ज्यादा जरूश्रत शौचालय की है, टॉयलेट की है, नहाने के लिये स्थान की है और डीडीए ने वो जगह उपलब्धा कराई। बिना किसी नक्शे के, बिना किसी वजह के, लेकिन कल आपने ही सदन को बताया कोई एक जगह नहीं, मैं इस पर कोई अपनी पीठ नहीं थपथपना चाहता कि मेरे क्षेत्र में था, मैंने डीडीए से जगह दिलवाई।

आपने ही सदन को अवगत कराया कि डीडीए ने पूरी दिल्ली में हर स्थान पर, हमको झुग्गी बस्तियों के आसपास (3.40) शौचालय बनाने के लिए अनकन्डीशनल एनओसी दे दिया है। तो ये भावना अगर आप रखकर के सरकारकाम करे अभी बजट को बहुत अच्छा बताया जा रहा है। लेकिन बजट में फिसलन डेफिसिट है, वो बढ़ रहा है। फिसकल डेफिसिट बढ़ने का मतलब ये है कि जितनी आपकी आय है, उससे ज्यादा आपके खर्च है। मैं अभी आपके समक्ष वो आंकड़े भी रखूंगा जिसके अंतर्गत रेवेन्यू एक्पेंडिचर, जिसको आपने नॉन प्लान की जगह नाम दिया है, और प्लान के जगह जिसको आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा है। इसमें बड़ा भारी गैप बढ़ता जा रहा है। हम सब जानते हैं रेवेन्यू एक्सेपेंडिचर क्या हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कोई सरकार नही तो तब भी होंगे। मुझे तो नहीं लगता अध्यक्ष जी, किसी की सैलेरी रूक सकती है या रोकी जाती है। सरकार न होने पर, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स हैं, वो तो होंगे ही। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से किसी सरकारकी तस्वीर नहीं दिखाई जाती। मुझे मालूम है वित्त मंत्री खड़े होकर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से कुछ बताएंगे और वो बताएंगे कि ऐसा नहीं हे। हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से लोगों का डवलपमेंट कर रहे हैं। हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से लोगों का अपग्रेडेशन कर रहे हैं और उसकी परिभाषा रखी जाएगी, रखी गई है, रखी जाती है। वो बताई जाएगी फिर से कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप क्या समझते हैं कि सब्सिडी देने से लोगों का अपग्रेडेशन नहीं हो रहा। मैं उस पर कोई विवाद नहीं करना चाहता। मैं उस पर कोई तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कुल बजट का, 38 हजार चार सौ सत्ताईस करोड़ है। कुल बजट का 48 हजार करोड़ में से आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 38427/-

रूपये है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका सिर्फ 9573 करोड़ है। कपिल जी को मेरी बात बहुत पसंद आई है।

उपाधयक्ष महोदया : कन्क्लूड करिए गुप्ता जी। गुप्ता जी कन्कलडू कर लीजिए प्लीज। बहुत देर हो गई आपको।

श्री विजेंद्र गुप्ता : अध्यक्षा जी, अब आप अगर रिबेट की भी बात करते हैं, सब्सिडी की भी बात करते हैं। मैंने इसका टोटल किया है। चार तरह की सब्सिडी आप दे रहे हैं। एक सब्सिडी आप दे रहे हैं, पावर सब्सिडी, जसमें आपने 16 सौ करोड़ का प्रावधान किया है। एक आप वाटर सब्सिडी दे रहे हैं, जिसमें आपने 353 करोड़ का प्रावधान किया है। एक डीटीसी कन्सेशनल पासेज दे रहे हैं, जिस पर आपने 71 करोड़ का, इसको अगर टोटल कर लिया जाए तो ये दो हजार करोड़ रूपया भी पूरा नहीं बैठता है। कहने का अर्थ यह है कि 38427 करोड़ ये और ये मैं अगर आपको आंकड़े बताऊं कि किस तरह से आपका रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 2 014-15 में 24 परसेंट कुल बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर था, 76 प्रसेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। 2015-16 में आपका 75 प्रसेंट एक्चुअल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 2 5 परसेंट आपका कैपिअल एक्सपेंडिचर था। लेकिन 2016-17 में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर घटकर के आ गया 2 परसेंट यानि की 25 परसेंट से 22 परसेंट औरअ ब इस साल घटकर आ गया है ये 19.9 परसेंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका बढ़कर के हो गया 80 परसेंट से ज्यादा। ले किन चलिए ये भी देखा जाता लेकिन आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकी फिगर्स को धयान से देख जाए तो आपने जो बजट पेश किया है, उसमें जो आपका डेफिसिट है, वो 3785 करोड़ का है। यानि कि 3785 करोड़ रूपया आपने,

आपको जो आय हो ये जो फिसकल डेफिसिट है, ये जो फिसकल डेफिसिट है, ये भी हर साल बढ़ रहा है। ये भी आपका जो फिसकल डेफिसिट है, मैं इसकी कुछ फीगर्स भी आपके समक्ष लाना चाहता हूं जिससे कि आपको यह धयान रखा 24 हजार पांच करोड़ का पिछले वर्ष। रिवाईज्ड में 22 हजार और अब जो एक्चुअल फीगर्स आ रही हैं, 20 हजार करोउ़ के आसपसा आ रही हैं जो मेरी जानकारी क अनुसार है। तो सवाल यह है कि जो वैट है, वह कम हो रहा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। आपका जो फिसकल डेफिसिट है, वो बढ़ रहा है यानि कि ये बजट सरप्लस था वो डेफिसिट, फिसकल डेफिसिट हो रहा है। जो डेफिसिट हो रहा है, ये एक बड़ी चिंता की बात है।

उपाधयक्ष महोदया : बस, अब खत्म करिए।

श्री विजेंद्र गुप्ता : मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और वो ये है कि वैसे तो पिछले छः महीने से यहां पर अनुसूचित जाति का जो हमारा सदस्य मंत्री था, वहां किसी मंत्री की एप्वाइंटमेंट नहीं हुई है। यानि कि दिल्ली की सरकार दावा करती है कि वो अनुसूचित वर्ग के भले में काम कर रही है लेकिन मुझे यह बताते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि आपके कुल बजट का जो खर्च है, वैल्फेयर पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, वो बाकी देश से बहुत कम है। आपके समक्ष जो 2916-17 में आपने प्रावधान किया दिल्ली में, 2016-17 जो प्रावधान था, आंध्र प्रदेश का, वो 7.03 प्रतिशत कुल बजट का 7.03 प्रतिशत। लेकिन आपके बजट में वित्त मंत्री जी ये मात्र और भी मैं आपको स्टेटस बता देता हूं थोड़ी सी, महाराष्ट्रा का 4.06 प्रतिशत, तेलंगाना का 8.02 प्रतिशत, कर्नाटका का 5.06 प्रतिशत और बाकी राज्यों का

भी देखा जाए तो किसी का 3 परसेंट, किसी का ढाई परसेंट किसी का चार परसेंट, लेकिन दिल्ली में ओबीसी को मिलाकर आपने मात्र 2016-17 में .09 प्रतिशत, दशमलव 9 प्रतिशत। ये सोचना पड़ेाग आपको। 399 करोड़ और उसमें से वास्तविक खर्च क्या होगा, ये तो एक्चुअल बाद में मालूम चलेगा और इस वर्ष भी 2017-18 में भी जो प्रावधान किया गया है, वो कुल बजट का लगभग 408 करोड़ यानि की अगर देखा जाए तो 48 हजार करोड़ के बजट में अनुसूचित जात के कल्याण पर .08 प्रतिशत इस वर्ष खर्च किया जाएगा जो देश के किसी भी राज्य में ख्र्च यिके जाने वाला कम से कम बजट ये है। मिनिमम वेज की आप बात कर रहे थे। मिनिमम वेज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कहा, कल मुख्यमंत्री जी ने ब्यान दिया कि मिनिमम वेज ओर आपने भी बजट भाषण में कहा कि मिनिमम वेज 37 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है। मिनिमम वेज 37 प्रतिशत तक। लेकिन वित्त मंत्री जी, उससे पहले दिन, शाम को हाई कोर्ट ने स्टे किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि जो मिनिमम वेज आज भी दी जा रही है, इसके लागू होने से पहले क्या वो मजदूरों को मिल रही है। हम सब लोग मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए संकल्पबद्ध है उनको लाने क ेलिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। राजनीति से ऊपर हम सब लोग, हम एक दूसरे को कोई भी आरोप प्रत्यारोप क्यों न करें, लेकिन हम संकल्प ल ेते हैं। सरकार में जो ठेकेदार है, क्या श्रमिकों को मिनिमम वेज जो आज दिया जाना चाहिए, क्या वो उनको दे रहे हैं। (3.50)

आप मुझे बताइए किसी भी एक एम्पलायर पर आपने पेनल्टी लगाई, एक भी एम्पलायर को आपने जेल की सलाखों के पीछे भेजा? क्या ये मान

लिया जाए कि दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज का कोई वॉयलेशन नहीं हो रहा है और अगर मिनिमम वेज का वॉयलेशन हो रहा है तो फिर सरकार सिर्फ कागजों में मिनिमम वेज बढ़ाने की बात कह कर क्या सिर्फ वाहवाही लूटनाचाहती है या फिर वही ढाक के तीन पात कि लोगों को उसी प्रकार से ये सारे उसमें वो देख जाएगा। मैं इतना कहूंगा कि सरकार इस बजट, पर अभी अपने कल बात की थी कि मिनिमम वेज की फाइल जो है, जो रोक ली गई थी और जो मिनिमम वेज मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की वित्त मंत्री जी, मिनिमम वेज की फाइल नहीं रूकी। रूकी, मिनिमम वेज की फाइल आठ महीने बाद लगभी रिपोर्ट बनने के बाद उप-राज्यपाल कार्यालय गई है। 8 की जगह वो 6 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। एक साल भी हो सकता है। लेकिन क्या ये सरकार कानून का पालन करना, कानून से चलना उस पर सियासत करती रहेगी या फिर कानून का पालन करके इस दिल्ली के काम को आगे बढ़ाएगी। वो फाइल वापस आने की बात क्यों की गई कमेटी जो मिनिमम वेज कमेटी है, उसके गठन पर उस राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर होने थे। जब आपने फाइल भेजी विधिावत् तो आप कितने घंटों में आपको फाइल वापस मिली, उस मिनिमम वेज कमेटी को एक्जीक्यूट होने में जबक वो फाइल आपके पास आ गई कमेटी नॉमिनेट हो गई। तो फिर उसके बाद कमेटी ने इतना लम्बा समय क्यों लिया? उसकी रिपोर्ट बना लें, उस रिपोर्ट को बनाकर दोबारा उप राज्यपाल को भेजने में इतना समय क्यों लिया? क्या मैं ये कहूं कि :

उसूले चमन से जो नहीं वाकिफ।
निजामे चमन उनके हाथ आ गया है।।

तो सवाल ये है कि निजाम का कानून तो पालन करना पड़ेगा। बिना निजाम के कानून के अगर आप चाहे कल स्वर्गीय पूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल।

उपाधयक्ष महोदय : गुप्ता जी आप कितनी देर में खत्म करेंगे? आध ा घंटा हो गया। एक मिनट से ऊपर नहीं।

श्री विजेंद्र गुप्ता : एक मिनट में, एक मिनट मैडम आपका ऑर्डर सर माथे पे। भई ऐसा है, यहां पे गोयल साहब बैठे हाते तो मैं कुछ गुस्ताखियां कर भी लेता, अब मैडम बैठी हैं तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा न इनका कहना। तो प्रश्न ये है कि राम किशन ग्रेवाल के मामले में ये कहा गया कि हमको एक करोड़ रूपया नहीं देने दिया गया। हमारी भी भावनाएं हैं पूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल जी से जिन्होंने सुसाइड....भावनाएं हमारी भी जुड़ी हुई है। लेकिन उसके बावजूद कितने और सैनिक इस देश के लिए बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, क्या मैं जानना चाहताहूं सरकार ने कभी कोशिश की या मैं ये कहूं कि मोहब्बत है कि सियासत है या इसको यूं कहूं कि जब आज राजनीति में नहीं थे, तो कल सियासत में भी मोहब्बत देखी जाती थी, कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। तो सवाल ये है कि आप लोगों ने आ कर मोहब्बत में भी सियासत शुरू की है और पूर्व सैनिक के नाम पे आपने राजनैतिक रोटियां सेकने की कोशिश की है। आपने देश के प्रधानमंत्री से उसको जोड़ने की कोशिश की है। जब कि वास्तविकता ये है अगर मैं सदन के सामने. ...खत्म कर रहा हूं जी खत्म कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : विजेंद्र जी आधा घंटा से ज्यादा हो गया है। आध ा घंटा पूरा।

श्री विजेंद्र गुप्ता : मैं आपके आने का इंतजार कर रहा था आपके वित्तमंत्री जी आखिरी लाइन मैं खत्म कर रहा हूं बस।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं एक मिनट अलाउ कर रहा हूं।

श्री विजेंद्र गुप्ता : वित्तमंत्री जी, मैं एक मिनट सर, मैं तो 40 सैकंड में खत्म कर रहा हूं, एक मिनट भी नहीं। वित्तम ंत्री जी आप अगर इस सदन के समक्ष मैं सिर्फ इतना कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा उसके बाद अगर आपके पास जवाब हो मेरी इस बात का तो जरूर यहां रखिएगा और वो ये बात है कि वो प्रावधान तो मुझे दे दो, वो प्रावधान जैसे मैंने कहा है कि निजाम कानून से चलता है वो कानून और अगर कानून नहीं है। तो राम किशन ग्रेवाल को स्वर्गीय पूर्व सैनिक को जिन्होंने सुसाइड किया था, अगर मदद करना ही चाहते हो तो ये सदन कानून बनाने के लिए है अगर प्रावधान नहीं है आपके पास, तो फिर प्रावधान बना दो, प्रावधान बना दो, प्रावधान बना दो, धान्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : राजेश गुप्ता जी।

श्री सुखबीर सिंह दयाल : झूठ बोला सदन के सामने, किशन ग्रेवाल के मेटर में मैं वहीं था।

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद चाय टी के बाद।

श्री सुखबीर सिंह दलाल : एक मिनट के लिए बोल रहा हूं दिल्ली की सरकार ने मैं वहीं खड़ा था 20 लाख रूपये खट्टर साहब ने, उनके लिए

ऐलान किया, एक बच्चे की नौकरी का किया था। हमारे अरविंद केजरीवाल ने तो उसके एक दिन बाद ही दिया है इसलिए मुझे ये बात कर रहे हैं। क्या वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उनके लिए नियम अलग है या इस दिल्ली सरकार के लिए नियम अलग है। मैं यही बात पूछना चाहता हूं। उसी बात पे मैं नहीं था। धानकड़ साहब ने बात बोली।

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी।

श्री राजेश गुप्ता : अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, हालांक बहुत लेट दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धान्यवादौ बाद में भी बोलने के नुकसान ये थोड़े से ये होते हैं कि लगभग सारे प्वाइंट कवर हो जाते हैं। मेमरे से पहले वाले लोगों ने लगभग बहुत सारी बातें कर ली, लगभग सारी हो गई। आज से पहले जब दो तीन साल पहले से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और उससे पहले जो सरकारें थीं, तो हम अक्सर जब न्यूज पेपर में बजट के बारे में पढ़ते थे तो एक कॉलम आया करता था, क्या बढ़ा और क्या घटा जब ने धयान दिया होगा कि ये बढ़ गया, ये घट गया। हमें कई सारे पेपर हैं ये 4-5 पेपर मेरे पास में है किसी भी पेपर में ये नहीं लिखा हुआ कि क्या बढ़ा। सबमें एक ही चीज है कि क्या घटा। ये हिंदुस्तान टाइम्स है इसमें लिखा है : "Delhi budget keep focus on health care, education. true poor trust, दूसरा है Indian Express, Education Health Rule Common Man Budget." पंजाब केसरी लिखता है जी शिक्षा, स्वास्थ्य पर जोर टैक्स नो मोर! और दैनिक जागरण लिखताहै पहला आउटकम बजट, नया कर नहीं। ये सारे न्यूज पेपर कहीं न कहीं एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि दिल्ली की सरकार ने जो

बजट पेश किया, उसमें सिर्फ आम आदमी के बारे में सोचा गया। ये हिंदी का हिंदुस्तान है जिसमें मैट्रो, बसों और सड़कों के लिए 55 सौ....6 करोड़ तो लिखे ही हैं और लिखा है, ''नगर निगमों पर मेहरबान हुई दिल्ली सरकार'' पूरी तरीके से सारे के सारे न्यूज पेपर यही दिखाते हैं कि कहीं कुछ भी नहीं बढ़ा, एक पैसा भी कहीं नहीं बढ़ा और ऐसा नहीं है कि बजट के बीच में जो बजट होता है, उसके बीच में कहीं दो महीने पहले किसी पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए गए हों, जैसे कि केंद्र सरकार करती आई कि हर महीने कुछ न कुछ करते रहो, बढ़ाए जा ओ। ऐसा भी नहीं है कि जो एलपीजी सिलेंडर के रेट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वो कुछ बजट में नहीं आते। बीच में रेलवे के किराए बढ़ा दिए जाते हैं। (4.00) बजट का तो इंतजार ही नहीं किया इन्होंने सेंटर के अंदर लेकिन हमने पूरे एक साल के अंदर ये जो पिछले साल बजट पेश हुआ और इस साल हो रहा है, उसमें किसी भी चीज पर कोई पैसे, कहीं नहीं बढ़ाए गए। ना बीच में, ना बजट से। पिछली बार जब आदरणीय वित्तमंत्री जी ने बजट पेश किया और अगले दिन जब उस पर मैं बोल रहा था तो मैंने कहा था सर को याद होगा कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है नहीं तो चिरागों से लौट जा रही थी। सब इतनी मुकराहट के साथ में बजट पेश करते हैं, सिर्फ बजट मुस्कराहट उस वक्त नहीं होती जब वो बजट पेश करते हैं, सिर्फ बजट मुस्कराहट उस वक्त नहीं होती जब वो बजट पेश करते हैं बल्कि जब आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी बोल रहे थे तब भी आदरणीय वित्तमंत्री जी मुस्करा ही रहे थे, हां वो खुद भी मुस्कराते रहते हैं उनके बजट के बाद भी जनता मुस्कराती है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि केंद्र में जब बजट पेश होता है तो वो बजट पेश करते हुए भी दुखी से रहते हैं और जनता तो बहुत ही दुखी होती है उसके बाद। इस बार मैं

मुस्कराहट के ऊपर वित्तमंत्री जी के लिए कहना चाहता हूं कि

इस चेहरे की मुस्कराहट के दीवाने हजारों हैं,

इस मुस्कराहट के वाबस्ता मस्ताने हजारों है

और ये मैं अपनी सरकार के बारे में कहना चाहता हूं कि :

एक हम ही है जो आम आदमी की सुनते हैं,

कहने को दुनिया में सरकारें हजारों हैं।।

और आदरणीय विपक्ष के नेता जी आपके लिए भी मैं कहे देता हूं, क्योंकि आपने बजट के बाद में कहा कि ये जो आउटकम बजट है, ये तो फेल होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। तो इसमें सर दो लाइनों में कह देता हूं कि : इस शम्मे फिरोजां को आंधाी से डराते हो

इस शम्मे फिरोजां के परवाने हजारों हैं।।

सर आपने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी चीजें ऐसी कही कि जो वैसे तो आप रोज ही कहते रहते हैं। लेकिन दोनोंु सरकारों के बजट में आपने तुलना की होगी केंद्र सरकार का भी बजट अभी कुछ दिनों पहले आया था और अब हमारी सरकार का भी बजट आया है। तो आपने देखा, मुझे लगा नहीं कि आपने एक घंटे से आपने बहुत कुछ कहा लेकिन कुछ भी कांक्रिट निकल के नहीं आया उसके अंदर। कुछ समझ में तो मेमरे कम से कम आया नहीं, बाकी मुझे लग नहीं रहा ज्यादा लोगों की समझ में तो मेरे कम से कम आया नहीं, बाकी मुझे लग नहीं रहा ज्यादा लोगों की समझ में भी। लेकिन इसीलिए अध्यक्ष जी भी चले गए थे। जब आप उन्हें लगा कि बोर हो रहे

हैं शायद। ठीक है सर, जरूर मिलेंगे। आपने बहुत सारी चीजें रखीं, आपने स्कूल्स के लिए कहा कि सिर्फ बिल्डिंग से शायद स्कूल नहीं चलेंगे। उस पर वित्त मंत्री जी आपको ज्यादा जवाब देना बेहतर होगा, टॉयलेट्स की आपने बात करी जो डीडीए से परमिशन मिली है। मैं आपको बता दूं उसमें बहुत सारे केसिज भी लग रहे हैं तो मैं आपकी जरूर मदद चाहूंगा उसके अंदर कि मेरे यहां पर एक केस लगा है जिस वजह से वो रूक रहे हैं, उसमें वो जरूर देख लें। आपने कहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा होता रहता है, वो रूकता नहीं है और एमसीडी में सेलरी क्यों रूक रही थी, मुझे समझ में नहीं आई। आपने कहा सरकारें नहीं होती, तब भी मिल जाता है। तो वहां तो है, वहां तो सरकार है। तो वो कैसे रूक गया? मेरे सिर के ऊपर से ठीक है। लेकिन मुझे समझा देना ये बात। आपने कहा कि वेट घट गया, ये बात भी ठीक है। अब चक्कर ये हो गया सर जो स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी जो सब बिक रही थी ना, वो बिकनी बंद हो गई, नोटबंदी की वजह से। तो वेट तो घटेगा ही, घटेगा ना। अभी ऊपर से नीचे से, आप मुझे समझाना एक्चुली ऊपर से जो चीजें होती हैं, नीचे की बिल्कुल समझ में नहीं आती। मुझे टेबल के नीचे से जो एमसीडी में है ना ऊपर की तो शायद मैं फिर भी समझ लूं। तो वेट इसलिए घटा है सर, क्योंकि ना तो मकानों की रजिस्टरी हो रही है क्योंकि लोगों के पास में जो भी आपने नोटबंदी करी, ना गाड़ी बिक रही, ना स्कूटिर बिक रहे, ना कोई सामान बिक रहा है। इसलिए जो वेट घटा, वो घटा।

एक आपने कहा कि जो अनुसूचित जाति के उनके लिए हमने ज्यादा प्रावध ान नहीं किया, मैं आज तक नहीं समझ पाया आपने दुनियाभर की रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी जितने भी सबसे ज्यादा पिछड़े हुए लोग है अनुसूचित जाति से या

हमारे मुस्लिम भाई, ये जो सरकारी स्कूल है, ये हास्पिटल्स हैं, ये मौहल्ला क्लीनिक्स है, ये बस हैं। इन्हें सबसे ज्यादा सर, इस्तेमाल कौन करता है? ये वही लोग तो इस्तेमाल करते हैं। ये उन्हीं के लिए तो है। तो सारा बजट ही उनक लिए है। मेरा तो ये कहना है कि आप प्रावधान करो। मैं कहता हूं 48 हजार करोड़ ही उनके लिए है और किसके लिए हैं? बिल्कुल उन्हीं के लिए है। जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं। जो सबसे ज्यादा पिछड़े रह गए हैं, उन्हीं के लिए है। ये सारे के सारे स्कूल्स बना रहे हैं, उन्हीं के बच्चे सबसे ज्यादा उसमें पढ़ते हैं। ठीक है सर! आपके मुंह में घी शक्कर! हम साहूकार हो जाएं आपके जैसे। श्रमिकों के लिए आपने कल भी कहा था कि हमारे जो आम आदमी के जो बना हरे थे कैंटीन तो आपने कहा कि हमने चालूम नहीं करी है। लेकिन हमने तो जेसे अभी आपने कहा कि मिनिमम वेजिज इतने बढ़ा दिए कि वो कैंटीन में तो खा ही लेंगे दिन में लेकिन शाम में अगर अपने बच्चों के साथ में किसी रेस्टोरेंट में भी जाना चाहेंगे ना, तो जा सकते हैं इतने हमने मिनिमम वेजिज बढ़ा दिए हैं। मेरा यही कहना है सर, कि बजट के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। सर, आपके अपने थियेटर हैं। आपको क्या जरूरत है? और आपके घर में थियेटर है सर, आपको जरूरत कुछ नहीं है, और आप खुद एक्टर हैं। निजाम आपका है। वो डायरेक्टर है। आपको जरूरत क्या है सर, बताओ? और एडिटर आपके एलजी साहब थे। आपकी तो पूरी सबकी घर की खेती है।

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, चर्चा करें प्लीज।

श्री राजेश गुप्ता : सर, आपको उन चीजों की खैर जरूरत नहीं है, मेरा बजट के बारे में ये जरूर कहना है कि जब बजट इस तरीके से पेश किया

जाता है, हम पढ़ते हैं। हम भी उसको एक नजरिए से देखते हैं कि क्या कोई कमी तो नहीं हर गई है इसमें। हम भी वो बात करते हैं लेकिन यकीन मानिएगा, उसके अंदर से हम इतने सारे लोग बैठे हैं उसमें हम कमी ढूंढ नहीं पाते। हम समझने की कोशिश करते हैं कि तीन-चार दिन पहले जब हम मौहल्ले और नुक्कड़ में बैठा करते थे, जब हम आंदोलन किया करते थे तो हम लोग बात करते थे आपस में कि बजट होना कैसा चाहिए और बड़ा अजीब लगता है कि वित्त मंत्री जी हू-ब-हू आप बिल्कुल आप किताब दिखा रहे हो, आपका धान्यवाद। मैं चाहता हूं कि मीडियाकर्मी जरूर दिखा दें कि ये फोटो आपकी दिखाएं तो बहुत जो हम बातें करते थे, वित्त मंत्री जी हू-ब-हू वैसे ही बजट पेश कर देते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, बजट डबल हो जाए, हैल्थ में डेढ़ गुणा बढ़ जाए, बसों के किराए कम हो जाएं और अलग ही किस्म की इकॉनी है, जिसे हम बार-बार बात करते हैं कि टैक्स हम बढ़ाते नहीं, सब पर घटाए चले जाते है। व्यापारियों के हित के लए तोह म ही सोचते हैं। व्यापारी सरकार आपकी है, केंद्र में व्यापारी सरकार नहीं है व्यापारियों के लिए सरकार हमारी है कि टैक्स घटाया जाए और ज्यादा उन लोगों को सुविधाएं दी जाए और हमसे कभी कोई गलती हो जाए, जैसे पिछली बार हुई जूते में या कपड़े में, उसे अगले दिन हमने रोलबैकभी कर लिया। हमारी इतनल ईगो भी नहीं है। तो ये सरकार जैसे आम आदमी के लिए बनी है, सिर्फ आम आदमी के लिए सोचती है। जबक भी ये आता है कि आम आदमी सड़क पे जैसे कल भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर रोड पर जाओ और पांच लोगों से पूछो तो आपको हर 100 मीटर पर या तो कोई मौहल्ला क्लीनिक दिखा देगा, नही तो स्कूल की एक शानदार बिल्डिंग, जिसे देखकर ही आदमी की छाती चौड़ी हो जाए। उसको देखकर के सच में 56 इंच से भी चौड़ी हो

जाती है हमारी छाती। ऐसा स्कूल दिखा देगा और कुछ नही दिखेगा तो पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर रात को दो बजे भी निकलोगे तो रोड वैक्युम क्लीनिंग साफ हाते दिख जायेंगे। वो हरियाली दिखा देगा जो किसी बजट में पेश नहीं हो सकती कि हरियाली कितनी भरी है कैसी ट्रेनिंग होती है। एक-एक चीजें हर 100-200 मीटर की दूरी पर आपको कुछ न कुछ ऐसा दिखाई दे जाएगा कि जो दिल्ली सरकार उसमें करती चली जा रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है। मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो वित मंत्री जी से कहूंगा कि सर बहुत-बहुत धान्यवाद आप इसी तरीके से बजट पेश करते रहिए। मुझे सिर्फ एक दो चीजों के बारे में कहना है; एक तो कुछ व्यापारियों ने मुझे कल कहा था तो मैं उस पर कह देता हूं कि जो दाल की लिमिट है, अगरह म उसे बढ़ा सके तो जरूर उसे बढाएं। आदरणीय इमरान जी भी यहां बैठे हैं, मंत्री जी और एक जो आउटकम बजट आपने पेश किया है, जो एमएलए फंड है, इस पर भी एक आउटकम लगा दिया जाए सर। वैसे तो हमारी एमसीडी आ जाएगी एक महीने के बाद में लेकिन अदरवाइज इनसे दो-दो साल के तो ब्याज वसूल कर लो। जो 4-4 करोड़ रूपये एमसीडी में लेके बैठे रहे, उससे भी कई सड़कें और गलियां बन जाएंगी तो ये भी अब की बार में आउटकम हम उसे जरूर तय करें। जगदीश प्रधान जी, आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है तो मैं आपकी तरफ से भी वित मंत्री के लिए आखिरी दो लाइनें कह देता हूं। क्योंकि आपक यहां पे बहुत कम होते हैं स्कूल्स के काम बहुत होते हैं, आप खुद ही बताते हैं हमें। आपके लिए कह देता हू ं : ''तुम यूं ही अगर साथ चलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। बहुत-बहुत धान्यवाद सर।

अध्यक्ष महोदय : टी-ब्रेक अभी मेम्बर्स लॉज में चाय की व्यवस्था है सभी वहां आमंत्रित हैं हम ठीक 4.40 बजे यहां पर उपस्थित होंगे आधो घंटे के बाद। बहुत-बहुत धान्यवाद। (4.40)

सदन् अपराह्न 4.45 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) *पीठासीन हुए।*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धान्यवाद कि आपने मुझे बजट के डिस्कसन में हिस्सा लेने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, जब मैं माननीय विजेंद्र गुप्ता जी का भाषण सुन रहा था तो उन्होंने, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल इस बात के ऊपर कि नॉन प्लान क्या होता है, प्लान क्या होता है, बड़ी उन्होंने विस्तार से आलोचना की थी। जब माननीय उपमुख्यमंत्री ने, वित्त मंत्री महोदय ने इस बार उसको हटाकरके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के रूप में बजट को पेश किया। उन्होंने इसका ध न्यवाद तक नहीं दिया। चूंकि मुझे किसी ने बताया क्षेत्र के अंदर कभी, जो मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं वहां कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप अपना सिर भी काट के दे दो न, तो बोलेंगे ये तिरछा कटा है भाई साहब। थोड़ा सीधा काट दें। तो ये बजट अगर अच्छा है, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। विजेंद्र जी, आप तनिक थोड़ा कभी-कभी प्रशंसा भी कर दिया करें। माना कि विपक्ष है लेकिन विपक्ष का काम कंस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिस्टिसिजम क्याकरें ल ेकिन आपकी मजी। अध्यक्ष महोदय, तो बड़ी बात मेरे साथियों ने बहुत विस्तार से चर्चा की और बहुत ज्ञानवर्द्धन किया सदन का आपके माध

यम से। लेकिन दो बड़ी बात, अध्यक्ष महोदय, जो कि अन्डरलाईनिंग इस बजट को, एक कि आम आमदी को एम्पावर करना। कोई भी सरकार नहीं चहाती कि आम आदमी मजबूत बनें, आम आदमी शिक्षित बनें। आम आदमी की गरीबी दूर हो। आम आदमी की स्वास्थ्य की समस्याएं दूर हों। आम आदमी को पानी की सहूलियत मिलें। कोई सरकार नहीं चाहतीं। ये सरकारचूंकि जिस कारण से हम आये हैं, और जो हमें पर लेके आये हैं, वो पीड़ा वहीं है कि इस देश का आम आदमी मजबूत बनें। एम्पावर्ड बने। मैं वित्त मंत्री महोदय कोधान्यवाद देना चाहता हूं कि जो इसका ये नाम अगर मैं कह दूं एम्पावरमेंट बजट। Empowerment budget, this budget is to empower each and every individual. चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो गृहणी हो, चाहे वो कोई भी हो। दलित हो, माइनिरटी हो, कोई भी हो, हर आदमी को एम्पावर करने वाला ये बजट है और ये बहुत बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय। मैं इसके लिए उनका धान्यवाद करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बड़ी बात एक-एक पैसे का हिसाब-किताब जिस तरह से इन्होंने इस बजट को पेश किया और इसका नाम दिया आउटकम बजट। माननीय वित्त मंत्री ने कहा और बड़ी सुखद है कि वित्त मंत्री ही शिक्षा मंत्री है। तो ये जो एक्सीलेंट कम्बिनेशन है, उसके कारण इस बजट की जो विशेषताएं उभर के आयी हैं, उसका धान्यवाद मैं करता हूं माननीय वित्त मंत्री को। आउटकम बजट, हिंदुस्तान के अंदर ये पहली चीज आयी है। भई, हर सरकारें बजट को एलोकेट करती हैं कि इस काम का बीस करोड़, उस काम का पचास करोड़ और उस काम का सौ करोड़। वहां छः सौ करोड़, वहां पांच सौ करोड़ लेकिन वो पांच सौ करोड़ खर्चा कैसे होगा। उसके ऊपर कंट्रोल,

उस मशीन क जरिये जो आपरेशन होने थे, उस मशीन क जरिये जो जांच होनी थी, उस पर कंट्रोल कि वो मशीन इफेक्टिव तरीके से काम कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही है। बहुत बड़ी बात है। हम पूरे सदन को इन दो बड़ी बातों के लिए कि हमने, माननीय वित्त मंत्री ने आम आदमी को मजबूत करने के लिए जो बजट बनाया और जो मैंने पिछले हफ्ते सदन के अंदर भाषण में कहा था कि सरकारें चाहतीं है कि आम आदमी मुर्गा बन के रह जाये। जब मर्जी, उसके पंख निकाल लो। जब मर्जी, उसको लहूलुहान कर दो। जब मर्जी, उसके पास दाना लेके चले जाओ लेकिन ये बजट हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा बजट है कि जो चाहता है कि आम आदमी एम्पावर्ड हो। उसके पास सोचने की शक्ति, सवाल पूछने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति, इन सभी शक्तियों को उनके अंदर मि श्रण हो। ये बहुत बड़ी बात है, अध्यक्ष महोदय। इस तरह के नये कीर्तिमान इस बजट के अंदर आये और जो विजेंद्र गुप्ता जी यहां बोल रहे हों ले किन इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें! ये सरकार तो बिल्कुल हावी है और इतनी हावी है कि वो सारे काम जो ये नहीं कर पाये जिसके कारण आम आदमी मुर्गा बनता रहा आज तक। आम आदमी को नोचते रहे आज तक। वो सारे काम शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिये, वो सारे काम, उन सारे साधानों के जरिये जो आम आदमी को एम्पावर करता है, उसकी आलोचना करें तो कैसे करें। ऐसा बजट जिसके अंदर टैक्स तो है ही नहीं, टैक्स बढ़ाने की बात तो छोड़िये, इन्होंने घटा दिया। टैक्स घटाया और काम बढ़ाया। ये बड़ा गजब का कम्बिनेशन निकला अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, पेज नं. 11 में जो मैंने पहले बात कही थी, उस पर बाकायदा कहा गया है कि नॉन प्लान और प्लान पढ़ दूं उनके लिए, वो तो

पढ़ नहीं पाये। उनके लिए पढ़ के बता देता हूं। सदन को भ अवगत करा देता हूं। कहा है, ''As I have already stated that the budget estimates for the 2017-18 will not be in the form of Plan and non Plan hence discarding the earlier practice our govt has prepared the budget of 2017-18 in two major categories that is revenue and capital expenditure."

अध्यक्ष महोदय, हममें कई साथियों ने एफआइटार की कापी देखी होगी। (4.50)

श्री सोमनाथ भारती (जारी) : अध्यक्ष महोदय, हममें से कई साथियों ने एफआईआर की कॉपी देखी होगी। एफआईआर में पढ़ते हैं तो एफआईआर के अंदर पता नहीं कौन सी भाषा लिखी रहती है, किसी को समझ में नहीं आता। मैं आज तक यह समझ नही पाया कि उस भाषा को कैरी करना क्यों जरूरी है। इसी तरह से बजट के अंदर प्लान, नॉन प्लान करके आम आदमी को जो दुविधा में डालता है, आज मैं वित्त मंत्री साहब को धान्यवाद देता हूं कि आपने देश को एक दिशा दी है। आपका बहुत-बहुत धान्यवाद इसके लिए।

अध्यक्ष महोदय, ईमानदारी के नये आयाम कि 31 मार्च के पहले सभी को अपने बजट खत्म करने की होड़ लगी रहती है कि बजट खत्म करें। लेकिन इस सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह के प्रयास किए, जितना हमारा बजलट था, उसमें से एक-एक पैसे का भरपूर उपयोग किया। यह ऐसा बजट है Which can be called easily a budget which is accountable to every ordinary citizen of Delhi.

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं उनका धान्यवाद करता हूं। इसमें जो इन्होंने कहा है कि आउटकम बजट होगा। अब आउटकम बजट जो पैसा हमने डेडीकेट किया है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के ऊपर उसका उपयोग कैसे होगा। मानीय मोदी जी कहते हैं वो बड़े इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवी है, लेकिन यहां एक सरकार है, उसने बाकायदा कहा कि इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी के माधयम से ऐसा सॉफ्टवेयर बनायेंगे, वो सॉफ्टवेयर हरेक पैसे की देख-भाल करेगा कि कौन सा पैसा कहां गया, किस पैसे का उपयोग किया। आईटी के इतने अच्छे उपयोग के लिए, मैं वित्त मंत्री का धान्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इनफेक्ट यह बजट बहुत, इनके जो शब्द यूज किए हैं कई लाइनें इसमें बड़ी प्यारी हैं चूंकि माननीय वित्त मंत्री ने पिछली बार भी कहा था कि एक ऐसा बजट जब पिछली बार पेश किया था आपने तो वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हमारे लिए इलैक्शन मेनिफेस्टो कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, हमारे लिए इलैक्शन मेनिफेस्टो एक कॉट्रैचुअल ऑलिगेशन है और आज इसबारी जब मैं बजट पढ़ रहा था, जब मैं सुन रहा था आपका बजट, आपने फिर उसको दोहराया है कि यह बजट हमारे इलैक्शन मेनिफेस्टोज के अनुसार उसको पूरा करने का तंत्र है और यह जो जरिया निकला है, उसमें बाकायदा कहा, ''I am presenting the budget which have been prepred to effectively utilize the hard earned money of the citizens of Delhi for the implementation of various Governments schemes and programmes, peoples money for the welfare of people." यह एक ऐसा भाव देता है मन में, कि हम सिर्फ कुछ समय के लिए कस्टोडियन हैं इसके, हम इसके मालिक नहीं है। हर पैसे पर जनता का

अधिकार है, जनता के लिए कर रहे हैं और इस भाव से कर रहे हैं कि जनता ने बड़े आदर से, बड़ी आशा से हमें यह आदेश दिया कि इस पैसे के जरिये उनका भला कर पायें। मैं उनका तहेदिल से धान्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़ी अच्छी सी लाइन आयी, कहा, "Success fo any government means that the people should be fearless." बहुत बड़ी बात है, जो सरकारें कह रही है, ''People should be fearless and feel secure inthe field of education and health etc." कहा, "Creating such opportunities and environment for the people is to enable them to have good education and lead healthy life." मतलब मुर्गा बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश के अंदर सरकारों द्वारा, उस पर रोक लगे।

अध्यक्ष महोदय, आप कुछ भी उठा लें। एजुकेशन उठा लें, स्किन एजुकेशन उठा लें, ट्रांसपोर्ट, वाटर इन सब के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर देख लीजिए, वाटर सप्लाई के अंदर देख लीजिए, इस तरह से बीस लाख कनैक्शन्स में से साढ़े बारह लाख कनैक्शन्स को पानी मुफ्त मिल रहा है। यह कोई छोटी-मोटी बात है? उसके साथ-साथ 178 करोड़ रूपये का रेवेन्यू जनरेशन भी हुआ है, फायदा पहुंचा है। यह किसी भी इकॉनॉमिस्ट को, किसी भी एक्सपार्ट को सकते में डाल देने वाले फैक्ट्स हैं। आज की तारीख में, जब मैं आज सुबह पार्क में गया था तो कहा कि यह मैजिक क्या है, तुम लोग कैसे कर पा रहे हो यह? चूंकि हम लोग अभी भी अपनी गलियों में, अपने मोहलों में बडे आम तरीके से चलते हैं, आम तरीके सेक रहते हैं तरो लोग बड़ी आशा से अपवने पास आते है और ऐसी बातें शेयर करते हैं, इससे लगता है कि उनका अपना

है। कुछ तो लोग पूछ रहे थे मुझसे आज। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर काफी इकॉनेमिस्ट रहते हैं, कि कैसे कर पाते हो यह। मैंने कहा कि मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा, माननीय मनीष जी से तो वो समझा देंगे आपको किस तरीके से करते हैं लेकिन उसकी एकमात्र लाइन यह है कि सरकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो ईमानदारी के तरीके से काम कर रही है, यह बहुत बड़ी मिसाल बनकर आ गया है। ईमानदार और ईमानदारी, इस सरकार की दो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और उसी का सारा परिणाम यह बजट बन कर आया है।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से स्कीम्स के ऊपर स्कीम्स आई हैं लेकिन जो बड़ी एक दिल छू लेने वाली बात है कि आपने जो नाइट शेल्टर बनाया है, नाइट शेल्टर के अंदर जो आपने स्किल्ड डेवलपमेंट कोर्सेज बनाये, आप उस आदमी को केवल डिग्निटी नहीं दे रहे हो, उसको इंडिपेंडेंट बनाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हो। आज के पहले मुझे याद है एज अ लॉयर में ऐपियर हुआ था कोर्ट के अंदर 2009 में नाइट शेल्टर्स के लिए, उस वक्त तो यह चर्चा चलती थी कि इसकी कूलर दे दो, इसको पीने का पानी दे दो। आज तो चर्चा कई स्टेजेज ऊपर चली गई कि सुविधाएं तो दो ही, उनको डिग्निफाईड लाइफ तो दो ही, लेकिन उनको ऐसे हुनर सिखाओ जिससे कि वो नाइट शेल्टर्स कर आम आदमी की तरह, इज्जत से, अपने घर में रह सकें। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं वित्त मंत्री महोदय को।

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने एक ऐसे भविष्य की परिकल्पना की, जिसके अंदर शिक्षा सिर्फ शिक्षा न रह जाये। एक आदमी जब वो डिग्री लेकर निकले तो उसके पास ऐसे स्किल्स भी हों कि वो रेडिली ए म्पलॉएबल हों। जब वो डिग्री ल ेकर निकले तो उसके पास एक ऐसा हुनर भी

हो जिसके जरिये वो इंडसट्रीज के अंदर और भी कारखानों क अंदर वो रेडिलजी एम्पलॉएबल बने।

अध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपने 280 वाले में पानी के बारे में कुछ कहा था तो मुझे कुछ कहने के साथ-साथ में मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि माननीय जल मंत्री यहां बैठे हैं इनके जो अचीवमेंट्स हैं, वो अनपैरलल हैं। 309 कालोनियों के अंदर, चूंकि मुझे फैक्ट्स बाद में मालूम पड़े, 15 साल के कांग्रेस के शासन काल में सिर्फ 18 कालोनियों के अंदर उन्होंने नयी वाटर लाइन वहां पर डाली थी और सिर्फ दो साल में माननीय जल मंत्री के नेतृत्व में जल बोर्ड ने 309 कालोनियों के अंदर लाइनें डालीं, यह बहुत बड़ी बात है।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि येक अनपैरलल चीजें हैं, यह समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि यह हो कैसे रहा है! लेकिन पीछे एक ही है हमारा नेतृत्व अरविंद केजरीवाल साहब का नेतृत्व। अरविंद केजरीवाल साहब नेक हम सब को इस तरीके की सीख दी है कि अपने आपको मंत्री हो, एमएलए हो, दांव पर लगा कर के जनता की सेवा करनी है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 900 एमजीडी पानी चूंकि सरीकार जब ईमानदारी होती है तो इस तरीके की बातें होती हैं। माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 900 एमजीडी पानी दिल्ली में है और अगर दो करोड़ लोग हमारे दिल्ली म ें हैं तो कितना निकल कर आता है 300 लीटर पानी पर पर्सन पर-डे पैदा होता है। अब व्यवस्था यह है कि वो पानी जा कहां रहा है, वो पानी चोरी हो

रहा है, वो पानी लीक हो रहा है। वो पानी टैंकर माफिया ले जा रहा है, इसके लिए सरकार बड़ी कटिबद्धता से काम कर रही है, मैं सलाम करता हूं, जज्बे को, कि इतना बड़ा टास्क कि 300 लीटर पानी पर-डे पर पर्सन किमल जाये तो दिल्ली एक ऐसा शहर बन कर उभरेगा, पूरे हिंदुस्तान में एक तमॉडल सिटी बनकर उभरेगा और चूंकि माननीय मोदी जी सिर्फ ठेका ले रहे हैं एनडीएमसी एरिया का। माननीय मोदी जी ने कहा है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे लेकिन दिल्ली का वो हिस्सा है जो कि एनडीएसमी में है तो मोदी जी आपको हम आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी सरकार पूरी दिल्ली को आपके पहले, आप एनडीएमसी क्षेत्र को बना पायें, उसके पहले स्मार्ट सिटी बनाकर दिखायेगी, यह हम इस सद न से वायदा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, स्कीम्स देखिये, 'वॉक द लाइन' एक इन्होंने स्कीम चलाया। 24x7 वाटर सप्लाई जो हमारे क्षेत्र से शुरू हुआ, हमने कपिल जी, कल यह कहा था कि जब यह 24x7 वाटर सप्लाई दो कालोनियों में कर दिया (5.00) अब हर तरफ से डिमांड आ रही है तो वहां तो ये 2 4 घंटे मिल रहा है। हमें तो कम से कम 6-7 घंटे दो, ये हमने कहा था। मुझे लगता है कि इसमें आपको थोड़ा सा लेकर के चलना चाहिए लेकिन ये हमारी पीड़ा थी मैंने आपको बयान किया और ये जो आपने यमुना प्रोजेक्ट, जो यमुना प्रोजेक्ट पर आपने शुरूआत की है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं आप। आपने बड़ा अच्छा काम किया है। Delhi as a slum free city. मैं चेलेंज करता हूं दोनों पार्टियों को कांग्रेस भाजपा को अपने कोई भी मेनिफेस्टो उठा कर दिखा दें, अपना कोई भी बजट का भाषण उठाकर दिखा दें, अपनी कोई प्लानिंग उठाकर दिखा दे, अगर ये दिख जाए कि दिल्ली उन्होंने कभी

स्लम फ्री सिटी के बारे में उन्होंने कभी सोचा तो मैं उनको नतमस्तक हो जाऊंगा लेकिन आज पहली बारये आया है कि Delhi as a slum free city और ये कहने की बातें नहीं हैं स्लम फ्री सिटी, वो कर के दिखा रहे हैं और साथ-साथ मतें ये नहीं कह रहे कि उजाड़ देंगे। बाकियो को ये कह रहे हैं कि हम सबको रिहैब्लिटेट करेंगे और हमारे पास आंकड़े हैं 5 हजार स्लम ड्वैलर्स को इन्होंने रिलोकेट किया है ये बहुत बड़ी बात है! दिल्ली जिस दिन स्लम फ्री सिटी हो जाएगी और हमारे सारे भाई बंधु जो स्लम्स में रह रहे है, उनको रहने का साधान मिलेगा। यह सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं मानवता के लिए भी। मानवता धान्यवाद करेगी पूरे सरकार का कि जिस तरह से आज भाई-बहन स्लम्स में रहने को मजबूर हो रहे हैं, वहां पर कितना भी अच्छा कर दीजिये, वो बहुत अच्छा नहीं बन सकता। तो स्लम्स को जब रिलोकेट करेंगे, जब उनको रिलोकेट करके वन रूम सेट देंगे और उनकी पूरी जरूरतों का धयान रखेंगे, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कदम होगा। अध्यक्ष, महोदय इसके लिए मैं धान्यवाद देता हूं। दूसरा, मतलब ये सुनकर भी हैरानी होती है कि दिल्ली के अंदर ओपन डेफेरशन अभी भी हो रहा है। ये दिल्ली है, भारत की राजधानी, जहां कि अभी भी ओपन डेफकेशन हो रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं वित्तमंत्री महोदय को कि दिल्ली को ओपन डेफरेशन फ्री सिटी बनाने के लिए जो उन्होंने जज्बा दिखाया है, इसके अंदर ये बहुत बड़ी बात है, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, चूंकि एक पानी की व्यवस्था हमने पहले की बात की, ये विलायती कीक्कर है क्यों? कि सरकार के किसी अधिाकारी ने सोचा ही नहीं कि विलायती कीक्कर अगर दिल्ली के जल के स्तर को खत्म कर

रहा है तो इसके लिए हम कुछ उपयोग करें। मैं इस फॉरसाइट के लिए, इस विचार के लिए, इस प्लानिंग के लिए कि विलायती कीक्कर दिल्ली उसे दूर हो और कहा कि 10 साल में हो जाएगा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : कंन्क्लूड कीजिए सोमनाथ जी, अब।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने मुझे बिल्कुल आखिर में कहा है, उसके बाद तो मंत्रीगण बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, 15 मिनट हो गये हैं पूरे।

श्री सोमनाथ भारती : मैं 5 मिनट और लूंगा, फिर खत्म कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही ज्यादा एक तरह से धाक्का लगा, वो कह रहे हैं कि सैनिक जी, हरियाणा का था, इसीलिए उन्होंने दिया, हरियाणा वालों ने नहीं दिया। अरे! भाई सैनिक पूरे देश का होता है। सैनिक चाहे हरियाणा का रहने वाला हो, सैथ्नक चाहे पंजाब का रहने वाला हो, सैनिक चाहे हरियाणा का रहने वाला हो, सैनिक चाहे पंजाब का रहने वाला हो, सैनिक चाहे दिल्ली का रहने वाला हो, सैनिक तो पूरे देश का है। अगर इस सरकार ने सैनिक को सम्मानित करने का फैसला लिया है तो इसका तो आपको स्वागत करना चाहिए था। जो बॉर्डर पर खड़ा है, वो देखेगा क्या कि मैं तो सिर्फ पंजाब का हूं, मैं तो सिर्फ हरियाणा का हूं?

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस मापदंड से जो हमने फैसला किया था सैनिक को सम्मानित करने का, उसको इन्होंने गिरा दिया। मैं तो विजेंद्र गुप्ता जी के जरिए कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को बोलें,

''भई, सैनिक पूरे देश का है और जो दिल्ली सरकार ने फैसला किया है उनको सम्मान देने का, तो करने देना चाहिए।'' अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे कि मिनिमम वेजेज एप्लीकेशन में अभी विजेंद्र ग ुप्ता जी ने अपने भाषण में कहा कि जेल नहीं भेजा किसी को। क्या ि मनमिम वेजेज का किसी ने वॉयलेट किया, तो जेल भेजा क्या? अरे! भई, जेल कैसे भेजें? दिल्ली पु लिस आपके पास है, एंटीकरप्शन ब्रांच आपके पास है, सीबीआई आपके पास है। एक बार देके तो देखो, एक बार देके देखो एंटीकरप्शन ब्रांच, कौन-कौन जेल जाएंगे! एक बार देके तो देखो। हम बताएंगे पुलिस का सदुपयोग करेंगे, दुरूपयोग नहीं करेंगे। मैं आपको आज यहां से आश्वासन देता हूं। अगर आपने लत नहीं किया है। अगर आपने, पंजाब आ रहा है, कल आ रहा है पंजाब अब देखना। मैं इस सदन की अनुमति से एक बात कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। पंजाब मैं पुलिस हमारे पास होगी, लेकिन पंजाब में पुलिस का सदुपयोग करेंगे, दुरूपयोग नहीं करेंगे, आपकी तरह। गलत तो नहीं कह रहा? भई, पंजाब में पुलिस का हम सदुपयोग करेंगे लेकिन ये सोच लेना के भई, पॉलीटिकल फ्रेंडशिप, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, अब कंन्क्लूड करिये, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : पहले चर्चा होती थी कि कांग्रेस वाले भाजपा के साथ, भाजपा वाले कांग्रेस के साथ विजेंद्र गुप्ता जी ये पॉलीटिकल फ्रैंडशिप आपके जरिए बोल रहा हूं, कहीं डायरेक्ट न ले लें वो, वो फिर खड़े हो जाएंगे कि पॉलीटिकल फ्रैंडशिप, हमारे यहां नहीं होता। हम तो अपने भाई के भी नहीं हैं। अगर वो गलत करेगा तो, अगर गलत करेगा तो हम अपने भाई के भी नहीं हैं। आप छोड़ दीजिए इस बात को।

....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा लोन रिक्वरी आप एमसीडी से कर रहे हैं। आप काहे को चिंता कर रहे हो? ये तो 2017-18 का बजट है न? एक महीने बाद एमसीडी अपने पास आ जाएगी। आप क्यों चिंता कर रहे हो उसके लिए? भई, एमसीडी के अंदर जो सुधार कार्य लाना है, आप एक ख्याल रखना।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारती : एमसीडी जिस वक्त हमारे पास आ एगी, ये एमसीडी को मैंने पिछली बार भी कहा था कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट आपने बनाया और मोसट करेक्ट डिपार्टमेंट हम बनाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, अब ये कंक्लूड कर दीजिए, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष जी, आखिर में एक बात चूंकि माननीय वित्तमंत्री जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये बात कर रहे थे, भई, एमसीसीएसटी पर खर्च नहीं किया, ये नहीं कया, अरे! भई, अस्पताल क्या एमसीएसटी जानता है? अस्पताल, स्कूल, रोड्स, पानी इतने लाखों करोड़ खर्च हो रहे हैं, तो सब पर खर्च हो रहा है।

....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारती : देखिये आप तो, अब आप तो आप हैं। आप कहते हैं कि बिजली भी मुसलमान भी है। पता नहीं क्या-क्या करते रहते हो। आप कहते हो कि बिजली की जात हो गई, धार्म हो गया, तो ये आपकी मानसिकता है। आप हमको मत नापो उससे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में, चूंकि माननीय वित्तमंत्री बैठे हैं, एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चूंकि आपके माधयम से करना चाहता हूं दिल्ली के अंदर हर राज्य का आदमी रहता है केरला का भी है, तमिलनाडु का भी है, पंजाब का भी है, बिहार का भी है, सबका है तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक दिन हर स्टेट का मनाया जाए जैसे केरला दिवस हो जाए, बिहार दिवस हो जाए, तमिलनाडु दिवस हो जाए और उस दिन को हम दिल्ली में रहने वाले केरला के हर लोगों को आमंत्रित करें और एक अच्छा सा डेडीकेटेड प्रोग्राम करें जिससे कि हम सबको फायदा पहुंचेगा, पूरे देश को फायदा पह ुंचेगा और एक भाईचारे की भावना सबमें फैलेगी। केरला का कल्चर सब सीख पाएंगे, बिहार का कल्चर सब सीख पाएंगे तो माननीय वित्तमंत्री अपने भाषण में अगर इस पद पर शब्द बोल पाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, एक और....

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, आपने एक बात बोली थी बस, सोमनाथ जी, ये क्रम बंद कीजिए, अब प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : एक लाइन और, अध्यक्ष महोदय, गुजरात दिवस मना लेंगे हम, भई गुजरात दिवस मनाएंगे हम दिल्ली के अंदर, इसी साल मनाएंगे। साथी कह रहे हैं पंजाब दिवस तो कल मन रहा है, गुजरात दिवस भी मनेगा इसी साल मनेगा। गुजरात दिवस भी यहीं मनेगा और ये जब दिवस मनेगा तो कहीं आपको तकलीफ न हो, इसलिए आप पहले ही साथ आ जाओ हमारे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी ने यहां पर जो उन्होंने बजट पेश किया, उसमें एक चीज की कमी रह गई, अगर वो उसको कर पाएं। लॉ,

लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है देश के अंदर, उसके ऊपर हमारा तो कंट्रोल है नहीं, लेकिन जो कोर्ट्स के जरिए हम लॉ डिस्पेन्सेशन सिस्टम जो करते हैं कोर्ट्स को और स्ट्रैंग्थन करें, उनको और इक्विप करें, उसके ऊपर थोड़ा बजट में प्रावधान अगर ला पाएं बाद में जब रिवाइज्ड एस्टिमेट ले के आएं तो बड़ा अच्छा रहेगा मैं इन शब्दों के साथ और चूंकि उन्होंने कहा कि भई आपने एजुकेशन पर कम खर्च किया। अरे! भई, आज देखें it is much beyoyn proportional expenditure on education, health care हमारी पापुलेशन डेढ़ करोड़ की है (5.10)

अध्यक्ष महोदय : चलिये, सोमनाथ जी हो गया।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, हमारी पॉपुलेशन ही डेढ़ करोड़ की है, आपकी मधयप्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, छत्तीसगढ़ की पोपुलेशन को अगर देख लें, हल समझ में नहीं आ या हमको, तो उसके माधयम से देखें कि प्रपोशनली हमारा जो बजट का एलोकेशन है, ऐजुकेशन हेल्थ केयर पर, वो कहीं ज्यादा है। तो आप सबको माननीय वित्तमंत्री महोदय को, हमारे पूरे साथियों को,ह मारी पूरी पार्टी को, हमारे नेतृत्व को, मैं पूरे देश को ऐसा बजट, मैं बड़े दिल के कहता हूं, मैंने काफी बजट पढ़े हैं, ऐसा बजट आज तक इतिहास में कभी नहीं देखा। मैं वित्तमंत्री महोदय को इस बजट के लिये सलाम करता हूं कि आपने आम आदमी को एम्पॉवर करने की ठानी है, आपको बहुत-बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक।

अध्यक्ष महोदय : श्री कपिल मिश्रा जीं

श्री कपिल मिश्रा (जल एवं पर्यटन मंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। मैं सबसे पहले इस बजट के बारे में ये कहना चाहता हूं कि अब तक जन लोगों ने सूटकेस की राजनीति की है और सूटकेस में ही बजट भी दिखाया और सूटकेस से ही देश को चलाया, उनको, झोले से निकला ये बजट ह जम नहीं होने वाला। ना हजम होने वाला, ना समझ में आने वाला। ये तो झोले से निकला है और झोले वाले मनीष जी, उनके झोसे से क्या-क्या निकला! बजट की तारीफ करते हुए हैरानी भी होती है, हैरत भी होती है। शायद मनीष सिसौदिया जी ये काम कर सकते हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान में आजादी के बाद से, झोले से ये जादू निकलने का काम कोई और नहीं कर पाया आज तक। विपक्ष के कई लोगों ने बड़ी कमियां निकलाने की कोशिश की।

....(व्यवधान)

श्री कपिल मिश्रा : मैं तो इज्जत दे रहा था साहब।

....(व्यवधान)

श्री कपिल मिश्रा : मैं बहुवचन में बोल रहा हूं आप एक वचन में सुनना चाहते हो। गुप्ता जी को बड़ा दर्द हुआ इस बजट से। तो मैं ये कहना चाहता हूं गुप्ता जी के शेरों के जवाब में एक शेर :

जो गिनने दाग हमारे, हमारे घर पर आयें

वो अपने घर से आईना भी देख कर आयें।

एक प्रतिक्रिया आई बजट बड़ा निराशाजनक है। यही प्रतिक्रिया है गुप्ता जी? अध्यक्ष महोदय, आपके माधयम से पूछना चाहता हूं कि आप अकेले ही निराश हो कि पूरी भाजपा निराश है?

....(व्यवधान)

श्री कपिल मिश्रा : निराशाजनक भी है और आपके लिये हतोत्साहित करने वाला भी है।

श्री महेंद्र गोयल : अरे! कपिल भाई, ये बाहर कह रहे थे, बहुत बढ़िया बजट दिया है।

....(व्यवधान)

श्री कपिल मिश्रा : बात बाहर कहने की तो है ही नहीं। गोयल साहब, बाहर तो विरोधा कर भी सकते हैं।

....(व्यवधान)

श्री विजेंद्र गुप्ता : ये उस समय परांठे खिला रहे थे।

श्री कपिल मिश्रा : मैं यही तो कह रहा हूं।

....(व्यवधान)

श्री कपिल मिश्रा : नहीं, ये बिल्कुल सही बोला इन्होंने। जो पकाता है और खिलाता है, घर के बाहर हो या घर के अंदर, उसके सामने इस बजट की बुराई नहीं कर सकते। जिसको चूल्हे की समझ है और चौके की समझ है, वो सब इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। घर जाकर खाना खाना है तो घर में तारीफ आप भी करोगे।

....(व्यवधान)

श्री कपिल मिश्रा : देश का पहला आउठ कम बजट, यानि केवल बिल्डिंग बन के खड़ी नहीं होगी, उस बिल्डिंग के अंदर कितनी जनता का फायदा होना है, मशीन आई है तो उससे कितने लोगों को इलाज होना है, उसका मसौदा भी बजट में रखने की तैयारी है और देश के इतिहास में पहली बार! अब भाजपा की हालत ये है कि उनको आउट कम में ना आउट समझ आ रहाना कम समझ आ रहा तो कहते हैं चलो, कुछ भी हो कुछ तो कम है। इस बजट में चाहे आउटकम ही सही। ऐसा कोई बजट बनाता है सर? मनीष जी, ये कौन सा तरीका है बजट बनाने का? मतलब ये सत्तर साल वालों की सब की राजनीति बंद करने की तैयारी है। ना कोई टैक्स लगाया, ना कोई टैक्स बढ़ाया, उल्टा कम करते चले गये और उसक बाद भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दिये जा रहे हैं। सर, लुटा दोगे क्या सरकार गरीबों के लिये? ये क्या तरीका है बजट बनाने का? पसंद आ रहा है, लेकिन हैरत है! हैरानी है! सरप्राईज्ड हैं! और वो सभी लोग जो अपने आपको अर्थव्यवस्था का, इकॉनॉमी का विशेषज्ञ मानते थे। ये कहत थे कि इकॉनॉमी ऐसे ही चलती है, अर्थव्यवस्था ऐसे ही चलती है। टैक्स पेयर से पैसा लेना पड़ेगा, उसके बादही तो वि कास हा ेगा। क्या कर दिया सर, ये आपने! मतलब सोचने पर मजबूर करने वाला दो साल में आठ हजार कमरे सरकारी स्कूलों में बना दिये और ग ुप्ता जी कहते हैं कुछ कमरे ही तो बने हैं। जा के देखो उन कमरों मेमं, उन कमरों में जा कर देखो, उन बच्चों की आंखों में झांक कर देखो, उनके माता-पिता से मिलकर देखो, सुनकर देखो, उन टीचरों से, जो हिंदुस्तान से बाहर जाकर ट्रैनिंग लेकर आये हैं। हवाई जहाज में एक आदमी पूरी दुनिया घूम ले उससे देश काभला नहीं होता। लेकिन टीचर एक बार देश के बाहर जाकर कैम्ब्रिज में, हावर्ड में सीखकर आ जोय तो शिक्षा व्यवस्था बदल जाये। व्यवस्था परिवर्तन

होता है और आठ ह जार कमरे तो दो साल में बनाये और दस हजार कमरे इस साल बनाने का वायदा कर रहे हैं। हमारे टाईम पर,सर, एक सरकारी स्कूल टैंट में अगर चला था तो बच्चा पहली से लेकर बारहवीं पास हो जाये, स्कूल टैंट में ही चलता था। एक पाली का स्कूल फिर दो पाली का स्कूल फिर तीन पाली का स्कूल फिर चार पाली का स्कूल हो गया इसी शहर के अंदर। मेरे यहां चल रहा है, प्रधान जी के यहां चल रहा है, चल रहा है, चलेगा नहीं, लंबे समय तक। अब प्रधान जी ने बड़ी मजेदार बात बोली। प्रधान जी ने कहा छठीक क्षा में लड़का आ जाता है, उसे पढ़ना नहीं अ ाता। छठी कक्षा में आ कैसे जाता है? पांचवीं तक के स्कूल तो नगर निगम ही चलाता है। आ कैसे जाता है वो छठी कक्षा में? दस साल से बीजेपी बैठी है नगर निमग में, यानि दस साल पहले जो बच्चा पहली कक्षा में आया होगा, नगर निगम के, पढ़ना नहीं आता था छठी में, उसे दसवीं पास करा के भेज रहे हैं आज। नगर निगम के स्कूलों के बारे में आपका बयान सच्चाई से भरा हुआ है। बदल देंगे, आने वाली समय में। लेकिन ये बात सच है। ये आपने बिल्कुल स्टीक बात बोली कि प्राइमरी हेल्थ, ऐजुकेशन सिस्टम कोलेप्स्ड है। वहां नहीं सिखाया जा पा रहा है; पढ़ना लिखना। वो जिम्मेदारी भी यहीां पर आकर होती है फिर सिक्सथ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ क्लास में और ये जो नो डिटेंशन पालिसी कि कोई फेल ही नहीं होगा, करते चले जाओ पास। आप ही सब लोग बैठे थे, सर, जब ये स चीजें पास की जा रही थीं और केवल स्कूल नहीं बना रहे, उसके बाद उसमें स्किलरी यानि पढ़ो और राजगार की तैयारी भी करो। अपने पैर पर खड़े होने की तैयारी करो और कैसा स्किल? वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर! टैक्स नहीं लगायेंगे, लेकिन वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर बना के देंगे। मुझे हैरानी है, इस बजट से, व्यक्तिगत तौर पर हैरान हूं कि ये कैसा बजट और

किसके लिये स्किल सेंटर बना रहे हैं? नौ वोकेशनल कालेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी का एक कैम्पस अलग से और कुल मिलाकर लगभग बारह नये कालेज पांच साल में बीस कालेज खोलने थे, टोटल जो हमने वादा किया था और दो साल में बारह तैयार करके, मैं तो सिर्फ इतना ही हता हूं मनीष जी से, भई, जरा धीरे गाड़ी हांको। ये तो बीस की बात थी, यहां हद पार हो रहा है ये।

....(व्यवधान)

श्री कपिल मिश्रा : गुप्ता जी, आपकी तरफ देखूं तो आप को दर्द और मनीष जी को बोलूं तो आप को दर्द।

....(व्यवधान)

श्री कपिल मिश्रा : आपने एक बात बोली आपने बोला, ''निन्दक नियरे राखिये....

....(व्यवधान)

श्री कपिल मिश्रा : हमने कहां दूर रखा हुआ था? लेकिन वो विचारधारा की लाईन आपको क्रॉस करनी होगी, जो मुश्किल है आपके लिये।

झुग्गी वालों को फलैट दे दिये झुग्गी में व्यक्ति रह रहा है फलैट दे दिये। न पुलिस आई, न लाठी चली, न गोली चली, न आंदोलन हुआ, न धारना हुआ, न प्रदर्शन हुआ, न तमाशा हुआ शहर में और लोग झुग्गी से उठकर फलैट के अंदर रहने चले गये।

....(व्यवधान)

श्री कपिल मिश्रा : हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ कहीं। हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं हुआ।

....(व्यवधान)

श्री कपिल मिश्रा : अरे! गुप्ता जी, साहब हमने दो साल में झुग्गी वालों को घर दे दिया। ये बीस साल में रामलला को छत नहीं दे पाय और हद तो तब है, हद तो ये है कि रैन बसेरे में भी स्किन सैंटर। ये थोड़ा ज्यादा हो गया मनीष जी। मतलब, जिस वर्ग के लोगों ने नकार दिया, लोग मुड़कर देखने के लिए तैयार नहीं, कभी पूजा पाठ के दिन जाकर दान दक्षिणा दे के और अदरवाईज सड़क से निकलते हुए यही सोचते थे कि ये लोग सड़क पर हैं, इन्हें उठाकर फेंक क्यों नहीं दिया जाता? (5.20) ज्यादातर शहर वालों की ये मानसिकता हो जाती है कि ये शहर की गंदगी है। ये दिखनी नहीं चाहिए, आंखों से छिपी रहनी चाहिए। उसके लिए न केवल 'रैन बसेरे' बनाए जा रहे हैं बल्कि 'रैन बसेरे' में रोजगार की भी तैयारी की जा रही है। सलाम है, सलाम है ऐसे बजट को और ऐसे बजट की सोच को!

एजुकेशन के कमर्शियलाइजेशन पर बात हुई। ये अब तक जो सरकारें चलीं, उसमें शिक्षा में क्या होता था; बड़ा स्कूल बनवा लो; कोई पब्लिक, कोई मिनिस्टर का अपना स्कूल बन जाएगा, किसी एमएलए का अपना स्कूल बन जाएगा, किसी और उसमें इतना जरूर होगा कि एक फोन पर मंत्री के, एमएलए के एडमिशन हो जाएंगे दो-चार। लेकिन उनकी फीस न बढ़े और सरकारी स्कूलों में स्वीमिंग पुल और लिफ्ट लगने लग जाए, मुझे लगता है, हिंदुस्तान में आजादी के बाद अभी लोगों ने सपना भी नहीं देखा था इस चीज का, जो दिल्ली के अंदर करके दिखाया जा रहा है और बजट में जिसका प्रावधान रखा जा रहा है।

हैल्थ की अगर हम बात करें। मौहल्ला क्लिनिक अब तो दिल्ली के कोने-कोने में दिखने लगी हैं और मुझे पता है कि किसकी गाड़ी मुड़ती है और मौहल्ला क्लिनिक दिखने पर किस-किस के सीने पर सांप लौटता है, वो नजर आता है, वो दिल में जो दर्द होता है कि ये बन कैसे गई! ये रोड के कोने पर यहां! ये यहां ये यहां! और उसके बाद वापस तुरंत हड़बड़ाते हुए अपने दफ्तर आते हैं और फिर एमसीडी को फोन, डीडीए को फोन, रोको इस काम को, इसको रोको, उसको रोको। आपकी छाती पर मूंग दलने आए थे, मौहल्ला क्लिनिक मूंग दल रही है छाती पर। तैयार हैं पर शहर के अंदर मौहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, मिनी हॉस्पीटल और खेल, मजाक! जिसको बीजेपी और कांग्रेस को समझ ही नहीं आया। पहले बोला हम सारी दवाई मुफ्त देंगे, दवाई मुफ्त हो गई, सारे सरकारी अस्पताल में, मौहल्ला क्लिनिक में। उसके बाद कहते हैं टैस्ट भी मुफ्त करा लो। फिर एमआरआई और सीटी स्कैन भी मुफ्त करा लो और कल वो बोल रहे हैं, ''ऑपरेशन भी, अगर सरकारी में डेट नहीं मिलती, तो वो भी प्राइवेट में जाकर करा लो।'' उसके बाद एक और आई कि कोई घायल हो जाए तो उसका भी इलाज प्राइवेट में करा लो, वो भी मुफ्त। सत्येंद्र जैन जी को देखकर मुझे ऐसाल गता है कि कुछ बीजेपी कांग्रेस के स्वस्थ लोग भी सोचते होंगे, दो-चार दिन अस्पताल होकर आ जाएं। आमूल-चूल परिवर्तन। पांच करोड़ में बनने वाली डिस्पेंसरी, वो बीस लाख की मौहल्ला क्लिनिक बनकर तैयार हो रही है। तीन सौ करोड़ में बनने वाला फ्लाई ओवर, दो सौ करोड़ में तैयार हो रहा है। इतना पैसा बचाकर कहां ले जाओगे मनीष जी!

श्री विजेंद्र गुप्ता : यहीं बात मैं कह देता ना, बुरा मान जाते!

श्री कपिल मिश्रा : आप तो घर में नहीं कह सकते, यहां क्या कहां कहोगे? पानी की पाईप लाइन, अनअथोराइज्ड कॉलोनी में डाली जा रही है। इस साल 200 नई कॉलोनी में और पाईप लाइन डालने का टारगेट और उसका फंड भी दिया गया 2,100 करोड़ जल बोर्ड को जो दिया गया है, ये बदलाव है! आखिर क्यों ए क बना हुआ प्लांट होता था और चलता नहीं था। जो प्लांट बना दे, लेकिन चलाए नहीं, उनको ये राजनीति समझ में नहीं आती कि पाईप लाइन कॉलोनी में डाली क्यों जा रही है! क्योंकि जब प्लांट नहीं चलता तो धांधा चलता है। जब टैंकर चलता है तो धांधा चलता है और जब पाईप लाइन बिछ जाती है तो वो धांधा बंद हो जाता है और यही राजनीति इनको कभी समझ में नहीं आई। उसके लिए अलग से जल बोर्ड को जो फंड दिया गया है, उसके लिए जो प्रावधान किए गए, सलाम उन सभी सोच को और जिस प्रकार से ये नए तरीके का बजट इस बार दिया गया है। यमुना में नालों के बारे में, गंदगी के बारे में बहुत हंगामा हुआ। सालों से ये चर्चा होती रहती है, लेकिन हमेशा ये होता था; इसका फंड कौन देगा? इसका फंड कौन देगा? केंद्र सरकार देगी कि नेशनल क्लीन गंगा मिशन देगा? दो साल से तो हम खुद उमा भारती जी, नितिन गडकरी जी, वैंकेया नायडू जी, ऐसा कोई दरवाजा नहीं है इस देश का, जो खटखटाया न हो, जिसके आगे जाकर मांगा ना हो। सब ने कहा, ''बहुत अच्छी योजना है, शानदार योजना है, आशीर्वाद ले जाओ, पैसा नहीं है।'' हर बार, लगातार दो साल से, मनीष जी से मिलकर ये प्रार्थना की फिर समझ में आया कि शुरूआत करनी है तो बेशक दिल्ली की किटी से पैसा देना पड़े, जो बनता नहीं था देना, तब भी एक बार शुरूआत की जाए इस परियोजना की। आज आठ किलोमीटर की सप्लीमेंटरी ड्रेन के लिए अलग से फंड दिया गया है इस बजट के अंदर। पहली बार है ये और

इसी यमुना की केवल गंदगी, नेशनल क्लीन गंगा मिशन में बीस हजार करोड़ रूपये रखा है, अभी तक खर्च नहीं हुआ। उसमें से पैसा, दो साल हो गए हैं, गंगा कब क्लीन होगी, इसकापता नहीं है लेकिन यमुना के लिए काम शुरू कर दिया गया है और दिल्ली में यमुना केवल गंदी नहीं है। यमुना दिल्ली में साफ भी है लेकिन यमुना के नाम पर दुकानदारी चलाने वालों को कभी साफ यमुना दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। बाईस किलोमीटर की साफ यमुना दिल्ली से बहकर निकलती है उसको दिखाने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया को पहली बार अगर उठाई गई है तो इस बजट में उठाई गई है, रिवर फंड डेवलपमेंट फंड के लिए सौ करोड़ रूपये अलग से रखे गए हैं।

सोलर एनर्जी के लिए फंड रखा गया है। नगर निगमों का जो फंड है, उसमें किस प्रकार से उनसे मुआवजा नहीं लेना, टैक्स नहीं लेना, उसके बाद भी फंड देना है, उसका प्रावधान रखा गया है। जो नॉर्थ ईस्ट की फ्लाईट में क्योंकि वो वोट से जुड़ा मुद्दा नहीं है, कोई सरकार को करने की जरूरत नहीं है उसको कि 25% को 01% पर लेकर आ जाए। मुझे लगता है पूरा सदन जोरदार तालियों से स्वागत करे उस निर्णय का, क्योंकि वो असली देशभक्ति वाला कदम है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाला कदम है। देश को जोड़ने वाला, दिल्ली में बैठी कोई राज्य सरकार पूरे देश को जोड़ने वाला कोई कदम उठाए अपने बजट में, ये भी शायद पहली बार हो रहा है, जसमें एक वोट का फायदा नहीं होना है। तो बस, मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

गुप्ता जी की दो-चार बातें थी जिनको जरूर जवाब देना बनता है। एक तो उन्होंने नोटबंदी के ऊपर बताया कि नोटबंदी से रैवन्यू कुछ राज्यों का बढ़ गया। रैवन्यू बढ़ाने के लिए लाए थे नोटबंदी? नोटबंदी रैवन्यू बढ़ाने के लिए

लाए थे? नोटबंदी, भैया काला धान कितना पकडा गया है, ये बता दो, आतंकवाद कितना बंद हुआ, ये बता दो, भ्रष्टाचार कितना बंद हुआ ये बता दो और अगर ये नहीं बता सकते, नोटबंदी के नाम पर वोट मांग लेते ना। एक स्टेट के, एक स्पीच में, एक बीजपी के नेता ने नोटबंदी के नाम पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं दिखाई है।

श्री विजेंद्र गुप्ता : हम राजनीति नहीं करते।

श्री कपिल मिश्रा : आप ज्यादा दिन कर भी नहीं पाओगे। आप राजनीति करते हो या न करते हो, ज्यादा दिन कर नहीं पाओगे। अब ये पानी और बिजली की सब्सिडी के ऊपर, गुप्ता जी बोल रहे थे। दो तरह की राजनीति है या तो नौ हजार करोड़ रूपया माल्या को दे दो या फिर सारी दिल्ली के पानी बिजली के बिल माफ कर दो। एक ही चीज हो सकती है।

एम्पलायर को पेनेल्टी लगाई कि नहीं लगाई, मिनिमेम वेज के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया। अपना ही इसी विधान सभा के अंदर उठाए हुए सवाल को भूल गए। डीटीडीसी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर ने मिनिमेम वेज नहीं दिया, उसी समय उसका लाइसेंस खत्म किया गया, ब्लैक लिस्ट करा गया, एफआईर दर्ज कराई गई और सारे एम्पलाईज को डीटीडीसी ने खुद हॉयर करके, उनको पूरा पैसा देना शुरू किया। आपका खुद का उठाया हुआ मामला इस सदन के अंदर है जो आप भूल गए।

श्री विजेंद्र गुप्ता : उनको फिर भी नहीं मिला, यही तो बता रहा था।

श्री कपिल मिश्रा : नहीं बता रहे थे, आप ये?

श्री विजेंद्र गुप्ता : नहीं मिला।

श्री कपिल मिश्रा : विजेंद्र जी, प्लीज। कपिल जी, जरा करिए, कन्कलूड करिए।

श्री कपिल मिश्रा : बस एक मिनट। 'स्मार्ट सिटी' की बात आ रही थी कि एनडीएमसी को 'स्मार्ट सिटी' रख रहे हैं बाकी दिल्ली को 'स्मार्ट सिटी' नहीं, बाकी दिल्ली तो कितनी स्मार्ट है, उसने दो साल पहले ही बता दिया था और 'सियासत में मोहब्बत होती थी' बड़ी अच्छी बात बोली। वाह रे आशिक मस्ताने! 'सियासत में मोहब्बत होती थी' तुम्हारी, मोहब्बत ही तो खत्म करने आए थे। उस मोहब्बत का एक आशिक जीरो सीट पर बैठा है, एक तीन पर बैठा और बाकी अब पंजाब में समझा देंगे आपकी मोहब्बत। कल बीजेपी के एक प्रवक्ता चैनल पर बोल रहे थे कि जो वोट अकाली को नहीं गया,वो आम आदमी पार्टी को नहीं, कांग्रेस को जाएगा। मैंने कहा 'गिद्धों के मनाने से गाय नहीं मरा करती है।' तो कुल मिलाकर एक शानदार, ऐतिहासिक, जनता को समझने वाला, जनता से जुड़ने वाला, आम आदमी का, संवेदनशील बजट मनीष सिसौदिया जी ने पेश किया है, एक बार पुनः इस देश की इकॉनॉमी किस दिशा में जानी चाहिए, बुनियादी व्यवस्थाएं कैसे बदलनी चाहिए, बहुत-बहुत बधाई मनीष जी को और पूरी सरकार को और सदन को। थैंक्यू जय हिंद सर।

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्येंद्र जैन जी, माननीय मंत्री जी महोदय। (5.30)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येंद्र जैन) : आदरनणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माधयम से बजट पर बोलने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी को धान्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी ओर

से जितनी भी डिमांड थी, सभी डिपार्टमेंटस की ओर से, कहीं पर भी उन्होंने अपनी कैंची नहीं चलाई और एक दो जगह तो क्या हुआ कि जितना मांगा था, उससे ज्यादा ही मिला। देखिए, मैट्रो के लिए! मैट्रो के लिए जो थोड़ा पैसा या फंड देना था, इश्यू आ रहा था कि पूरा पैसा दे पायेंगे इस बजट में या नहीं दे पायेंगे, इस बजट में। तो हमने जितना पैसा मांगा था 1100 करोड़ रूपया, पूरा का पूरा दिया फेज-4 के लिए जितना शेयर देना था, उसके लिए वित्तमंत्री जी ने अपना शेयर दे दिया। मतलब पैसे की वजह से किसी भी बजट में....जैसे कि पॉवर के लिए सब्सिडी मांगी 1600 करोड़, पिछली बार 1400 करोड़ थी। तो एक बार यदि इसको क्वैश्चन ये दिया गया और फिर हमें पूरा पैसा दिया गया और दिल्ली देश के अंदर ऐसा राज्य बना, जहां पर बिजली के दो साल से रेट भी नहीं बढ़ाये गये और आधो रेट किएगए और वो बजट के अंदर प्रोविजन भी रहा, इसीलिए हम आगे बढ़ा पा रहे हैं और दिल्ली के लोगों को 400 यूनिट तक बिजली आधो रेट पर दे पा रहे हैं। इसी तरह से जैसे हमारे इनफ्रास्ट्रकचर प्रोजेक्टस हैं, बारापुला फेज थ्री है, नया बन रहा है, सिग्नेचर ब्रिज से लेकर भोपुरा बॉर्डर तक, पूरा सिग्लेनल फ्री कॉरीडोर बना रहे हैं। इसी तरह ईस्ट वेस्ट कॉरीडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरीडोर है, सभी प्रोजेक्टस के लिए, जो डिफरैंट डिफरैंट स्टेजेज पर हैं, सब के लिए पैसा आबंटित किया गया और किसी के लिए भी ये नहीं कहा गया कि भई, पैसे की वजह से काम को रोक लीजिए। ये जरूर है कि कुछ एप्रूवल्स की वजह से चीजों में डिले होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए इस्ट वेस्ट कॉरीडोर जो है, आनंद बिहार, आईएसबीटी से लेकर यूपी बॉर्डर तक पूरा एलिवेटेड रोड बनाने का प्रोविजन है, हमने कंसलटैंट नियुक्त कर लिए हैं और उसका भी

यूटी पैक मैं जमा करा दिया है। तो जैसे ही उसकी मंजूरी मिलेगी, तो उसके लिए जल्द से जल्द हम काम कर पायंगे।

दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने स्कूलों में जो अभी विजेंद्र जी कह रहे थे कि कमरे बनाने से क्या होता है। पहले मकान बनाना पड़ता है, आश्रय बनाना शिक्षा मंत्री जी का काम है, कमरे हमने बना दिये हैं और उसके बिना अभी तक टैंटों में जो कपिल जी कह रहे थे, त्रासदी तो मैं उनकी महसूस कर सकता हूं, टैंटों के स्कूल में पढ़े थे, तो जैसे उन्हेंने कहा अगर मौका मिलता दुबारा उसी स्कूल में तो वे पढ़ने के लिए तैयार हैं। अब उन बच्चों से पूछियेगा, उनके मां-बाप से पूछियेगा जिनके बच्चे पहली क्लास के पढ़ते-पढ़ते, दसवीं क्लास, ग्यारहवीं क्लास में पहुंच गये हैं और उन्हें अचानक उनको बिलकुल बहुत खूबसूरत अच्छी बिल्डिंग मिली, लैबोरेटरी मिल गई है, लाइब्रेरी मिल गई है, सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर मिल गया है और मैं जो जगदीश जी का ध ान्यवाद भी करूंगा वो तो इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि मेरे यहां भी इतने ज्यादा कमरे बन रहे हैं, उन्होंने तारीफ की कि कमरे बनाये जा रहे हैं, मैं उसकी तारीफ करता हूं, इसका मतलब बन रहे हैं तो अच्छी बात है। दूसरी बात साथ-साथ मैं ये कहना चाहूंगा दिल्ली सरकार ने 8 हजार कमरे बनाये हैं पिछले समय के अंदर, उसी दौरान देश के अंदर 29 ओर भी राज्य सरकारें हैं, सबने मिल के नहीं बनाये। सारी सरकारों ने मिल क नहीं बन ाये। ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले सब ने इकट्ठे हो के भी इतने कमरे नहीं बनाये और ये हते हैं कि हमने काम नहीं किया। अरे! काम तो इसको कहते हैं, जो काम आपने 70 साल में नहीं किया, उतना काम हमने 2 साल में करके दिखा दिया और आगे 10 हजार कमरे, पहले हमें 8 हजार कमरे बनाने में करीब 2 साल लगे हैं, 10 हजार कमरे हम आपको अगले बजट से पहले

बना के दिखाएंगे, मैं इसका वादा सदन से करता हूं।

टॉएलेट्स, खुले मैं शौच की समस्या दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली देश की राजधानी है, 8 हजार शौचालय हमने बना दिये है और 6 हजार टॉयलेट्स के लिए बजट में आवंटन किया गया है, इस साल के जून तक बन जाएंगे और अगले साल के लिये भी टारगेट रखा गया है ताकि हम जल्द से जल्द खुले में शौच से दिल्ली को 100 परसैंट मुक्त कर सकें और ये इसी से संभव हुआ कि बजट के अंदर जो भी जरूरी चीजें थी, उनके लिए पैसे की कमी बिल्कुल नहीं रखी गई।

एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस के ऊपर बहुत राजनीति भी होती अनोथराइज कालोनिज। अनोथराइज कालोनिज के लिये अभी भी बहुत सारी अनोथराइज कालोनिज में सड़कें बन रही है, नालियां बन रही हैं, सारा काम चल रहा है, बहुत सारी जगह चल रहा है। हमारे बहुत सारे साथी यहां बैठे हैं। 8 सौ करोड़ रूपये बजट के अंदर अलग से दिया गया है उसके लिये मैं बहुत-बहुत धान्यवाद करना चाहूंगा कि अनोथराइज कालोनिज के डेवलपमैंट के लिये इस साल के बजट में 8 सौ करोड़ रूपया दिया गया है और मुझे वायदा किया गया है कि अगर ये पैसा खर्च हो गया तो और भी दे देंगे। हां, 905 करोड़ ठीक कर देता हूं। अक्चुअली में मैंने आठ सौ ही मांगा था तो उन्होंने 905 कर दिया, इसलिये मुझे पता नहीं लगा। तो हमने जो भी, जिस भी क्षेत्र के अंदर जितना भी पैसा मांगा, वो हमें दिया गया।

मैं अब आपको थोड़ा सा हैल्थ के बारे में जो कुछ इशूज हैं, थोड़ा-थोड़ा बताना चाहूंगा। मोहल्ला क्लीनिकस की घोषणा लास्ट बजट में की गई थी और एक हजार मोहल्ला क्लीनिकस बनाने का टारगेट रखा गया था जिसमें 110

थे, कल एक ओर स्टार्ट हो गया और इसत रह 111 हो गये हैं आज शायद आज भी हो गया 112 हो गये। वो डॉयनिमिक है हर रोज चेंज होगा, हर रोज एक-दो, एक-दो बढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ा दु:खद ये रहा कि मोहल्ला क्लीनिकस का जो बजट था, पायलेट बजट में 100 बनाये गये हैं उसके बाद उसको रूकवाने की पूरी साजिशें की गई और उसक अंदर, कांग्रेस और बीजेपी ने मिल कर बड़े कंसटेटली तरीके से उसको रूकवाने के लिए तरीके-तरीके से तोड़ने के नोटिस दिये गये बहुत सारी जगह पर। और मैंने तो तीन दिन पहले भी कहा था। विजेंद्र गुप्ता जी सड़क के किनारे सीनियर सिटिजन के लिये वाचनालय बना रहे हैं, उसका मैं सबके सामने समर्थन करता हूं, कृपया वो भी क बारी मोहल्ला क्लीनिक का समर्थन कर दें। उसी सड़क पर वो बनाना है, उसी सड़क पर वो बनना है। तो मुझे लगता है, इन्होंने मिलके ये कसम खाई थी कि मोहल्ला क्लीनिक बनने नहीं देना है। फिर भी अब उनकी अप्रूवल मिल चुकी है और आने वाले कुछ समय के अंदर, सर, आप एक बारी कह दीजिये, हम समर्थन करते हैं, सड़क के किनारे बनाने पर हम समर्थन करते हैं, अभी खड़े होके कह दीजिये। सर जी, खड़े हो के हां तो कर दो। तो एक हजार मोहल्ला क्लीनिक जल्द से जल्द बना दिये जाएंगे। सभी मोहल्ला क्लीनिक के अंदर डॉक्टर्स की सर्विसिज मुफ्त होती है वहां पर 212 टैस्ट किये जाते हैं, दवाईयां मिलती है, कई इन्नोवेटिवस आइडियाज को इम्पलीमेंट किया जा रहा है। जितनी भी इन्ट्रीज हैं, टैबलेट पर की जाती हैं, पर्ची हाथ से नहीं बनाई जाती, सारा हमारे पास में रिकॉर्ड होता है। दस जगह पर हमने मैडिसन वैंडिग मशीनें लगाई है देश में पहली बारी लगी है और मैं नेता विपक्ष की जानकारी के लिए बता दूं अब केंद्र सरकार ने भी अपने आदेश दिये हैं कि जल्द से जल्दी कसो कॉपी करके पूरे देश में लगाया जाये। नड्डा साहब ने

आदेश दिये हैं, पूरे देश में लगाया जाये। हम दस जगह लगा चुके हैं उसको ट्राई कर चुके हैं। पॉलेक्लीनिकस बनाए जा रहे हैं, 23 पॉली क्लीनिक स्टार्ट हो चुके हैं और 150 पॉलीक्लीनिक बनाने का हमारा टारगेट है। आशा करते हैं कि इस साल के अंत मतक इस फाइनैंशियल इधार के अंदर सारे के सारे पॉलीक्लीनिक तैयार हो जाएंगे।

हॉस्पिटलस के अंदर बैडस! हमने जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पीटलस हैं, उन सभी को डीडीएन कर लिया है उसको डिजाईन तैयार हो चुके है, अस्टीमेट बन चुके है, टैंडर्स तैयार हो चुके हैं बिल्कुल एडवांस स्टेज के ऊपर काम है। तो 10 हजार बैड को 20 हजार बैड में कन्वर्ट करने की तैयारी हो चुकी है साथ ही साथ नये अस्पतालों के अंदर 5 हजार बैड बनाये जा रहे हैं। मैं आपको शेड्यूल बताना चाहूंगा दिसम्बर, 2017 तक हमारे 2900 बैड्स तक 4700 बैड आ जाएंगे। 15 हजार बेड्स, वित्त मंत्री महोदय ने 10 हजार बोला था, ये 1 5 हजार तक की उम्मीदउ है तो पांच हजार वो है जो जून, 19 तक जाएगा तो ये सारा शैड्यूल हमने बता दिया है। एक इसमें खासियत ये है कि पहले हॉस्पिटल में एक बैड बनाने का खर्चा इनकी आशिकी जब चलती थी आपसमें, तब आता था एक करोड़ रूपया। दो सौ बेड का अस्पताल 200 करोड़ में बनता था, अब उसकी कॉस्ट घटाकर और उससे अच्छा बनाकर, थर्ड पार्टी असेसमैंट कराएंगे, इन्टरनैशनल कम्पनी से कराएंगे, उनको चैक कराएंगे कि पहले क्या बनता था और अब क्या बनाया गया है और आज भी केंद्रे सरकार के जितने भी प्रोजैक्ट चल रहे हैं, एमसीडी के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सबके अंदर कॉस्ट एक करोड़ रूपये से लेकर डेढ़ करोड़ रूपये प्रति बेड आ रही है जिसको कि हमने कम करके, नये हॉस्पिटलस में 25 लाख और जिनमें रैनोवेशन कर रहे हैं, उसमें 10-15 लाख रूपये प्रति

बेड के हिसाब से कॉस्ट को कम कर दिया है। दिल्ली सरकार के पास जो हम 10 हजार को 25 हजार पर लेकर जा रहे हैं, अभी एमरजेंसी और आईसीयू के अंदर लगभग हजार बेड हैं, अस्पताल में एडमिट करने के लिये सभी माननीय सदस्य जो बार-बार कहते हैं, एमरजेंसी के अंदर जाना होता है। आपके पास 10 हजार बेड है और 10 हजार बेड में से एक हजार बेड ऐसे हैं, जो एमरजैंसी के लिये आईसीयू के लिये अवेलेबल है बाकी हमारी जनरल सर्विसिज के लिये हैं। दिल्ली स रकारर ने जो अब टारगेट रखा है, इन 1 हजार बेडस को 10 हजार बेड में कनवर्ट करेंगे ताकि एमरजेंसी में किसी को दिक्कत न हो। आज 125 वैंटिलेटर्स दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में हमने स्टार्ट कर दिये हैं, एलएनजेपी के अंदर 35, पंत के अंदर 33, जीटीबी में 30, अलग-अलग अस्पतालों में 125 वैंटिलेटर्स स्टार्ट कर दिये गये हैं और मुझे लगता है ये दिल्ली में ही नहीं, देश के अंदर सबसे बड़ा कदम, मतलब किसी भी प्राइवेट, गवर्नमेंट के अस्पतालों में 1 25 वेंटीलेटर्स किसी ने भी नहीं लगाये होंगे आज तक, जो हमने कर के दिखा दिया, कर चुके।

महिलाओं के लिए जो हमारे एमसीएस बेड होते हैं, मदर एंड चाइल् ड केयर बेडस होते हैं, अभी हमारे सभी अस्पतालों में लगभग 3 हजार बेड हैं, उसके प्रति हम कमिटेड हैं, उन 3 हजार बेडस को बढ़ाकर हम 7500 हजार बेड करने जा रहे हैं ताकि किसी को भी उसके लिए कोई दिक्कत ना आये।

आउटकम बजट की बात लोगों को समझ नहीं आ रही, कुछ विपक्षी लोग, आउटकम क्या होता है, उसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। लास्ट ईयर दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलस में, डिस्पैंसरीज में सब जगह मिलाकर तीन करोड़ ओपीडी थी, तीन करोड़ लोगों को देखा गया, इस साल में चार करोड़ लोगों को देखा

गया। This is called outcome. कि हमने जितना पैसा दिया, उस पैसे से क्या किया। उसका काम कैसे किया। तो तीन करोड़ लोगोंं को या चार करोड़ लोगों को देखा गया और एडमिशन, जिन पेसेंटस को एडमिट किया गया वो भी 25 परसैंट ज्यादा लोगों को एडमिट किया गया है। this is called outcome. तो आउटकम कैसे होगा, वो मैं बताना चाहूंगा।

आम आदमी कैंटीन की बात हुई थी, आम आदमी कैंटीन का एक पॉयलेट प्रोजेक्ट एलएनएच हॉस्पीटल में स्टार्ट कर दिया गया है। कैटस एम्बूलेंस, हमने दिल्ली के अंदर सौ से ज्यादा नई कैटस एम्बूलेंस इस साल में हमने जोड़ दी हैं। अब देश के अंदर सबसे मॉडर्न हमारे पास एम्बूलेंस सिस्टम दिल्ली के अंदर अवेलेबल है, वो बना चुके हैं। जितने भी हॉस्पिटलस हैं, सारे हैल्थ सिस्टम को हम कम्प्यूटराईज कर रहे हैं। सौ प्रतिशत कम्प्यूटराईजेशन का टारगेट है, हैल्थ कार्ड दिल्ली के सभी नागरिकों के लिये बनाने के काम में प्रगति चल रही है ताकि सभी लोगों का हैल्थ कार्ड बनाया जा सके। उनको अपना हैल्थ डाटा लेके घुमना ना पड़े।

मोहल्ला क्लीनिकस के अंदर सबसे पहले, बहुत ही जल्द एक दो महीने के अंदर सबके हैल्थ कार्ड बना दिये जायेंगे। उसके बाद भी लोगों को इसमें एक्सटेंड किया जायेगा और यूनिवर्सल हैलथ इन्शोरेंस, दिल्ली के सभी नागरिकों के लिये हैल्थ इन्शोरेंस का, पिछली बार भी जिक्र हुआ था। (5.40) फिर वही बात है कि हमारी जो 400 फाईलों को ऊपर ले जाकर रखा गया था, उसके अंदर वो फाईल भी थी। परंतु इसको हम समझते हैं कि जल्द जल्द हम इसको कर दुंगे। आउट कम की बात में, मैं एक दो एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। मोहल्ला क्लीनिक के अंदर हमारा डेटा है। उसके अंदर 80 प्रतिशत

महिलाएं और बच्चे दिखाने के लिए आते हैं। जबकि हमारे अस्पतालों में ऐसा नहीं है। इसका मतलब हमने जो महिला स्वास्थ्य के प्रति बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा आउटकम है कि जो मोहल्ला क्लीनिक, आबादी में, उनके मोहल्ले के अंदर खुल रहा है, तो वो जाकर दिखा सकते हैं। अदरवाइज हॉस्पिटल के अंदर वो आउटकम निकल ही नहीं सकता, अगर हम हॉथ्स्पटल परह ी रहते तो उस आउटकम ये बार-बार....और मुझे लगता है हर तीन महीने में या छः महीने में इसको रिव्यू किया जाएगा और इसके अंदर देखना पड़ेगा कि क्या आउटकम निकल रहा है। अभी दिल्ली सरकार ने हेल्थ के क्षेत्र में कुछ नई स्कीम्स स्टार्ट की हैं। एक तो एमआरआई, सीटी स्कैन, कैटस्कैन, मैमोग्राफी, जितने भी महंगे-महंगे टेस्ट हैं, ये सभी टैस्ट पिछले साल एक फरवरी, 2016 को मुख्य मंत्री के आदेश पर सभी टैस्ट, सभी दवाइयां दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मुफ्त कर दी गई थीं, ये भी मुफ्त कर दिये गये थे। परंतु मुफ्त करने की वजह से लाइनें बहुत लंबी हो गई, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एमआरआई है। एमआरआई अगर आप एम्स में कराते हैं तो वहां पर तीन हजार रूपये ल ेकर पांच हजार रूपनये तक लगते हैं और आपको एक साल से दो साल का समय मिलता है। अब हमारे पंत होस्पिटल में भी क्योंकि मुफ्त हो गया, तो वहां पर दो-दो, तीन-तीन साल का एमआरआई का टाइम लगने लगा। तो इस स्कीम को हमने रिवाईज करके प्राईवेट 21 लाख के अंदर दिल्ली सरकार के 30 हॉस्पिटल्स एंड 23 पॉलीक्लीनिक्स से आप लिखवाइएगा और प्राईवेट में जाकर आप करा लिजिएगा, तो ऐसा दिल्ली सरकार ने किया है। इसके अंदर एक एडिशन और है। 48 होस्पिटल्स भी हैं प्राईवेट हॉस्पिटल हैं, जहां पर एमआरआई, सीटी स्कैन या बड़े-बड़े इमेजिंग की सुविध ा उपलब्धा है। आप 48 होस्पिटल्स से भी करा सकते हैं। इसको पहले ही

एक्सटेंड किया गया है। तो अब 69 जगह से करा सकते हैं। सारी दिल्ली के अंदर फैली हुई है। आप दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल या पॉलीक्लीनक से लिखवाइएगा और वहां पर जाकर करा लीजिएगा, मुफ्त में होता है। इसी तरीके से ओपरेशन है। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में अगर जाते हैं और कोई गंभीर बीमारी है। डॉक्टर साहब आपसे कहते हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा और समय मिलता है एक साल बाद का या दो साल बाद का। अगर बीमारी इतनी है, तो दो साल में तो कितनी हो जाएगी। तो शायद पेशेंट न भी बचे। तो हमने फैसला किया है कि आप दिल्ली सरकार के अस्पताल में अगर जाते हैं और वहां पर आपरेशन की डेट आपको एक महीने के अंदर-अंदर नहीं मिलती तो आपका ऑपरेशन 48 अस्पतालों में, पहले 41 की लिस्ट थी, अब 48 कर दिया है। बड़े-बड़े अस्पतालों में जो एनएबीएच एक्रेडेटिड हैं, क्वालिटी इज एशयोरेड। बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जाकर अपना आपरेशन करा लीजिएगा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार दगी। ये स्कीम लागू हो चुकी है। अच्छा दोनों स्कीमों के लिए दिल्ली का नागरिक होना जरूरी है। कोई इनकम लिमिट नहीं है। दिल्ली का नागरिक होना चाहिए। गरीब है, अमीर है, कोई भी है, सबके लिए लागू है, एक समान है।

एक तीसरी स्कीम भी स्टार्ट की गई है। पिछले साल गांधी नगर में एक सिलेंडर हादसा हुआ था। उसमें कई लोग घायल ह ुए। उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में ले जाया गया। वो शायद ज्यादा समर्थ नहीं थे। तो हॉस्पिटल वालों ने टाल मटोल करके उनको सरकारी अस्पताल की तरफ भेज दिया। कुछ एलएबीएस में भी गए। इस दौरान छः सात घंटे का टाईम लैप्स हुआ। काफी दुःखद रहा। मैं खुद गया था अस्पताल में। एक दो लोगों की डेथ हुई जो कि मुझे ल गता है कि अगर डिले नहीं

होता, तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। मुख्यमंत्री से भी मिले वो लोग। तो उस दिन मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि अगर एक्सीडेंट की वजह से या आग लगने की वजह से या एसिड अटैक की वजह से किसी को इस वजह से कि भई, उसको सरकार अस्पताल में 15 कि.मी. दूर लेकर जाना है या प्राईवेट में आप लेकर गए तो वो इस लिए कि पैसा कौन देगा, हमें दिल्ली के अंदर लोगों की जान बचानी है। आज सिर्फ रोड एक्सीडेंट से दिल्ली में 1600 से 1800 लोगों की डेथ होती है। अगर उन डेथ में से प्राईवेट हॉस्पिटल के अंदर आप सामने हैं, आप ले जाइएगा। किसी का भी अगर एक्सीडेंट होता है, दिल्ली की टैरिटरी के अंदर एक्सीडेंट होता है, उसका हम नाम नहीं पूछेंगे; राम है कि रहीम है, हम ये भी नहीं पूछेंगे कि किस प्रदेश से है, कोई भी है। आप किसी भी अस्पताल में ले जाइएगा। दिल्ली सरकार उसका एक्सीडेंट का टोटल खर्चा वहन करेगी। जो हमने फ्री टैस्ट और फ्री ऑपरेशन की स्कीम बताई है, साथ में ये वाली एक्सीडेंट वाली स्कीमें। तो अक्सर मतलब, जैसे लोग मीडिया में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वे ये कहते हैं कि ये तो दिल्ली का पूरा बजट ही खत्म कर देंगे। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को धान्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बजट में प्रोविजन भी यिा और अनलिमिटिड कमिटमेंट भी दियाह ै कि अगर इसके अंदर कम पड़ेगा तो पैसे की कमी नहीं रहने देंगे। इन स्कीम्स से हम पीछे नहीं हटेंगे। आज तक सभी सरकारें ये कहते थी कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा तो पहले भी था आज भी है पर पहले नीयत नहीं थी, आज नीयतठीक है। फर्क ये था। एक छोटा सा ऑब्जेक्शन, कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि दोनों स्कीमें है जो फ्री टेस्ट वाली और फ्री आपरेशन वाली, ये सब दिल्ली वालों के लिए क्यों की गई है? क्योंकि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में पूरे देश के लोग आते हैं, उनका

इलाज किया जाता है मुफ्त में किया जाता है। हम उनसे नहीं पूछत कि आप कहां से आए हैं। वो कह रहे हैं कि आप आपने ये जो स्कीमें दिल्ली वालों के लिए क्यों की हैं? देखिएगा, अभी दिल्ली के पास बजट है, हमारा पैसा, पर इतना भी नहीं है कि कैट स्कैन जो कि 25 हजार का होता है। अब वो पूरे देश के लिए करा पाना संभव नहीं है। दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए हमने ये कर दिया है। मैंने तो कहा था, अभी मुझे हरियाणा से एक मित्र का फोन आया। कहते हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ऐसे काम किये हैं, जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे। जो डिमांड भी नहीं थी कहीं से। किसी ने सोचा भी नहीं था, ऐसा काम करना चाहिए, वो कर दिखाया आप लोगों ने। कहते हैं, हमारे लिए नहीं किया। मैंने कहा आप बुला लेना, आपके यहां भी करेंगे। और केंद्र सरकार! केंद्र सरकार भी तो कर सकती है। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले ऐम्स में ही कर दें। ऐम्स में हर चीज के पैसे ले रहे हैं, हर चीज के पैसे ले रहे हैं। दिल्ली सरकार तो सबके लिए कर रही है ना भी कर दीजिएगा, इमीजिएटली कर दीजिएगा। और जितनी भी राज्य सरकारें बीजेपी की, कांग्रेस की हैं, हमने रास्ता दिखा दिया है तो आपको रास्ता तो मिल गया, अब आप भी कर लीजिएगा। इसको क्रिटिसाइज ना करके मुझे लगता है इसका सहयोग करें। और लोगों के लए बताएं कि इसको यूज कैसे करना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत धान्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट दिया और सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि जैसे मैंने बताया अभी अनऑथोराईज्ड कालोनीज के लिए मैंने 800 करोड़ मांगे थे, 905 करोड़ दिये। तो पैसे इन्होंने मुझे ज्यादा ही दिये हैं पैसे की दिक्कत नहीं होने दी, धान्यवाद, थैंक्यू।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष जी, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा सिर्फ एक मिनट इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जरनैल जी, चर्चा हो रही है बजट पर।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष जी बहुत ही संवेदनशील मसला है, सिर्फ एक मिनट के समय में पूरा कर दूंगा। इस सदन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर किंग्जवे कैम्प में, भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से ही चुनाव से पहले लोगों को धार्मिक भावनाओं को भड़का कर लोगों को बांटने पर विश्वास रखती है, दो तीन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि पंजाब में हमने अपने दो साल के कामों के आधार पर वोट मांगे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी श्मशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए सात तारीख को किग्जवे कैम्प के ढका गांव में, जिस तरीके से पिछले साल पंजाब चुनाव से पहले इन्होंने बीजेपी और अकाली दल बादल द्वारा शासित एमसीडी ने पंजाब चुनाव से पहले शीशगंज साहिब के बाहर प्याऊ तुड़वाया और इल्जाम लगाया कि जी, ये काम दिल्ली सरकार ने किया है। खैर! पंजाब के लोगों ने सारी चीज को समझा और उसके नतीजे कल पंजाब के लोग इनके मुंह पर थप्पड़ मार कर देंगे,

जब रजल्ट आएंगे। अध्यक्ष जी, सात तारीख को ढका गांव के अंदर से फिर से गुरूद्वारा ढहाया गया है। बीजेपी एमसीडी चलाती है, पुलिस भी बीजेपी के कंट्रोल में है। दोनों ने मिलकर गुरूद्वारा ढहाया है और एक ऐसा समुदाय जो हमेशा से बात करता है, सभ्य सांझी वाल सदायेन कोये न दिसे बारा जिओ। उस महान गुरू श्री गुरू ग्रंथ साहिब का वहां पर अपमान हुआ है। इसके

पहले पिछले-पिछले हफ्ते तिलक नगर के अंदर जगदीप भाई ने पहले मसला उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री जरनैल सिंह : फिर से लोगों की धार्मिक धार्मिक भावना भड़काने के लिए, हमारे गुरूओं के चित्रों के ऊपर ऐसी घिनौनी हरकतें करके, मजाक उड़ाया गया है तो मेरा इस सदन की नॉलेज में लाने का मसला था, आपके समक्ष ये बात रखने का ये मकसद था कि फिर से दिल्ली में एमसीडी चुनाव आ रहे हैं और इनकी पूरी कोशिश है कि फिर से वोटों का पोलोराइजेशन किया जाए तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी सख्त से सख्त निर्देश हों, इस मामले में दिये जाएं। ढका गांव के अंदर जो गुरूद्वारा गिराया गया है, उसकी भी इन्कवायरी की जाए। पुलिस, एमसीडी से जवाब त ल ब किया जाए ताकि ये पब्लिक तो सब समझती है, पर अध्यक्ष जी ऐसे नुकसान होते हैं तो सदियों तक लोग भुगतते हैं, जब धार्म के नाम पर लोग मरते कटते हैं तो। ये अपनी चाल में अपनी साजिशों से कामयाब ना हो पाएं। इस सदन के माधयम से आपके माधयम से ऐसे सख्त निर्देश जाएं और उस गुरूद्वारा तोड़ने की पूरी इन्क्वायरी....

अध्यक्ष महोदय : कन्क्लूड करिए प्लीज। (5.50)

श्री जरनैल सिंह : एमसीडी और पुलिस विभाग से जवाब तलब किया जाए। धान्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मनीष सिसौदिया, उप-मुख्यमंत्री जी।

....(व्यवधान)

अध्यक्षम होदय : नहीं? मेरे पास कम से कम 8-10 आये हुए हैं, मैं सबको समय नहीं दे सकता प्लीज। नहीं, बजट पर चर्चा हो गई। माननीय मनीष सिसौदिया जी, उप-मुख्यमंत्री, बजट पर चर्चा का उत्तर देंगे।

उप-मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसौदिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं पूरे सदन का, आपके नेतृत्व में पिछले दो दिन से।

अध्यक्ष महोदय : पुष्कर जी, मैंने कहा था। आप कल हाथ उठाते, आज समय नहीं था। नहीं, अब नहीं कल आप भेजते मेरे पास, मैं विचार करता। बैठ जाइए, बैठ जाइए।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, बहुत सटीक चर्चा....

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भइया, बैठ जाइए। आप बैठिए प्लीज, माननीय उप-मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, बोल रहे हैं। आप बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए, हां मुझे धयान है प्लीज बैठिए। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। वित्त मंत्री जी।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिन से आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन मेमं बहुत सटीक चर्चा दिल्ली के मुद्दों पर इस बजट चर्चा के माध यम से हुई। मैं अपने सभी साथियों का बहुत-बहुत तहेदिल से धान्यवाद अदा करता हूं। कल से ले कर आज तक जिसमें कल जब चर्चा शुरू हुई तो अलका जी, नितिन जी, जरनैल सिंह, सरिता जी, राजेंद्र भाई, अनिल बाजपेयी जी, वेद प्रकाश जी, अखिलेश भाई ने और जगदीश प्रधान जी ने चर्चा की। आज भी

मदन लाल, बग्गा साहब, प्रमिला बहन, राखी जी, सोमनाथ भारती जी, राजेश गुप्ता जी और नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी ने चर्चा में हिस्सा लिया। कपिल मिश्रा जी और सतेंद्र जैन जी ने भी और कैथ्बनेट के मेरे सहयोगियों ने अपनी बात इन सभी के तमाम इनपुट्स और तमाम जितने भी इन्होंने वक्तव्य दिए, नेता प्रतिपक्ष ने बहुत क्रिटिकल नजरिए से बजट को देखा। मेरे तमाम साथियों ने कुछ चीजें जो छूटी या जो इच्छाएं थीं, उनको रखते हुए एक तारीफ के नजरिए से भी बजट के बारे में चीजें कही, मैं सबका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पूरे दो दिन अ पना बहुमूल्य समय इस बजट को पढ़ने में और इस पे चर्चा में लगाया। मैं देख रहा हूं कि कल परसों से जब से बजट पेश किया है इसकी देश भर में तारीफ हो रही है। कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने क्योंकि जीएसटी काउंसिल का मेम्बर होने के नाते बहुत सारे वित्त से मेरा संवाद बना है पिछले एक डेढ़ साल में, और इस वजह से उनसे व्यक्तिगत जान पहचान, उनसे संपर्क रहा है। कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने फोन करके मुझे इसकी बधाई दी है कि उनमें से कई, नाम लेना ठीक नहीं है, कई लोगों ने कहा कि ऐसा, ऐसा जन उपयोगी बजट हम अपनी पार्टी में तो बनाने का सोच नहीं सकते। ये आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का, आम आदमी पार्टी में तो बनाने का सोच नहीं सकते। ये आम आदमी पार्टी के नेतृ त्व का, आम आदमी पार्टी के विधायक मंडल का उनके सहयोग का कमाल है कि अलग-अलग राज्यों के वित्त मंत्री भी इस बजट की तारीफ कर रहे हैं और इस बात का अफसोस कर रहे हैं कि काश! वित्त मंत्री के रूप में हमें भी अपनी पार्टी, अपने विधायकों से ऐसा सहयोग मिला होता तो हम भी ऐसा बजट बना पाते। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय मंत्री और केंद्र के कई अधि ाकारियों ने मुझे फोन करके इसकी बधाई दी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि

उन्होंने, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि क्योंकि अगर मैंने नाम ले लिया, तो कइ की कुर्सी चली जाएगी। तो मैं कल का अखबार देख रहा था कई अखबारोंु में एडिटोरियल में बहुत जबरदस्त तारीफ लिखी गई है कि when every, but what is eye catching in the new budget is, "The allotment of 36 percent on education and health. Over the years, the Indian poor have lost out with the entry of the mafia and cooperatate sector in education and health." ये बहुत बड़ा क मेंट है। इसी तरह तमाम लोगों ने, आम जनता की राय, लोगों ने, व्यापारियों की राय, गृहणियों की राय, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल सभी की राय लेके अखबार में छापी। लोगों ने बहुत शानदार प्रतिक्रिया, कहीं से कोई औपचारिक शब्दावली जो हम हमेशा सुनते हैं विपक्ष के नेताओं की, उसके अलावा, कहीं से कोई बात आई नहीं सुनने में। पर मैं अखबारों की बात पे नहीं जा रहा। मैं ऐ नकता प्रतिपक्ष ने, विपक्ष के साथियों ने, जगदीश भाई ने और तमाम मेरे साथियों ने जो सत्तापक्ष से हैं, कई ऐसी चीजें रखी हैं, जिन पर में बहुत संक्षेप में कुछ कुछ बातें कहते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा, धान्यवाद करते हुए पर सबसे पहली बात में हमारे साथी कपिल मिश्रा जी ने कई बार मुझसे पूछा, ''इतनी बचत करके कहां जाओगे? इतनी बचत करके क्या लेके जाओगे? क्या करोगे?'' क्या बोल रहे थे कितने इतने....जिसको विजेंद्र जी ने अंडर लाइन किया था कि मैं बोल देता तो, इतना पैसा बचा के, कहां लेके जाओगे? कपिल भाई बचे हुए सिक्के गुल्ल्क में डालते, गरीबों के घर में हिसाब नहीं होते। हम तो आम आदमी हैं, घरों में ऐसा ही चलता है। बचे हुए सिकके गुल्लक में डाल देते हें। गरीबों के घरों में हिसाब नहीं होते हैं। तो हिसाब नहीं है, ये तो आम जनता है। आम जनता जितना कमाती है, उतना खर्च कर

लेती है। हम तो उसके मैनेजमेंट में हैं। ज्यादा पैसा हो जाता है, टैक्स कम कर देते हैं। लगता है इतने, और उसमें भी टैक्स ज्यादा आ जाता है फिर तो....मैं जगदीश ने, अपनी बात रखते हुए बड़ी तारीफ की है। एजुकेशन के बारे में उन्होंने इसबात की भी तारीफ की कि भाई मेरी विधान सभा में भी कमरे बन रहे हैं। इस बात से वो खुश हैं। बिल्कुल हृदय से उन्होंने इसके लिए तारीफ की। फिर, क्योंकि बीजेपी के सदस्य हैं तो औपचारिकता में ये भी कहा कि वो 500 स्कूल कहां हैं? उनको भी पता है कि उनके यहां 500 स्कूलों के हिसाब से देखें तो कई कई स्कूल बन चुके हैं या बन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, कुछ मीडिया में भी कुछ लोगों ने क्वैश्चन किए और कुछ मेरे साथियों ने भी अनौपचारिक चर्चा में भी पूछा, मैं एक दो चीज जो, क्योंकि इतनी सारी चीजें थी हर चीज को बजट स्पीच में शामिल करना और जिन चीजों पे मैं बात करता आ रहा हूं लगातार सरकार अदर देन बजट पर बात करती रही है, जरूरी नहीं समझा मैंने, जैसे मुझसे पूछा गया बात में कि वाई फाई....किसी एक चैनल ने तो हेडलाइन चला दी, ''वाई फाई गायब!'' क्योंकि मैंने बजट स्पीच में जिक्र नहीं किया था पर उसका पैसा बजट में है, बकायदा शामिल किया गया। तो वो बजट एक्चुली सिर्फ बजट स्पीच नहीं होती है। ये बजट में, बजट पेश करते हुए दिया गया वक्तव्य है लेकिन बजट तो ये है, बजट तो ये है अध्यक्ष महोदय। तो इसमें कोई गौर से देखियेगा, जिसको भी थोड़ा सा भी बजट के पेपर पढ़ने का संज्ञान है, निश्चित रूप से उसको वाई फाई का पैसा भी दिखेगा, उसमें सीसीटीवी में 100 करोड़, बसों में स्कूलों के लिए 100 करोड़ और 130 करोड़ रूपये जरनली सीसीटीवी के लिए, ये भी दिखेंगे, एलइडी स्क्रीन्स का पैसा भी दिखेगा, स्ट्रीट लाइट का भी पैसा दिखेगा।

अनॉथराइज कालोनी का जिक्र सत्येंद्र भाई ने भी किया, उसका पैसा भी देखेगा, मौहल्ला सभा का पैसा भी दिखेगा। ये चीजें ऐसी थी जिसको यहां सदन में नहीं, लेकिन सदन से बाहर भी इनको मुद्दा बनाने की कोशिश की कहां है? कहां है? इस बजट में है और सब चीजों पे पैसा है। कोई चीज, क्योंकि बजट स्पीच में किसी चीज का शामिल नहीं होना, इसका संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि वो चीज है या नहीं है। क्योंकि ये बात मीडिया के साथियों तक पहुंचती है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा। तो फंड कितना है, कैसे है, वो तो खर्च के हिसाब से कभी भी बढ़ाया जा सकता है।

हमारे साथी मदन लाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं उनसे सहमत हूं और मैं यहां आश्वासन तो नहीं देता लेकिन सरकार की तरफ से एक कोशिश की बात जरूर कह सकता हूं कि उन्होंने एक बुनियादी मुद्दा उठाया है कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहां देश के कोने कोने से लोग आ कर रहत हैं, हर भाषा के लोग यहां आ कर रहते हैं तो हम इस सोच के दायरे को थोड़ा विस्तृत करें कि यहां जिस भाषा के बोलने वाले अधिाक संख्या में हों, उन्हीं भाषाओं के अकेडमिज हों। जिन भाषाओुं के बोलने अपेक्षाकृत कम संख्या में हों, उनको भी तो लगे हम देश की राजधानी में गए हैं तो वहां गुजराती अकेडमी भी है, वहां हरियाणवी अकेडमी भी है, वहां राजस्थानी अकेडमी भी है तो ये अच्छा प्रस्ताव है। मैं इसकी सराहना करता हूं और जरूर इस पर सरकार में बैठके विचार करने की कोशिश करेंगे, इसमें अच्छा होगा अगर हम भारत की सभी प्रमुख भाषाओं की अकेडमी यहां बना सकें और सिर्फ अकेडमी, कि किसी को यहां चेयरमैन या वो बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन भाषाओं में रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, उन भाषाओं के साहित्यकारों के लिए,

उन भाषाओं पर के बोलने वाले लोगों के लिए, उन सब के लिए लगे कि हमारा, हमारी भाषा पर, हमारी संस्कृति पर ये भी सरकार, देश की राजधानी में बैठी हुई सरकार कुछ धयान रख रही है, हमारा हिस्सा वहां है, उनको ये लगे। इसलिए मैं बहुत प्रशंसा करता हू इनके इस प्रस्ताव की।

प्रमिला टोकस जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि पहले चिड़िया चहचहाया करती थी, अब वो चहचहाती नहीं है। इसलिए पर्यावरण पे जो किया जा रहा है, उसके लिए अच्छा है। बहन, अभी चिड़िया तो छोड़ दीजिए, इंसान की चहचाहट खत्म हो गई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्कूलों में वो चह चहाट लोट आए तो समाज में भी लोट के आएगी। (6.00) हमारा सिद्धांत है कि सरकार का काम लोगों को डराना नहीं है, सरकार का काम लोगों के अंदर से डर निकालना है। दिल्ली का एक-एक आदमी खड़ा होकर ये सोच सके कि जब भी उसके ऊपर कोई संकट हो, जब भी वो किसी भी विपदा महसूस करे तो उसको कांफिडेंस हो कि संकट में हूं तो क्या है, मेरी सरकार मेरे साथ है। मेरी सरकार ने मेरे लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कर रखी हैं। ये निडर बनाना है तो सरकार का काम अपने लोगों को, जिन लोगों ने उनको चुनकर भेजा है, उनके साथ खड़े होकर ये अहसास कराना कि सरकार की वजह से लोग निडर महसूस करें कि सरकार की वजह से लोग डर में न महसूस करें। इस बात को न सोचें कि कब पुलिस आ जाएगी, कब कब्रिस्तान और मंदिर-मस्जिद, इन सबके झगड़ों में मेरा व्यापार ठप्प हो जाएगा। ऐसी पार्टियों की नहीं सोचें। ऐसा सोचें कि ये पार्टी सरकार में आई तो हमें निडर बनाएगी, मेरे साथ खड़ी होगी। हम आज वो पार्टी कैसे-कैसे सिर्फ मंदिर-मस्जिद, कब्रिस्तान और श्मशान की बात नहीं है और भी जो परंपरागत

रूप से इसी सदन में बैठकर सरकारें चलकर गई हैं कई साल, और भी सदनों में चलती रही हैं, ये इस 70 साल की राजनीति में; टैक्स का डर, महंगाई का डर, बीमारी का इलाज न मिलने का डर, बच्चों की अच्छी पढ़ाई न मिलने का डर, ये सब डर हैं जो एक आम इंसान चाहता है कि मेरी सरकार कोई ऐसी आए जो मुझे इसके बारे में निडर बना दे। बिजली महंगी होने का डर, पानी के महंगे होने का डर, झुग्गियां टूटने का डर, जिसका जिक्र कई साथियों ने किया। बेघर रह जाने, रैन बसेरे, खुले आसमान के नीचे रात बिताने का डर, व्यापारी को रहता है रेड का डर, कहीं ऐसा ना हो, रेड आए 10 लाख का टैक्स बनाए और उसके बाद 5 लाख में सेटल करके ले जाए। व्यापारी को रेड का डर रहता है, कई तरह की पालिसिज का डर रहता ही। ये जो बजट है, जो मैंने बनाने की कोशिश की है, मैंने अपने तमाम साथियों के सहयोग से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की गाइडेंस में ये आम आदमी को निडर बनाने का बजट है। इससे लगातार तीसरा ऐसा बजट है, जो दिल्ली सरकार के आम आदमी को निडर बना रहा है और जैसे-जैसे आम आमदी निडर बन रहा है, कुछ लोगों के दिल का डर बढ़ता जा रहा हे। उन लोगों को डर लग रहा है। निडर होती जनता और डरते कुछ नेता! निडर होती जनता ने कई लोगों के समीकरण खराब कर दिए।

अध्यक्ष महोदय, ये महल लफ्ज नहीं हैं, ये ब ज ट के।

ये महल लफ्ज नहीं हैं, याद दे रहा हूं,

हौसला पनप रहा है, मैं तो सिर्फ खाक दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा काम एक वित्त मंत्री के रूप आम आदमी को निडर

बनाने का है। उसके हौसले को बढ़ाने का बजट है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बजट उस हौसले को, उस निडरता को ख ाक देने का काम करेगा। हर बारह म इसको और खाक देते रहेंगे, सरकार के रूप में, बजट के रूप में।

अब मैं नेता प्रतिपक्ष के कुछ बुनियादी मुद्दों पर आता हूं। भले ही वो कहें कि हम तो तीन है, हम तो दो है, हम तो एक हैं, पर मैं वित्तमंत्री के रूप में इस कुर्सी पर बैठकर हमेशा उप मुख्यमंत्री के रूप में इस बात को बहुत क्रिटिकल नजरिए से देखता हूं किवो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि किताबों में मत खंगाला करिए, लोगों की जिंदगी को देखिए। आपने कहा कि आउटकम किताबों में नहीं मिला, मैंने किताबों को बहुत खंगाला। अरे! किताब क्यों खंगालते हो? आउटकम तो जनता में मिल जाएगा आपको। आप मौहल्ला क्लीनिक में जाकर देखो, स्कूल में जाकर देखो। आउटकम देखना है तो आउटकम है या आउट कम है। आप किताबें खंगालते रहोगे, पता नहीं क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा।

आपने नोटबंदी के कागजी फायदे भी गिनवाए। मेरे पास बहुत कागज हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से दिल्ली में अलग-अलग कमोडिटीज का हमने पूरा रिकार्ड निकलवाया है, किस तरह से उनका व्यापार घाटे में चला गया है, किस तरह से लोग रो रहे हैं, किस तरह से लोग दुखी हैं। आप किन कागजों की बात करते हो? इसलिए मैं कहता हूं कि आउटकम कागजों में मत ढूंढो, लोगों की जिंदगी में देख लो जाकर, लोग बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। आपने अरविंद केजरीवाल जी की लिखी हुई स्वराज पुस्तक की बात की, बोले मौहल्ला सभा कहां गई? मुझे खुशी है कि कम से कम आपने स्वराज

पुस्तक तो पढ़ ली। बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि कम से कम आपको ये तो पता तो चला कि ये जो पागल लड़के-लड़कियां इधार आकर बैठ गए हैं जनता ने इनको बिना किसी एक्सपीरियंस के इतना बड़ा बहुमत देके भेजा है, उसके पीछे दीवानगीपन का राज क्या है। ये किस मिट्टी के बने हुए हैं। ये स्वराज की मिट्टी के बने हुए हैं। आपको पता तो चल गया। इसीलिए फाइलें मंगा-मंगाकर आप 8-8 महीने एलजी दफ्तर में कैद करा देते हो और फिर सदन में खड़े होकर पूछते हो कि मौहल्ला सभा कहां है। मौहल्ला सभा को वहां से भी मुक्त कराकर लायेंगे, विजेंद्र गुप्ता जी, चिंता मत करिए।

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बड़ा अच्छा शब्द सुना है कहीं, ''सुविधाजनक सत्य।'' 9 आदमी अपने हिसाब से सत्य को डिफाइन करता है और फिर बोल देता है, उसको कहता है, ''सुविधाजनक सत्य।'' लेकिन आज पहली बार मैंने सुविधाजनक कैलकुलेशन होते हुए देखी। सुविधाजनक गणना करते हुए देखा मैंने। सुविधाजनक सत्य बोलते हुए तो बहुत पाए जाते हैं। अपने हिस्से का, चार पन्ने का सत्य होता है, उसमें से अपने हिस्से का एक पैराग्राफ पढ़ दिया और उसको सुविधाजनक सत्य कर दिया है। लेकिन सुविधाजनक कैलकुलेशन करके सदन में रखना, आज विजेंद्र गुप्ता जी ने एक नई इजाद की है इस सदन में। उन्होंने कहा, पता नहीं कहां से, वो बता दें तो मैं कहूंगा भई, पता नहीं। लेकिन मुझे पता है कि आपके पास वो आंकड़े कहां से आए हैं। जो आपक ेपास वो आंकड़े लेके आया था, वो मेरे पास भी लेके आया था और आप गच्चा खा गए। क्योंकि मैंने तो बजट बनाया था, मैं गच्चा खा नहीं सकता था। बजट, मैं नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहता हूं कि यहां है। किसी रिसर्चरके आंकड़ों में नहीं है। बजट यहां है, बजट को यहां ढूंढिए। किसी रिसर्चर के

अधाकचरे ज्ञान के आधार पर तैयार किए गए किसी विश्लेषण से देखेंगे तो सदन में आप सुविधाजनक कैलकुलेशन करने के आरोपी हमेशा बताए जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विजेंद्र गुप्ता जी नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहता हूं कि 2017-18 के जिस बजट में शिक्षा के बजट में इन्होंने कहा 900 करोड़ रूपये हैं, मोटी पुस्तक छोड़ दीजिए, बाद में पढ़ लेंगे। काफी पढ़ने के लिए, आपके रिसर्चर को भी बहुत टाइम लगेगा। अपने रिसर्चर्स को बता दीजिएगा कक मैंने उनको बताया था पर वो माने नहीं इस बात को। समझे नहीं इस बात को, मानेंगे तो क्या। आप बता दीजिएगा कि आप बता दीजिएगा कि आप वित्तमंत्री की बात समझ गए होते तो आपको मिसगाइड नहीं करते, मैं बता रहा हूं। हां, मुझे पता है। क्यों? आप बस इतना कर लें कि ये 11300 तो है मैं सोच रहा था इनको पेज नंबर का मैंने लिखा था कागज। पेज-8 लिख लीजिए। फिगर 10186 करोड़ रूपये एजुकेशन में छोटी किताब है बड़ी की बात ही नहीं कर रहा मैं। पेज संख्या-14 पर 1054 करोड़ रूपये और पेज-18 पर 60 करोड़ रूपये एजुकेशन में खर्च करने के लिए बताए गए हैं। थोड़ा मैथमेटिक्स मुझे भी आता है। 10186, 1054 और 60 को जोड़ करते हैं तो 11300 होता है ये 9 हजार कैसे हुआ मुझे भी समझ में नहीं आया। ये एमसीडी के स्कूल में से तो नहीं आए है। अच्छा वो कह रहे हैं, उन्होंने कमिशन काट लिया। गुप्ता जी, हमारे यहां कमीशन काटने की राजनीति नहीं होती हमारे यहां 11300 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो 1 1300 करोड़ ही खर्च करने की राजनीति हम लोग करते हैं। परंतु ये कैलकुलेशन थोड़ा सा सिर्फ जोड़-घटा का ही मामला है, कोई बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है और तीन फिगर ही जोड़नी हैं। आपने हैल्थ के बजट की बात की। वहां भी कहा

आपने, ''5033 करोड़ रूपये।'' मैंने पन्ना पल्टकर देखा फिर से, पेज संख्या-8 पर 5048 करोड़ और पेज संख्या-14 पर 687 करोड़ 88 लाख रूपये लिखा हुआ है टोटल करके देख लो, सामान्य सा जोड़-घटना है। जोड़ना है, ये घटना भी नहीं है। 5735 करोड़ 88 लाख रूपये ये 48000 करोड़ रूपये का डिवीजन है जो आपने 9000 या 65000 करोड़, पता नहीं कहां से फिगर उठाके डिवाइड करने की कोशिश की। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्योंकि सदन के रिकार्ड में कोई चीज जाए। आज से 20 साल बाद कोई उठाकर देखे और कहे कि नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया था फिगर पर, इसलिए जवाब दे रहा हूं। मुझे ज्यादा जरूरत नहीं थी। क्योंकि आंकड़ों में सब कुछ लिखा हुआ है। इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। (6.10)

दूसरा आपने कुछ पिछले साल के मुद्दे भी उठाये। आपने कहा, ''बड़ा शेर मचाया था कि दो गुना बजट हो गया, दो गुना बजट हो गया।'' अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद है, 2013-14 में कांग्रेस की सरकार ने बजट बनाया होगा। 2014-15 का बजट। आपका एजुकेशन का प्लान जो खर्च हुआ है, 2013-14 में 2049 करोड़ रूपये खर्च हुआ है। 2014-15 में 2213 करोड़। 2049 करोड़ रूपये, 2014-15 में 2213 करोड़ रूपये और आज 2016-17 चालू वित्त वर्ष में 4045 करोड़ रूपये का आरई अभी पास करायेंगे। आप उठाके देख लीजिए। दो गुना नहीं होता है तो बता देना क्या कहा था।

अध्यक्ष महोदय, कमरों की बात की गयी। कमरे चाहिए क्लास रूम में, पर मैं फिर से कहूंगा इस किताब को बजट स्पीच भी पढ़ लीजिए। पेज संख्या 18 पर मैंने कमरों का जिक्र किया है लेकिन एजूकेशन में क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या-क्या सपना देखके हमने काम शुरू किये हैं, पेज

18 से लेके 25 तक लिखा हुआ है। थोड़ा सा ही है, ज्यादा लम्बा-चौड़ा नहीं है। पढ़ लेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन पर किये जा रहे काम की झलक मिल जायेगी। समय निकले तो स्कूलों में चलना पड़ेगा। किताबें खंगलाने से आउटकम समझ में नहीं आयेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कहीं थीं, जिनका जवाब देना यहां बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोन, मैं बहुत अथारिटी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सदन के समझ रख रहा हूं कि पिछले दो साल में हमने नगर निगम से जितना लोन दिया गया था, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एक रूपया भी वसूला नहीं है, एक रूपया भी वसूला नहीं है। एक रूपया भी नहीं लिया है, डाक्यूमेंटस में। लेकिन जब आपइ सपे आओगे। जब आप इस बुक पे आओगे तो एकाउंटिन्ग का एक बेसिक प्रिसिंपल होता है कि आपने अगर किसी को कर्ज दे रखा है तो उसको तो आपको अपनी लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा कि मैंन ेचार सौ करोड़ रूपये इसको कर्ज दे रखा है। नहीं लेंगे? वो तो कह ही रहे हैं। एक मिनट, आप सुन लीजिए। आप सुन लीजिए आप क्या कह रहे हैं आप। वो तो आपको पिछले साल भी दिख जायेगा। उससे पिछले साल भी दिख जायेगा, जब आपकी सरकार ने बजट पेश किया था, तब भी दिख जायेगा। क्योंकि एकाउंटिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी के लेनदार हैं तो उसका भी जिक्र करेंगे और अगर किसी के देनदार हैं, तो उसका भी जिक्र करेंगे एकाउंटिंग में। ये पॉलिसी नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ एकाउंटिंग है। आप जब बजटिंग करेंगे, एकाउंटिंग करेंगे तो ये लिखना ही पड़ेगा। आप मिसलीड मत कीजिए सदन को। आप देश को, दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। ये तो बताना पड़ेगा उसमें

और अधक्ष महोदय, इसमें सिर्फ एमसीडी का नहीं है। इसमें तो डीटीसी से भी कुछ लेना है। सरकार ने अगर डीटीसी को लोन दिया है, वो भी लिखा हुआ है। डीजेबी को दिया है, वो भी लिखा हुआ है। किसी भी कारपोरेशन को दिया हुआ है; लेनदारी और देनदारी तो एकाउंटिंग में लिनखी जाएगी, पालिसी है। हमने नहीं दिया दो साल से। केंद्र ले रहा है, दे रहे हैं। चार हजार करोड़ की देनदारी दे रहे हैं। बकायदा दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने नॉन प्लान, प्लान, नॉन प्लान, रेवेन्यू और कैपिटल को ले के भी कुछ कन्फ्यूजन क्रियेट करने की कोशिश की गयी। नॉन प्लान और प्लान अगर सब्जेक्ट है। रेवेन्यू और कैपिटल एकदम अलग सब्जेक्ट है। इसको नॉन प्लान और प्लान के चश्में से नहीं पढ़ सकते। नहीं समझ सकते। मैं बहुत इकोनामिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन जितना मैं समझा हूं, उससे मैं कह सकता हूं। बाकी इकोनामिक्स के हमारे बहुत सारे साथी यहां बैठे हैं। आप भी जान सकते हैं, वित्त मंत्री जी, केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली जी, खुद इसको इसलिए खारिज कर चुके हैं। वो बोले, 'प्लान और नॉन प्लान की वजह से सारा कन्फ्यूजन होता है।'' क्यों? मैं सिर्फ एक उदाहरण से बता दूंगा कि क्यों लागू किया, अगर अच्छा नहीं है तो। रेवेन्यू और कैपिटल में भी जिस तरह से, रेवेन्यू और कैपिटल के ये जो डिफरैंन्स होता था कि नान रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नॉन प्लान बढ़ रहा है कि प्लान बढ़ रहा है। ये डिफरैंस अच्छा या बुरा माना जाता था, लेकिन रेवेन्यू और कैपिटल में तो बुरा मानने वाली कोई गवर्नेंसके पैरामीटर देखे नहीं जा सकते। आज हम एक हॉस्पिटल बनाते हैं। हम सौ करोड़ रूपये खर्च करके हास्पिटल बना देते हैं, वो कैपिटल मुं आ जाता है। उतनी ही बढ़िया सेवाएं, सत्येंद्र जी अभी स्कीम एनाउन्स कर

रहे थे, उतनी बढ़िया सेवाएं अगर हम बाहर से किसी प्राईवेट सेंटर को हॉयर करते हैं, वो रेवेन्यू में आ जाता है। जबकि मरीजों को तुरंत इलाज मिलना शुरू हो जाता है। अब आप कहोगे, ''रेवेन्यू पर ज्यादा पैसा खर्च हो गया।'' अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार इस सदन में कहता रहा हूं। इस पार्टी ने, इस सरकार ने डेवलपमेंट की एक बड़ी डेफिनेशन बदली है। अब तो कैपिटल का मतलब सिर्फ मेज-कुर्सियां खरीदना, सिर्फ गाड़ियां, घोड़े खरीदना, सिर्फ कमरे बनवाने, रहने के लिए मकान बनवाना, इससे आगे कैपिटल की डेफिनेशन निकल गयी। पिछले तीन साल से हमारी असली कैपिटल दिल्ली के लोग हैं। हम उनके लिए काम कर रहे हैं। आप बिल्डिंग बनवाने को कैपिटल मानिए, हम लोगों की जिंदगी बनवाने को कैपिटल मानते हैं। आप श्मशान और कब्रिस्तान बनवाने को कैपिटल मानिए, हम स्कूल और अस्पताल में बच्चों को पढ़वाने को कैपिटल मानते हैं। ये हमारी और आपकी डेफिनेशन में अंतर है और बेसिक रहेगा। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सत्ता में।

अध्यक्ष महोदय, दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं, वो रेवेन्यू में है। क्योंकि दवाई तो खाली है, वो तो कैपिटल तो है ही नहीं। टीचर्स, बच्चे पढ़के निकल गये। टीचर्स को तनख्वाह दी गयी। अब वो रेवेन्यू है, कैपिटल हो ही नहीं सकता वो। इनके हिसाब से तो....इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं हे। इन्होंने एससी-एसटी कम्पोनेंट की बात की। वहां भी थोड़ा सा सुविधाजनक कैलकुलेशन करके दिया। आपने दिल्ली सरकार का सिर्फ और सिर्फ एससी कम्पोनेंट उठाया और बाकी राज्यों का आपने सोशल सेक्टर, सोशल सिक्योटिरी सेक्टर का पूरा कम्पोनेन्ट उठाके उसकी तुलना कर दी उससे। आज मैं आपको कह रहा हूं। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सेक्टर तो बहुत है, एजूकेशन, हेल्थ सोशल में आ

जाता है। सोशल सिक्योरिटी सेक्टर को आप उठाके देखेंगे, सात परसेंट खर्च कर ही है दिल्ली सरकार। सेवेन परसेट। आप सोशल सिक्योरिटी सेक्टर और उसका एक कम्पोनेन्ट, दिल्ली सरकार का एक कम्पोनेन्ट उठायेंगे, एससी पर इतना खर्च कर रहे हैं। बाकी राज्यों में इतना खर्च हो रहा है। अरे! उनका भी एससी कम्पोनेन्ट उठाके देखो न। उसके बाद बात करेंगे कि कितने परसेंट खर्च कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कुछ बातें मिनिमम वेजेज और जो शहीद सैनिक के परिवार को दी जाने वाली राशि के बारे में कही हे। कुछ उसूलों की बात कही हैं। उसूलों चमन और निजाम को समझो सर जी। उसूलों चमन और निजाम इससे खफा होके ही जनता ने इतना बड़ा फैसला लिया था। उसको न आपके उसूल पसंद आये और आपका न निजाम पसंद आया। उन उसूलों को तोड़ने के लिए, उस उसूलों को रिवाइज करने के लिए और इस निजाम को बदलने के लिए जनता ने हमें यहां बिठवाया है। आप उसूल और चमन में उलझे रहिये, हम जनता के दुख दर्द सुनते रहेंगे। उसूल और चमन में उलझके लोगों की जिंगदी को बदहाल करना आपकी राजनीति है। जनता के दुख-दर्द को समझके उसके लिए पालिसी बनाना, उसक लिए काम करना, ये हमारी राजनीति है। आप कह रहे हैं कि इसमें पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे। सियासत से मोहब्बत हो गयी है, सियासत से मोहब्बत हो गयी है। हमारी तो बेसियासत ही मोहब्बत है। हम जनता से मोहब्बत करते हैं। हमारी सियासत ही मोहब्बत है।

फिजिकल डिफिसिट की बात और की आपने। उस पर मैं जरूर बोलूंगा। आपने कहा, फिजिकल डिफिसिट बहुत बढ़ गया हैं आंकड़े उठाके देख लीजिए। आज दिल्ली का फिजिकल डिफिसिट 0.8 परसेंट है। जबकि भारत सरकार

का फिजिकल डिपुसिट 3.24 परसेंट है। जबकि बाकी राज्यों का टू प्वाईन्ट से ऊपर ही मिलेगा आपको। सारे आंकड़ें उठाके देख लीजिए। आज दिल्ली में हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में ईमानदारी से काम हो रहा है और उसकी वजह से....तो अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लम्बी बात न आगे करते हुए, तमाम चर्चा में शामिल सदस्यों का बहुत-बहुत धान्यवाद करता हूं नेता प्रतिपक्ष सहित आप सभी का बहुत-बहुत धान्यवाद करता हूं और आखिर में जिस व्यक्ति की वजह से, जिस शख्स की वजह से हमको प्लानिंग और गाईडेंस मिलती हे, जिसकी हिम्मत की वजह से हमारा हौसला चार्ज होता है उस शख्स को जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, उसके बारे में दो लाइनें पढ़ते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि :

न जाने किसी दुआओं का फैज है असर।

मैं डूबता भी हूं तो दरिया उछाल देता है।

बहुत-बहुत धान्यवाद।

अनुदान मांगें (2017-18)

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धान्यवाद। अब मैं आधा घंटा सदन का समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान मांगें प्रस्तुत करेंगे।

Deputy Chief Minister : Hon'ble Sspeaker Sir, I Present the demands for grant for the financial year 2017-18.

अध्यक्ष महोदय : अब सदन सभी डिमांडस पर डिमांडवाईज विचार करेगा।

डिमांड नंबर 1 जिसमें रेवेन्यू में 21 करोड़ 17 लाख रूपए हैं, सदन के सामने हैं,

जो इसके पक्ष में है वो हां कहें।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष जी इस पर डिवीजन ऑफ वोट्स करवाइये।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट बैठिए। मैं करवा रहा हूं। इससे अभी कई डिमांड हैं, उस पर करवा लेना। ये हो गया है। ये एक बार हो गया है। नेक्सट से शुरूआत करवा रहा हूं। ये एक बार हो गया है। भाई बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइये सहरावत जी। बैठ जाइये, प्लीज बैठ जाइये। प्लीज बैठिए। श्री सोमनाथ भातरी जी ने मत विभाजन की मांग की है। कई माननीय सदस्यों ने इसका अनुरोधा भी किया है, उनका समर्थन किया है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोधा है कि अपने निर्धारित स्थन पर ही रहें तथा जब मैं कहूं, तब अपने स्थान पर खड़े हो जायें। जब तक मैं बैठने के लिए न कहूं तब तक न बैठें। अब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत डिमांड फॉर ग्रांट नम्बर वन पर मत विभाजन होगा।

अब जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जायें और जब तक सदन की कार्रवाई के रिकार्ड में,

श्री विजेंद्र गुप्ता : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहां पर। जब इतनी मैजोरिटी है। तो आपी पार्टी की तो पोलटिक्स है, करिये । हम अपने आपको अलग कर रहे हैं इससे। (6.20)

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं।

श्री विजेंद्र गुप्ता : हम अपने को पूरे इससे अलग कर रहे हैं। आप अपने को चैक कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इन डिमांड के पक्ष में नहीं हैं क्या?

श्री विजेंद्र गुप्ता : हम अपने को इससे अलग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप डिमांड के पक्ष में नहीं है क्या?

श्री विजेंद्र गुप्ता : यह वोटिंग किसलिए हो रही है? प्रश्न यह है। आप करिये, जो करना है।

अध्यक्ष महोदय : चलिए ठीक है। दो मिनट, बातचीत नहीं, प्लीज। काउंटिंग हो गई।

श्री महेंद्र गोयल : अध्यक्ष जी, यह सदन की तौहीन है। जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है, इस प्रकार की भाषा नहीं सही जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : जरा शांत हो जायें। महेंद्र जी, मैं इस पर निर्णय ले लूंगा। दो मिनट बैठ जाएं। शांति रखें, दो मिनट। गणना हो गई क्या? माननीय सदस्य बैठ जाएं।

अब जो सदस्य इस प्रस्ताव के विरोधा में हैं, वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें; और जब सदन की कार्यवाही के रिकार्ड में पूरी गिनती की प्रविष्ट न हो जायें, तब तक न बैठें।

यह डिमांड नंबर 1 सर्वसम्मति से पारित हुई।

अध्यक्ष महोदय : बातचीत नहीं। इस प्रस्ताव के पक्ष में 59 सदस्य हैं जबकि विरोधा में 0 सदस्य हैं। कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव से तटस्थ नहीं रहा, प्रस्ताव पास हुआ।

डिमांड नं. 2 (General Administration) जिसमें रेवेन्यू में 3 अरब 42 करोड़ 36 लाख 50 हजार रूपये हैं सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इकसे विरोधा में हैं, वे न कहें
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,
डिमांड नंबर 2 पास हुई।

डिमांड नं. 3 (Administration of Justice), जिसमें रेवेन्यू में 12 अरब 03 करोड़ 14 लाख रूपये और कैपिटल में 23 करोड़ रूपये, कुल राशि 12 अरब 26 करोड़ 14 लाख रूपये हैं, सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोधा में हैं, वे ना कहें
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता
डिमांड नंबर 3 पास हुई।

डिमांड नं. 4 (Finance), जिसमें रेवेन्यू में 3 अरब 54 करोड़ 97 लाख 50 हजार रूपये और कैपिटल में 7 अरब 15 करोड़ 50 लाख रूपये, कुल राशि 10 अरब 70 करोड़ 47 लाख 50 हजार रूपये हैं सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हों कहें,
जो इसके पक्ष में हें, वे हां कहें,
जो इसके विरोधा में है, वे न कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,
डिमांड नंबर 4 पास हुई।

डिमांड नं. 5 (Home), जिसमें रेवेन्यू में 5 अरब 63 करोड़ 90 लाख रूपये और कैपिटल में 45 करोड़ 27 लाख रूपये, कुल राशि 6 अरब 9 करोड़ 26 लाख रूपये हैं सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोधा में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,
डिमांड नंबर 5 पास हुई।

डिमांड नं 6 (Education), जिसमें रेवेन्यू में 86 अरब 91 करोड़ 09 लाख रूपये और कैपिटल में 3 अरब 74 करोड़ 12 लाख रूपये, कुल राशि 90 अरब 65 करोड़ 21 लाख रूपये हैं सदन के सामने हैं;

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोधा में हैं, वे ना कहें,
(सदस्यों के हां कहने पर)
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,
डिमांड नंबर 6 पास हुई।

डिमांड नं. 7 (Medical and Public Health), जिसमें रेवेन्यू में 48 अरब 63 करोड़ 18 लाख रूपये और कैपिटल में 1 अरब 69 करोड़ 62 लाख 50 हजार रूपये, कुल राशि 50 अरब 32 करोड़ 80 लाख 50 हजार रूपये हैं सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोधा में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 7 पास हुई।

डिमांड नं. 8 (Social Welfare), जिसमें रेवेन्यू में 56 अरब 42 करोड़ 13 लाख रूपये और कैपिटल में 9 अरब 4 8 करोड़ 90 लाख रूपये, कुल राशि 65 अरब 91 करोड़ 3 लाख रूपये हैं सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोधा में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 8 पास हुई।

डिमांड नं. 9 (Industries), जिसमें रेवेन्यू में 3 अरब 26 करोड़ 54 लाख रूपये और कैपिटल में 24 करोड़ 27 लाख रूपये, कुल राशि 3 अरब 50 करोड़ 81 लाख रूपये हैं सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोधा में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 9 पास हुई।

डिमांड नं. 10 (Development), जिसमें रेवेन्यू में 29 अरब 30 करोड़ 42 लाख 60 हजार रूपये और कैपिटल में 7 अरब 46 करोड़ 19 लाख रूपये, कुल राशि 36 अरब 76 करोड़ 61 लाख 60 हजार रूपये हैं, सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोधा में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 10 पास हुई। (6.30)

अध्यक्ष महोदय : डिमांड नंबर 11 जिसमें रेवेन्यू में 100 अरब 5 करोड़ 24 लाख रूपये और कैपिटल में 48 अरब 42 करोड़ 16 लाख रूपये कुल राशि 1 4 8 अरब 47 करोड़ 40 लाख रूपये है सदन के सामने हैं :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोधा में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 11 पास हुई।

डिमांड नंबर 12 जिसमें कैपिटल में 1 करोडद्य 50 लाख रूपये है सदन के सामन है :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोधा में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 12 पास हुई।

डिमांड नंबर 13 जिसमें रेवेन्यू में 1 अरब 25 करोड़ रूपये हैं सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोधा में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

डिमांड नंबर 13 पास हुई।

हाउस ने रेवेन्यू में 350 अरब 69 करोड़ 24 लाख 60 हजार रूपये और कैपिटल में 78 अरब 90 करोड़ 53 लाख 50 हजार रूपये, कुल राशि

429 अरब 59 करोड़ 78 लाख 10 हजार रूपये की डिमांड को मंजूरी दे दी है।

विनियोग विधोयक वित्त (सं. 2) 2017

अब माननीय उप-मुख्यमंत्री Appropriation (N0.2) Bill, 2017 (Bill No. 02 of 2017) को हाउस में introduce करेंगे।

Deputy Cheif Minister : Hon'ble Speaker Sir, I seek permission of the House to introudce Appropriation (No.2) Bill, 2017 to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolodated fund of the NCT of Delhi for the financial year 2017-18.

अध्यक्ष महोदय : उप-मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोधा में हैं, वे ना कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

अब माननीय उप-मुख्यमंत्री Bill को हाउस में introduce करेंगें।

Deputy Chief Minister : Hon'ble Speaker, Sir, I introduce Appropiration (No.2) Bill, 2017 to the House.

अध्यक्ष महोदय : अब बिल पर clause-wise विचार होगा।

प्रश्न है कि खंड-2, खंड-3 व Schedule बिल का अंग बनें।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोधा में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

खंड-2, खंड-3 एवं Schedule बिल का अंग बन गये।

प्रश्न है कि खंड-1, Preamble और Title Bill का अंग बनें,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोधा में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

खंड-1, Preamble और Title Bill का अंग बन गये।

अब माननीय उप-मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि Appropriation (No. 2) Bill, 2017 को पास किया जाए।

Deputy Chief Minister : Hon'ble Speaker Sir, the House may now please pass the Appropriation (No. 2) Bill, 2017.

अध्यक्ष महोदय : उप-मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोधा में हैं, वे न कहें,

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता,

Appropriation (No. 2) Bill, 2017 पास हुआ।

2017-18 के लिए वार्षिक बजट पास हुआ।

माननीय सदस्यगण, आपको विदित होगा कि गत वर्ष दिल्ली विधानसभा व्याख्यान श्रृंखला प्रारंभ की गई थी और मैगसेसे पुरस्कार विजेता श्री पी. साईनाथ ने भारत में पानी और सूखे की स्थिति पर व्याख्यान दिया था।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे चरण के अंतर्गत, दिनांक 2 3 मार्च, 2017 को शहीदी दिवस है, प्रातः 11.30 बजे प्रसिद्ध बैरिस्टर, इतिहासकार तथा लेखक श्री ए. जी. नूरानी को आमंत्रित किया गया है। वे शहीद भगत सिंह, राज गुरू तथा सुख देव की शहादत के संबंधा में अपना व्याख्यान देंगे। उससे पहले प्रातः 10.30 बजे शहीदी दिवस के अवसर पर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी जायेगी। आप सभी विधायकों से अनुरोधा है कि वीरवार दिनांक 23 मार्च, 2017 को निर्धारित समय पर अर्थात् प्रातः 10.30 बजे विधानसभा सचिवालय पहुंचें। मैं फिर दोबारा प्रार्थना कर रहा हूं। थोड़ा सा लेट आने की हमारी आदत बन गई है। इसको ठीक 10.30 बजे शहीदी दिवस है। तीनों शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, समय पर आने का कष्ट करें।

माननीय सदस्यगण, होली आने वाली है। मैं इस अवसर पर आप सबको होली पर्व की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह खुशी, रंग तथा प्रेम का उत्सव होता है। यह त्यौहार मन को सभी पकार के तनाव तथा राग-द्वेष मुक्त करके आनंद मनाने का भरपूर अवसर देता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि :

रंगों का खेल,
दिलों का मेल,
मस्ती के गीत,
जीवन का संगीत,
मन में हो प्रीत,
न हार, न जीत,
आओ खेलें होली,
बोलकर मीठी बोली।

एक बार फिर आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित करूं, स्वस्थ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय सभी मंत्रीगण, श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय नेात प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा विधानसभा सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ दिली सरकार के मुख्य सचिव व उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सीआरपीएफ बटालियन-55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलैक्ट्रिकल व हार्टिकल्चर

डिवीजन, अग्निशमन विभाग आदि द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिये भी मैं उनका हार्दिक धान्यवाद करता हूं।

विधानसभा की कार्यवाही को मीडिया के माधयम से जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी मैं हार्दिक धान्यवाद करता हूं।

अंत मैं माननीय उप-राज्यपाल महोदय ने आकर हम सबका मार्गदर्शन किया, मैं आप सबकी ओर से पूरे सदन की ओर से उनका बहुत-बहुत हार्दिक ध न्यवाद करता हूं। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोधा करता हूं कि वे राष्ट्रगान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हों।

(राष्ट्र गान : जन-गण-मन)

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

विषय सूची

सत्र-5 भाग (1) शुक्रवार, 10 मार्च, 2017/19 फाल्गुन, 1938 (शक) अंक-48

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	
2	विशेष उल्लेख (नियम-280)	
3	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	
4	वार्षिक बजट (2017-18)	
5	अनुदानों मांगों पर विचार एवं पारण (वित्त वर्ष 2017-18)	
6	विनियोग विधेयक (सं.2) का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	